प्रभात

अंदर के पन्नों में...

★ चुनावों का विश्लेषण 7
★ छत्तीसगढ़ बजट–2014–15 13
★ सैद्धांतिक लेख –कॉ.माओ 17
★ आह्वान ...शहीदी सप्ताह मनायेंगे 20
★ श्रद्धांजलि ...अमर शहीदों को 23
★ प्रेस विज्ञप्ति 35
★ पर्चा ...8 मार्च 47
★ पुलिस हिरासत में मृत्यु 49

Hkkjr dh dE;fuLV ikVh (ekvkoknh) dh n.Mdkj.; Li'ky tkuy deVh dk frekgh eq[k&i=k

o"k&26 vad&1 & 2 tuojh&tu 2014 lg;kx jkf'k&15 #i,

भा.क.पा. (माओवादी) और भा.क.पा (मा–ले) नक्सलबाड़ी का विलय जिंदाबाद! भारतवर्ष में एक ही पार्टी के रूप में दो माओवादी पार्टियों के विलय को ऊंचा उठायेंगे।

1 मई, 2014

दुनिया के सर्वहारा वर्ग के महान गौरवशाली अन्तर्राष्ट्रीय दिवस–मई दिवस के मौके पर हम भारत के माओवादी एक महान उत्तरदायित्व की चेतना के साथ भाकपा (माओवादी) और भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी के एक ही पार्टी भाकपा माओवादी के रूप में विलय की घोषणा करते हैं। इससे भारत के सर्वहारा वर्ग का हिरावल दस्ता जो कि विश्व सर्वहारा वर्ग की एक टुकड़ी है, मजबूत हुई है। भारत की क्रांति और विश्व सर्वहारा क्रांति के लक्ष्य को सफल बनाने के प्रति हम स्वयं को दृढ़तापूर्वक समर्पित करते हैं। 1967 के महान नक्सलबाड़ी के किसान सशस्त्र संघर्ष के उभार के साथ भारत में माओवादी आन्दोलन का उदय हुआ। हमारी पार्टी के संस्थापक नेता कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी से प्रेरणा लेकर और उनके नेतृत्व में क्रांतिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए तथा एक मजबूत पार्टी के निर्माण के लिए हजारों नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा जनता ने अपने अनमोल प्राणों को न्योछावर कर दिया। ➔

भारत की क्रांति के महान नेता कॉ. सुशील राय हमेशा एक लाल सूरज की तरह हमारी राह को रोशन करते रहेंगे।

भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य और भारत की क्रांति के गरिमाशाली नेता कॉमरेड सुशील राय (अशोक, शोम, बरुण दा) की 18 जून, 2014 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में लम्बी बीमारी के बाद मृत्यु हो गयी। इसके साथ ही हमारे देश की सर्वहारा और मेहनतकश जनता ने अपने महानतम बेटों में से एक को खो दिया जिसने सिर्फ जनता और क्रांति के हितों को दिलों–जहन में रखकर अपनी आखिरी सांस तक पांच दशकों से भी ज्यादा समय उनकी सेवा की।

'प्रभात' अपने समस्त पाठकों की ओर से कॉमरेड सुशील राय को सिर झुकाकर विनम्र लाल श्रद्धांजलि पेश करता है। उनके शोक–सन्तप्त परिजनों, मित्रों और भारत की क्रांति के शुभचिंतकों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करते हैं।

76 साल पहले कॉमरेड सुशील राय का जन्म आज के बंगलादेश में हुआ था। वह महान क्रांतिकारी शहीद दिनेश गुप्ता के भतीजे थे, जिनका देश और देशवासियों के लिए प्रेम, कुरबानी और प्रेरणा उन्होंने अंत तक अपने दिल में रखा। 1960 के दशक की शुरुआत में वह कम्युनिस्ट आन्दोलन में सक्रिय हो गये। उन्होंने मजदूर आन्दोलन में

(शेष पेज 4 में...)

← 1970 के दशक के धक्के और कामरेड चारू मजुमदार की शहादत के बाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शक्तियां अनेक गुटो में विभाजित हुई थी। असली क्रांतिकारियों ने अलग–अलग इलाकों में आन्दोलन के निर्माण के लिए प्रयास करते हुए सभी क्रांतिकारियों को एक पार्टी में एकताबद्ध करने की गंभीर कोशिशें की थी। पिछले चार दशकों की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अलग–अलग रह रही दो प्रधान धाराएं जो पूर्ववर्ती भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) और एमसीसीआई का प्रतिनिधित्व करती थी, 21 सिंतम्बर 2004 को एक ही पार्टी भाकपा (माओवादी) के रूप में विलय हो गई थी। यह विलय भारतवर्ष के मजदूर, किसान और अन्य पीड़ित जनता की बहुप्रतीक्षित अकांक्षाओं को कायान्वित करने के एक गुणात्मक छलांग को चिन्हित करता है और देश में नवजनवादी क्रांतिकारी युद्ध की जीत के लिए और समाजवाद, बाद में साम्यवाद की स्थापना की ओर आगे बढ़ने के लिए एक ही मार्ग निर्देशक केंद्र बनाना चाहता था। उसी तरह भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी ने भी विघटनकारी के. वेनू के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सीआरसी, भाकपा (मा–ले) और अवसरवादी के.एन. रामचंद्रन के नेतृत्व वाली रेड् फ्लैग के संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए उनमें मौजूद सभी असली माओवादी शक्तियों को एकताबद्ध करने के गंभीर प्रयास किये थे। दोनों पार्टियों की इन प्रक्रियाओं के अंतिम नतीजे के रूप में भाकपा (माओवादी) और भाकपा (मा–ले) नक्सलबाडी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) मजबूत हुई है। निःसंदेह इस एकीकरण ने साबित किया है कि एक तरफ शासक वर्गों और साम्राज्यवाद के खिलाफ दीर्घकालीन लोकयुद्ध में पीड़ित जनता को एकजुट करते हुए, दूसरी तरफ मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के सिद्धान्त तथा पार्टी की क्रांतिकारी लाइन पर अटल रहते हुए, संशोधनवादियों तथा विघटनकारियों के खिलाफ दृढ़तापूर्वक संघर्ष करते हुए सभी असली माओवादी शक्तियों को एक ही पार्टी में एकताबद्ध कर सकते हैं, चाहे यह प्रक्रिया जितनी भी लंबी क्यों न हो। हमारी पार्टी विभिन्न मार्क्सवादी–लेनिनवादी गुटों में काम करने वाली सभी असली क्रांतिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करने के कार्यभार को जारी रखती है।

एकीकृत पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद को अपने मार्ग निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपनाती है। उसे ऊंचा उठाने, उसकी रक्षा करने तथा सृजनात्मक ढंग से कार्यन्वित करने के द्वारा उस पर अपनी समझदारी को गहराती है। हमारे क्रांतिकारी व्यवहार की हमेशा समीक्षा करते हुए तथा दुनिया भर के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी दस्तों के और संघर्षरत जनता के अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी लाइन व व्यवहार को विकसित करती है। यह पार्टी सामंतवाद विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी नवजनवादी क्रांति के कार्यभारों को अपने कंधों पर लेती है। यह क्रांति, सांस्कृतिक क्रांतियों के जरिए क्रांति को जारी रखने के द्वारा समाजवाद, बाद में साम्यवाद की तरफ अग्रसर होती है। नव जनवादी क्रांति के लक्ष्य हैं– सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद जिसका मुख्य सारांश है, सशस्त्र कृषि क्रांति। दीर्घकालीन लोकयुद्ध ही क्रांति का रास्ता है। सामंतवाद तथा व्यापक पीड़ित जनता के बीच का अन्तरविरोध प्रधान अन्तरविरोध है। पार्टी का मानना है कि साम्राज्यवाद तथा उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं एवं जनता के बीच जो अन्तरविरोध है वह दुनिया के स्तर पर प्रधान अन्तरविरोध है। यह दुनिया के अन्य मौलिक अन्तरविरोधों के साथ–साथ तीखा होता जा रहा है।

अभी हासिल हुई एकता भाकपा (माओवादी) की क्षमता को बढ़ावा देती है। इससे भारत की क्रांति के हिरावल दस्ते के रूप में अपनी भूमिका को वह बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकती है। कई दशकों के कठिन संघर्ष, हजारों महान कम्युनिस्ट नेताओं, लाल योद्धाओं तथा पीड़ित जनता के बलिदानों के द्वारा ही भाकपा (माओवादी) ने भारत देश में जनयुद्ध को इस स्तर तक विकसित किया कि मध्य और पूर्व भारत में गुरिल्ला आधार क्षेत्र और क्रांतिकारी जन कमेटियों के रूप में लाल राजनीतिक सत्ता स्थापित किया गया है। इसकी सुरक्षा जन मुक्ति छापामार सेना तथा जन मिलिशिया कर रही है। अत्यंत अमानवीय दमन अभियानों, जो अभी जनता पर युद्ध, ऑपरेशन ग्रीनहंट के रूप में केंद्रीकृत हुई है, के खिलाफ संघर्ष करने के द्वारा ही यह हासिल हुआ है। ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत दसियों हजार जनता पर क्रूरतापूर्वक हमले किये जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, घरों को जलाना तथा फसलों को बर्बाद करना, जबरन विस्थापित करना और कई अन्य आमनवीय हथकंडे साधारण हो गई हैं। अभी भारतीय राज्य अपनी थल सेना और वायुसेना के साथ सक्रिय रूप से वैमानिक और जमीनी हमले करने का पूर्वाभ्यास कर रही है। इस तरह के कत्लेआम के बावजूद दीर्घकालीन लोकयुद्ध का लहरों की तरह आगे बढ़ना जारी है। हाल ही में भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट से लगी पश्चिमी घाटी के दक्षिणी भाग में विस्तार इसका एक सबूत है। दक्षिण एशिया में साम्राज्यवाद का स्तम्भ– भारतीय राज्यसत्ता के ध्वस्त होने तक क्रांति की लपटें विस्तार होती जायेंगी।

चूंकि साम्राज्यवादी और उनके दलाल शासक दुनिया भर में बेरोकटोक संकट में फंसे हुए हैं। इससे दुनिया भर में अनुकूल क्रांतिकारी परिस्थिति बन रही है। यह दुनिया भर में वर्ग संघर्षों को तेज करेगी, माओवादियों के नेतृत्व में जनयुद्धों की तरफ, पीड़ित देशों में अन्य शक्तियों के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों की तरफ ले जायेगी। देश

के मध्य और पूर्वी भाग में शासक वर्गों ने अपने चार लाख भाड़े के बलों को तैनात किया है जहां वर्ग संघर्ष तीव्र क्रांतिकारी अन्तर युद्ध के चरण में पहुंच गया है। यह एक क्रांतिकारी विकल्प के रूप में उभर रहा है और व्यापक पीड़ित जनता को क्रांति की तरफ प्रेरित कर रहा है। इतना ही नहीं जनमुक्ति छापामार सेना मजबूती से संगठित हो रही है और नवजनवादी राजसत्ता अपने भ्रूण रूप में उभर रहा है। पश्चिम घाटी में अंकुरित होने वाले क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष को कुचलने के लिए भारतीय राज्य के द्वारा वहां सैनिकीकरण तेज हो रहा है। दूसरी तरफ वह मजदूरों, किसानों आदिवासी दलितों महिलाओं तथा अन्य पीड़ित जनता पर जनविरोधी वैश्वीकरण नीतियों को जबर्दस्ती थोप रहा है। इस वजह से समरशील आन्दोलनों में तेजी आ रही है। इस अनुकूल परिस्थिति का इस्तेमाल करते हुए पार्टी क्रांतिकारी आन्दोलन को एक उच्चस्तर तक आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास करेगी और अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यभारों को बेहतर तरीके से पूरा करेगी। वह लाखों की संख्या में जनता को एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। गुरिल्ला युद्ध को तेज व विस्तृत करेगी। क्रांतिकारी आन्दोलन के सामने जो कठिन चुनौतियां मौजूद हैं उनका समाधान करेगी और अवरुद्धों को पार करेगी।

हम इस बात से चिंतित हैं कि भारत और दुनिया भर में अमानवीय विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था की वजह से व्यापक जनता दूभर तथा अभाव की स्थिति में जीने को विवश है। हम वाकिफ हैं कि इस व्यवस्था की वजह से विश्व पर्यावरण पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है उससे धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है।

साम्यवाद के लक्ष्य के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले हजारों शहीदों की यादों को समेटकर उनके खून से सने सुर्ख लाल झण्डे के तले एकजुट होकर शपथ लेते हैं कि जो एकता हमने हासिल की है उसे क्रांति के एक शक्तिशाली हथियार बनायेंगे।

गणपति,
महासचिव,
भाकपा (माओवादी)

अजित,
महासचिव,
भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा राज्य के विशेष जन सुरक्षा कानून वैध घोषित

शोषक–शासक वर्गों के राज्ययंत्र का हिस्सा है, न्याय व्यवस्था

बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के विशेष जनसुरक्षा कानून को वैध ठहराते हुए इस अधिनियम के खिलाफ दायर की गई पीयूसीएल की याचिका हाल ही में खारिज कर दी। चीफ जस्टिस यतींद्र सिंह, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिविजन बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। पीयूसीएल के सदस्य राजेंद्र सायल ने वर्ष 2005 में बनाए गए छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा कानून को चुनौती देते हुए 17, जुलाई 2008 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अधिनियम में किए गए प्रावधानों को मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूची–1 में तय किए गए विषयों के अंतर्गत केंद्र को, अनुसूची–2 के तहत राज्य को और अनुसूची–3 में राज्य और केंद्र दोनों को नियम–कानून बनाने का अधिकार है। जनसुरक्षा कानून के तहत किए गए प्रावधान सूची–1 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज्य शासन इस संबंध में कानून नहीं बना सकता।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुधा भारद्वाज ने कानून को जनविरोधी बताते हुए कहा कि इसके अनुसार शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। विनायक सेन, पत्रकार अजय टीजी, वकील सत्येंद्र चौबे इसके उदाहरण है। इस कानून के अंतर्गत प्रदेश के छह संगठनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सब गलत है।

इस कानून के अमल में आने के बाद से अब तक सैकड़ों लोगों को इसके तहत फर्जी मामलों में फंसाया गया है। शोषक–शासक वर्गों की कोर्ट–कचहरी से नहीं बल्कि मजबूत जन संघर्ष के जरिए ही ऐसे जन विरेधी कानूनों को खत्म कर सकते हैं।

★

(...पहली पेज से)

काम किया और 1963 में भाकपा में शामिल हुए। वियतनाम के खिलाफ छेड़े गये अन्यायपूर्ण युद्ध के विरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादी विरोधी प्रदर्शनों और 1966 के दक्षिण कोलकाता के खाद्य आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभायी। भाकपा में मौजूद संशोधनवादियों के खिलाफ अन्दरूनी संघर्ष में वह शामिल थे। उनके कई समकालीन क्रांतिकारियों की तरह उनकी भी अपेक्षा थी कि संशोधनवादी भाकपा से अलग होकर गठित माकपा एक क्रांतिकारी पार्टी में तब्दील होगी और इसी आशा के साथ वह 1964 में इस नई पार्टी में शामिल हुए।

उनका सम्पर्क कामरेड्स कन्हाई चटर्जी और अमूल्य सेन से हुआ जो चीनी क्रांति की तर्ज पर एक क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण के लिए और एक नई जनवादी क्रांति की अग्रगति के लिए अथक वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक तैयारियों में जुटे हुए थे। संशोधनवाद के खिलाफ बसंत के बज्रनाद बनकर जन दुश्मनों पर कहर ढ़ानेवाली नक्सलबाड़ी की ललकार को उन्होंने 'नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता' के नारे के साथ समर्थन और अभिवादन किया। 'चिंता' तथा 'दक्षिण देश' गुटों के वह शुरुआत से ही हिस्सा थे और माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र (एमसीसी) के एक संस्थापक सदस्य थे। पेशेवर क्रांतिकारी के रूप में एक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए वह पश्चिम बंगाल के अन्दरूनी गांवो में चले गये।

दीर्घकालीन जनयुद्ध की लाइन को सृजनात्मक तरीके से व्यवहार में अमल करने के क्रम में पश्चिम बंगाल के सोनारपुर और कांक्सा इलाकों में एमसीसी को आन्दोलन के निर्माण का पहला अनुभव हासिल हुआ। पार्टी ने इन संघर्षों में आई सामयिक गतिरोध के कारण बनी कमियों के बारे में गहराई से समीक्षा की। सच्चे कम्युनिस्ट उत्साह के साथ गया–हजारीबाग (उस समय यह एरिया बिहार के अन्तर्गत था) में आन्दोलन को आगे बढ़ाने की गम्भीर कोशिश की गई, जहां कॉमरेड केसी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में पिछली गलतियों से सीखकर एक रणनीतिक योजना के साथ जनसेना और आधार इलाका निर्माण करने के लिए काम शुरू किया गया। जल्द ही सशस्त्र कृषि क्रांति की आग चारों ओर फैल गयी और इसके साथ राज्य दमन गम्भीर रूप से बढ़ गया। कुछ अहम नुकसानों के बावजूद आन्दोलन ने कॉमरेड सुशील राय सहित पार्टी के नेतृत्वकारी साथियों के सकुशल दिशा निर्देशन की वजह से दुश्मन के हमलों का सफल मुकाबला किया। उन्होंने एक मजबूत सर्वहारा पार्टी, एक जनसेना और एक क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे की नींव रखी और सशस्त्र कृषि क्रांति की राह पर महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की।

18 जुलाई, 1982 को गम्भीर बीमारी की वजह से कॉमरेड केसी की अकाल मृत्यु के बाद उसी साल कॉमरेड सुशील राय ने एमसीसी के सचिव की जिम्मेदारी ली। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर दृढ़ता से पार्टी लाइन को थामते हुए उन्होंने पार्टी को एकताबद्ध तरीके से गोलबंद व विकसित करने तथा आन्दोलन के निर्माण के लिए प्रयास किये। 1989 में आयोजित पार्टी के पहले केन्द्रीय अधिवेशन में उन्हें सचिव चुन लिया गया। पार्टी, सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी युद्ध और जनाधार के निर्माण में, खासकर बिहार–झारखण्ड और बंगाल में वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, सैनिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में कॉमरेड सुशील राय का योगदान अनमोल साबित हुआ। उन्होंने अपनी निष्ठा, सर्वहारा रणनीतिक नेतृत्व की कुशलता, मार्गदर्शन, कर्मठता और निस्वार्थ सेवा से अपनी कमेटी, निचले स्तर की कमेटियों, तथा पूरी पार्टी कतारों का विश्वास जीत लिया। गम्भीर दृष्टिहीनता और बीमारी की वजह से उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी सचिव के पदभार से मुक्त होने का प्रस्ताव पार्टी के सामने रखा। 1996 में संपन्न पार्टी के दूसरे केन्द्रीय अधिवेशन में पार्टी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उस समय से वह एक केन्द्रीय कमेटी सदस्य की हैसियत से अपनी भूमिका निभाते रहे। केन्द्रीय कमेटी और पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, खासकर वैचारिक और राजनीतिक क्षेत्र में, पार्टी के अन्दर सफलतापूर्वक दो–लाइन संघर्ष चलाने में, आन्दोलन का मुल्यांकन करने में, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित करने और सच्चे माओवादी संगठनों के साथ, खासकर भाकपा (मा–ले) {पीपुल्सवार} के साथ एकता हासिल करने में जारी रही।

पार्टी के कई अन्दरूनी संघर्षों का सफलतापूर्वक संचालन करने में और पार्टी की सही लाइन की रक्षा करने में एक नेतृत्वकारी सदस्य तथा बाद में पार्टी के सचिव व वरिष्ठ केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में कॉमरेड सुशील राय की विशिष्टि भूमिका थी। इन अन्दरूनी संघर्षों में 1999 और 2001 के बीच केन्द्रीय कमेटी के अत्यन्त अवसरवादी व विघटनकारी भरत–बादल गुट के खिलाफ चलाया गया दो लाइन संघर्ष सबसे तीखा था। अवसरवादियों की विघटनकारी गतिविधियों की वजह से आन्दोलन ने कुछ सामयिक नुकसान उठाया। उसके बावजूद उन्होंने और अन्य नेतृत्वकारी साथियों ने इन अन्दरूनी संघर्षों में पार्टी के अंदर 'वाम' और दक्षिणपंथी अवसरवादी रुझानों का सफल मुकाबला किया और फिर से पार्टी को सही पथ पर संचालित किया।

देश के सच्चे क्रांतिकारियों के साथ एकता स्थापित करने में कॉमरेड सुशील राय की भूमिका भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास में विशेष रूप से दर्ज रहेगी।

कॉमरेड केसी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में 1981 में ही पीपुल्सवार के साथ एकता का प्रयास शुरू हुआ था जिसने एकता की एक मजबूत आधारशिला रखी थी। अन्य कारणों के अलवा, एमसीसी की पहलकदमी से सन 2000 में ऐलान किये गये एक तरफा युद्ध विराम जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था, के बाद एमसीसी और पीपुल्सवार के बीच एकता के प्रयासों ने अंततः रंग लाना शुरू किया। इस निर्णय में और इस महान एकता को वास्तविक रूप देने की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने एमसीसी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल के एक नेतृत्वकारी सदस्य की हैसियत से हिस्सा लिया। इस विलय के कुछ ही समय पहले आरसीसीआई, आरसीसीआई (एम) और सेकंड सीसी के साथ एकता में भी उन्होंने इसी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमसीसीआई ने भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी के साथ एकता वार्ता की और एकता स्थापित करने के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह आम सहमति पर पहुंची। दोनों पार्टियों के बीच करीबी सम्बन्ध थे। इन वार्ताओं में भी कॉमरेड सुशील राय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाकपा (माओवादी) और भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी के बीच हाल ही में 2014 में हुए विलय की भी इसने नींव रखी।

विलय के बाद, पार्टी के एक वरिष्ठ कॉमरेड और पोलित ब्यूरो सदस्य होने के नाते वह पार्टी के निचले स्तरों में विलय की प्रक्रिया को संपूर्ण करने और एक एकीकृत पार्टी के रूप में काम करने की नई परिस्थिति में पूरी पार्टी को ढ़ालने के प्रयासों में व्यस्त थे। एकता कांग्रेस की तैयारियों में वह शामिल थे और जनयुद्ध को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए किये गये केन्द्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के सभी निर्णयों का वह हिस्सा थे तथा कुछ अंतरराष्ट्रीय काम भी देख रहे थे।

विलय के बाद भारत की क्रांति के एकमात्र मार्गदर्शन केन्द्र के तहत पार्टी, पीएलजीए और जनाधार में गुणात्मक बदलाव आया और जनयुद्ध आगे बढ़ा। इसीलिए, भारत के प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों ने उनके साम्राज्यवादी आकाओं के दिशा–निर्देश पर नवगठित भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व को गिरफ्तार या हत्या करने की सुनियोजित षड़यंत्र रची। इस क्रम में कॉमरेड सुशील राय को 21 मई, 2005 को गिरफ्तार किया गया। कई फर्जी मामलें थोपने के बाद उन्हें पूछताछ किया गया, मानसिक रूप से यातनायें दी गयी और जेल में डाला गया। पश्चिम बंगाल और झारखण्ड की जेलों में उन्हें अमानवीय और निर्मम बरताव से गुजरना पड़ा। दरअसल, उनके कारावास की पूरी अवधि में उन्हें एक से अधिक बार जमानत दी गयी थी। लेकिन झूठे अभियोगों के आधार पर उन्हें जेल गेट से ही उठाकर फिर से जेल में ठूंस दिया जाता था। नेतृत्वकारी साथियों को, खासकर केन्द्रीय कमेटी सदस्यों को क्रांति का नेतृत्व और सेवा करने से रोकने के लिए राज्य इस साजिश पर अमल कर रहा है। उनकी बढ़ती उम्र और गम्भीर बीमार हालत की पूरी तरह उपेक्षा कर उन्हें बिना किसी सहायता के (अपनी दिनचर्या के कामों के लिए भी जिसका उन्हें बहुत जरूरत थी) बंद कोठरी में अलग रखा गया था। इससे उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया। जेल में ही कुल्हे की हड्डी टूटने से उन्हें गम्भीर चोट भी आयी। कई साल इस हालत में जेल में गुजारने के बाद सितंबर, 2012 में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था, वह भी कई जनवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शनों व प्रयासों के बाद।

कॉमरेड सुशील राय मूत्राशय की केन्सर से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने पहले उनके मूत्राशय से एक टयूमर को ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया था और केन्सर के लिए एक अन्य ऑपरेशन भी किया था। वह हृदयारोग के मरीज थे। उनकी एक किडनी (गुर्दा) पूरी तरह खराब हो गयी थी जबकि दूसरी संक्रमित थी। फिर भी एक योद्धा की तरह अंतिम सांस तक उन्होंने इन बीमारियों से संघर्ष किया। इसी क्रांतिकारी उमंग की वजह से ही वह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का सामना कर कुछ समय के लिए मृत्यु को टाल सके। इस तरह की अत्यंत दुखदायी शारीरिक पीड़ा और विकलांगता सहन करते हुए उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी हिम्मत और दृढ़ता नहीं खोयी।

कॉमरेड सुशील राय की दुखद मृत्यु बेशक एक भारी क्षति है और पार्टी व आन्दोलन के लिए एक बहुत ही दुखदायी घटना है। लेकिन पूरी पार्टी तथा क्रांतिकारी जनता इस महान शहीद से सीखेगी और क्रांति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुगुने दृढ़संकल्प के साथ काम करेगी। कॉमरेड सुशील राय पार्टी कतारों के चहेते, प्रशंसनीय नेता और आदर्श कम्युनिस्ट थे। वह हमेशा क्रांतिकारियों के दिलों में बसे रहेंगे और प्रेरणा का स्रोत होंगे। हमारे महान शहीदों के अरमानों को पूरा करने के लिए आगे आनेवाले कम्युनिस्टों की पीढ़ियों के लिए उन्होंने कई उच्च आदर्श प्रतिष्ठित किये। कॉमरेड सुशील राय की पूरी जिन्दगी भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के उतार–चढ़ावों, ज्वार–भाटों, सफलताओं और गरिमाओं के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी रही है। उन्होंने समूह में अपने आपको इतने गुमनाम रखकर और सच्ची कम्युनिस्ट भावना से समाहित किया कि उनके जीवन और काम हमारे देश के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के इतिहास को ही बयान करेंगे।

हर एक कम्युनिस्ट को महान नेता कॉमरेड सुशील राय से इन विषयों को सीखना चाहिए – मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद का दृढ़ अनुसरण और उसका सृजनात्मक प्रयोग, एक तरफ अवसरवाद व

विघटनवाद का विरोध और दूसरी तरफ एकता के प्रयास तथा उस एकता को बरकरार रखने की कोशिश, गलतियों को स्वीकार करने और दूसरों की गलतियों को सुधारने में ईमानदारी, तीन जादुई हथियारों का निर्माण कर आन्दोलन को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में हरसंभव प्रयास करना, और व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के मातहत रखना।

कॉमरेड सुशील राय सरलता के प्रतीक थे और एक बहुत ही मितव्ययी जीवन जीते थे। जीवनभर वह अविवाहित रहे। नक्सलबाड़ी, सोनारपूर और कांक्सा आन्दोलनों पर क्रूर राज्य दमन के समय और उसके बाद आन्दोलन के उतार–चढ़ावों के दौरान वह दृढ़ता से खड़े रहे। वह कभी भी नहीं डगमगाये और हमेशा पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी या कार्यभार दी उसे पूरा करने में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। अन्य पार्टियों व आन्दोलनों के प्रति वह हमेशा सकारात्मक रवैया रखते थे और उनके प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने और अध्ययन करने की कोशिश करते थे। उनका अध्ययन गहरा था। वह बहुत ही धैर्य के साथ कामरेडों से सम्बन्ध रखते थे। एक क्रांतिकारी जीवन में आनेवाली हर तरह की मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और इन सभी का एक सच्चे क्रांतिकारी की गरिमा के साथ मुकाबला किया।

यह एक कम्युनिस्ट का कृतसंकल्प ही है जिसकी वजह से वह मानव की पीड़ा के खात्मे के लिए कोई भी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहता है। जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये, कभी भी उनके हंसमुख मिजाज को नहीं भूल सकते। और कठिनतम परिस्थितियों में भी वह कॉमरेडों में क्रांतिकारी जोश भर देते थे। यह उनके व्यक्तित्व का एक सकारात्मक पहलू ही नहीं, बल्कि एक महान लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट वचनबद्धता ने ही उसे मुमकिन बनाया, और वह महान लक्ष्य था – सभी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव से दुनिया की जनता की मुक्ति।

इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कॉमरेड सुशील राय को इतनी पीड़ा भुगतना नहीं पड़ता और उनकी इतनी जल्द मौत नहीं होती अगर भारतीय राज्य का उनकी तरफ इतना लापरवाह बरताव नहीं होता। तमाम जनवादी ताकतों एवं मानवाधिकार संगठनों को शासक वर्गों, उनके राज्य यंत्र और साम्राज्यवादियों की इस बर्बर अमानवीय कोवर्ट हत्या की तीव्र निंदा करनी चाहिए और इस क्रूरता का पर्दाफाश करना चाहिए। इस तथ्य को जनता के बीच व्यापकता से प्रचार करना चाहिए ताकि जेलों में बन्द नेतृत्वकारी साथियों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर उन्हें सचेत कर सकें और उनके व अन्य बन्दियों पर ढ़ाये जा रहे अनगिनत अन्यायों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें जागृत कर सकें। कॉमरेड सुशील राय जिन्होंने इतने भयंकर परिस्थितियों में भी राज्य के खिलाफ अपने अथक संघर्ष से एक मिसाल कायम की, जेल बंदी कॉमरेडों व जनता को इस लड़ाई में भी प्रेरित करते रहेंगे।

कॉमरेड सुशील राय के एम्स में दाखिले और ऑपरेशन के बाद वह चलने–फिरने में भी समर्थ नहीं थे और उन्हें हर समय सहायता की जरूरत थी। क्रांतिकारी और जनवादी जनसंगठनों तथा व्यक्तियों व लोगों ने इस जरूरत को पूरा किया। भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में समस्त क्रांतिकारी शिविर की ओर से तहे–दिल से अपनी क्रांतिकारी कृतज्ञता और लाल सलाम उन सभी को पेश किया है जिन्होंने उनकी रिहाई और उपयुक्त इलाज के लिए जी–जान से कोशिश की और अंतिम समय तक उन्हें बेहद जरूरी व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करायी। कॉमरेड सुशील राय की सेवा में उन्होंने जो सच्चे मानवीय मूल्यों का परिचय दिया उसे पार्टी और क्रांतिकारी जनता हमेशा याद रखेंगी। भारत की क्रांति के इस अनमोल नेता के प्रति भारतीय राज्य के अमानवीय व्यवहार की तुलना में यह और भी उज्वलता से झलकता है। उनके जैसे ज्येष्ठ और सच्चे जननेताओं की सेवा करना पूरे विश्व में सच्चे मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के व्यापक संघर्ष का एक अभिन्न हिस्सा है।

एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब क्रांतिकारी आन्दोलन के कई वरिष्ठ कॉमरेड बिना जमानत, उपयुक्त इलाज, साफ सफाई और सहूलियत के पांच से दस साल तक जेलों में कैद हैं और गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस तरह के और भी कार्यभार आनेवाले दिनों में सामने आना तय है। कॉमरेड सुशील राय के उचित इलाज के लिए की गयी लड़ाई सभी राजनीतिक बन्दियों की बिनाशर्त रिहाई और बन्दियों के अधिकारों के संघर्ष का एक हिस्सा है। सच्चे जननेताओं की रिहाई और उनका समुचित इलाज करवाना जनता का अधिकार और जिम्मेदारी है।

'प्रभात' अपने सभी पाठकों का अह्वान करता है कि वे कॉमरेड सुशील राय एवं अन्य महान शहीदों की जीवनियों से प्रेरणा लेकर, उनके क्रांतिकारी गुणों, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों व आदर्शों पर अमल करते हुए आखिरी सांस तक दृढ़ संकल्प के साथ उनके अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

कॉमरेड् सुशील राय अमर रहे!

★

भाजपा की मोदी जीत– कॉरपोरेट शोषण व फासीवादी दमन में बेतहाशा वृद्धि का संकेत। जनयुद्ध एवं जन आन्दोलनों के बेहतर तालमेल से हिन्दुत्व फासीवाद का मुकाबला करना होगा।

विगत 16 मई को 16वें लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा हुई। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 283 सीटों पर विजय हासिल की जबकि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 332 सीटें हासिल हुई। विगत चार दशकों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हिन्दुत्व राजनीति में प्रशिक्षित स्वयंसेवक एवं प्रचारक नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई, 2014 को देश के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इन चुनावों में विगत 10 सालों से सत्ता पर काबिज कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की करारी हार हुई। कांग्रेस को महज 44 सीटों पर विजय मिली। हालांकि इन चुनावों से उत्पीड़ित व शोषित जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन चुनावी नतीजें जनता की जीवन परिस्थितियों को बुरी तरह प्रभावित करने वाले हैं। देश की जनता के भविष्य के लिए ये नतीजे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाले हैं।

कुल 81.4 करोड़ मतदाताओं में से 16वीं लोकसभा के चुनावों में चुनाव आयोग के द्वारा एड़ी–चोटी एक करने के बावजूद मतदान प्रतिशत 66.38 से आगे नहीं बढ़ पाया। रिग्गिंग, बूथ कैप्चूरिंग, फर्जी मतदान को जोड़कर भी। इन चुनावों में एक तिहाई से भी कम, 31 प्रतिशत वोट हासिल करके भाजपा ने 283 सीटें प्राप्त की। कांग्रेस 19.3 प्रतिशत वोटों के साथ 44 सीटें प्राप्त की। मौजूदा चुनाव प्रणाली में हालांकि उसे सरकार बनाने का बहुमत हासिल हुआ है लेकिन देश की जनता का पूर्ण बहुमत उसे प्राप्त नहीं है। इस मायने में वह देश की तमाम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार नहीं है।

चुनावों का संचालन–युद्ध स्तर की तैयारियां

चुनाव आयोग का यह दावा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 16वीं लोकसभा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है, सत्य से परे है। 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक 9 चरणों में, दसियों लाख पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों की संगीनों के साये में, 70 लाख मतदान कर्मियों के जरिए चुनाव संपन्न कराये गये। इन चुनावों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गयी थीं। क्रांतिकारी संघर्ष के इलाकों में लाखों की संख्या में अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों को तैनात करके चुनाव के काफी पहले से ही दमन अभियान चलाये गये थे। भाकपा (माओवादी) के चुनाव बहिष्कार के आह्वान को विफल करने चुनावों के कुछ समय पूर्व तक अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन संचालित किये गये। गांवों पर हमलों, अवैध गिरफ्तारियों, अंधाधुंध पिटाई, मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों के जरिए संघर्षरत जनता को आतंकित किया गया था। देश के संघर्ष इलाकों में दो बड़े दमन अभियान संचालित किये गये। पहला, कश्मीर, उत्तर पूर्व के अलावा 14 राज्यों में व्याप्त माओवादी संघर्ष इलाकों में एक साथ 26 दिसंबर, 2013 से 1 जनवरी, 2014 तक 40 हजार अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों को तैनात करके एक सप्ताह का कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। दूसरा, 6 राज्यों जहां माओवादी संघर्ष सक्रिय रूप से जारी है, में एक लाख अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों, 6000 कमांडों बलों, दसियों हेलिकॉप्टरों, 4 इज्रायली एरोन ड्रोन, राडार युक्त माईन प्रूफ वाहनों के जरिए पुलिए महानिरीक्षक स्तर के 70 अधिकारियों के पर्यवेक्षण में 19 मार्च, 2014 से 27 मार्च, 2014 तक ऑपरेशन चलाया गया था। भाकपा (माओवादी) के अलावा कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस एवं उत्तर पूर्व में मणिपुर के कुछेक संगठनों के द्वारा दिये गये चुनाव बहिष्कार के आह्वान को विफल करने की कवायद के तहत ये ऑपरेशन चलाये गये थे।

चुनाव बहिष्कार एवं प्रतिरोध

चुनाव आयोग एवं सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद संघर्ष इलाकों की जनता ने चुनावों का बहिष्कार किया था। दण्डकारण्य, बिहार–झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र के संघर्ष इलाकों में 5 से 20 प्रतिशत मतदान ही हुआ। जबकि छापामार आधार इलाकों में जनता ने चुनावों का पूर्णतया बहिष्कार किया। न केवल संघर्ष इलाकों बल्कि देश के कई अन्य इलाकों में भी लोगों ने खुलकर चुनाव का बहिष्कार किया। दंडकारण्य के नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर व दंतेवाड़ा जिलों में बड़े बांधों, बड़ी खनन परियोजनाओं, वृहद उद्योगों के चलते होने वाले विस्थापन के विरोध में व विभिन्न मांगों को लेकर लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। उत्तर प्रदेश के बांदा–चित्रकुट इलाकों के कई गांवों ने किसानों की लंबित मांगों के पूरा न होने

के खिलाफ किसी को वोट न देने का बाकायदा पंचायत में प्रस्ताव पारित करके चुनाव बहिष्कार किया था। शोषक–शासक वर्गों के तमाम दमनात्मक हथकंडों के बावजूद कश्मीर घाटी में मतदान का प्रतिशत 27 तक सिमट कर रह गया था।

चुनावों के दौरान भाकपा (माओवादी) की जन मुक्ति छापामार सेना व जनता ने सरकारी सशस्त्र बलों के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान संचालित करके पुलिस, अर्ध–सैनिक व कमांडों बलों के दसियों जवानों को खत्म करके उनसे हथियार व गोली–बारूद को जब्त किया था। सशस्त्र बलों के द्वारा जोर–जबर्दस्ती के सहारे चुनाव संपन्न कराने एवं संघर्ष इलाकों की जनता को उनके चुनाव बहिष्कार के अधिकार से वंचित करने के प्रयासों को नाकाम करने एवं शोषक–शासक वर्गों की राजसत्ता के विकल्प के रूप में जनता के द्वारा चुनी गयी जन राजसत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनताना सरकारों की रक्षा करने के लिए ही ऐसा किया गया था।

नोटा का प्रयोग

इन आम चुनावों में पहली बार चालू किये गये नोटा बटन को एक करोड़ से भी ज्यादा वोटरों ने दबाया। सशस्त्र बलों के डर से या किसी अन्य दबाव में ऐसे सभी लोगों ने जो खुलकर चुनाव बहिष्कार नहीं कर सकें, नोटा को चुना। पूरी चुनाव प्रक्रिया में फिलहाल नोटा का कोई खास व्यावहारिक महत्व नहीं है। हालांकि चुनावों में रुचि न रखने वालों को भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ही नोटा को लाया गया है, फिर भी लोगों के द्वारा इसके प्रयोग को चुनाव बहिष्कार के तहत देखा जा सकता है।

चुनाव खर्च– जनता पर भारी बोझ

इस बार के चुनावों में आयोग के खर्च के साथ–साथ प्रत्याशियों के प्रचार खर्च में बेहिसाब वृद्धि हुई। चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा हाईटेक हो गया था। चुनाव लड़ने व संचालन की प्रक्रिया बेहद जटिल, खर्चीली व कठिन हो गयी। इस बार कुल तीस हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। चुनाव प्रचार में हेलिकॉप्टरों, जेट विमानों का भी खूब इस्तेमाल हुआ। मानव विकास सूचकांक में, 2012 में 177 देशों में 136 वें स्थान पर रहने वाला भारत अपने तथाकथित लोकतंत्र के चुनाव खर्च के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर रहा।

चुनाव सुधारों की धज्जियां उड़ी

आम लोगों में चुनावों के प्रति टूटते भ्रम को कायम करने एवं उदार जनवादी बुद्धिजीवियों की मांग व दबाव के चलते अपनाये गये चुनाव सुधारों –आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा, दल बदल (विरोधी) कानून, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को चुनाव लड़ने से रोकने संबंधी कानून आदि की इन चुनावों में धज्जियां उड़ते देखा गया।

इन चुनावों में सभी पार्टियों ने गुण्डों, हत्यारों, बलात्कारियों, घोटालेबाजों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, व दल बदलुओं को टिकटें दी। 2014 के चुनावों में दलबदलू राजनीति अपने चरम पर थी। वंशवाद के नये उत्तराधिकारियों का भी यही हाल रहा। 16वीं लोकसभा के लिए चुने गये सांसदों में 186 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रिंट व इलोक्ट्रानिक मीडिया में पेड न्यूज, रिपोर्ट्स, विशेष रिपोर्ट्स, साक्षात्कार प्रकाशित व प्रसारित किये गये। इन चुनावों में पैसे पानी की तरह बहाये गये। देशी व अंग्रेजी शराब की गंगा बही। युवाओं के बीच नशीले पदार्थ परोसे गये। एक वोट के लिए 500–1000 रुपये खर्च किये गये। चुनाव आयोग ने 313 करोड़ रुपये से ज्यादा नगदी, करोड़ों का सोना–चांदी, 2.25 करोड़ लीटर शराब एवं 185 टन नशीले पदार्थ जब्त किये। देश भर में आचार संहिता के उल्लंघन के 75,306 मामले दर्ज किये गये। इन चुनावों में सभी पार्टियों ने जाति, धर्म, लिंग, इलाकावाद का खुलकर इस्तेमाल किया।

संसदीय दलों के घोषणा पत्र– आम जनता के लिए झूठे वादें और कॉरपोरेट दुनिया के लिए सौगातें

चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपने–अपने घोषणा पत्र जारी जरूर किये थे लेकिन उनमें आम जनता के लिए कोरे वादों के सिवाय ठोस कुछ नहीं था। गरीब लोगों के लिए जो वादे घोषणा पत्रों में किये गये थे, वो महज दिखावे के लिए ही थे। गरीबी, भूखमरी, सभी को शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पेयजल व सिंचाई, बिजली, रोजगार, दलितों का उत्थान, महंगाई, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, विस्थापन, लैंगिक समानता, पार्यावरण सुरक्षा, भूमि सुधार आदि मुद्दे संसदीय दलों के एजेंडे से गायब से हो गये हैं। इन मुद्दों पर कोई वादा, कोई बहस, कोई दृष्टिकोण देखने को नहीं मिला। इन चुनावों में आमने –सामने रहे दो मुख्य संसदीय दल कांग्रेस व भाजपा दोनों के घोषणा पत्रों में मुद्दे व वादे एक समान थे, सिर्फ शब्दों का हेरफेर था। एफडीआई की अनुमति, निवेश, सौ शहरों का समूह, स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन, आर्थिक सुधार, अधो संरचना विकास, गांवों में इंटरनेट सुविधा, टैक्स सिस्टम में बदलाव आदि दोनों के घोषणा पत्र में थे। सीधी सी बात है कि इन तमाम योजनाओं का फायदा देशी–विदेशी पूंजीपतियों, बड़े ठेकेदारों को ही मिलने वाला है। भ्रष्टाचार, कालेधन के

मामले में कुछ ठोस नहीं। चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सभी को घर, पुलिस सुधार, मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों के अलावा कुछ कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख हालांकि दोनों के घोषणा पत्र में शामिल थे लेकिन उनके अमल को सुनिश्चित करने से संबंधित कोई बात नहीं। भाजपा के घोषणा पत्र में राम मंदिर, समान नागरिक संहिता एवं धारा–370 को हटाने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का खतरनाक एजेंडा यथावत रहा।

चुनाव नतीजें–एक सरसरी नजर

2014 के चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 30 साल बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के चलते उसकी शर्मनाक हार हुई। चुनावों में हालांकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला लेकिन पूरे देश के रूझान एक समान नहीं हैं। इन नतीजों पर तरह–तरह की व्याख्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा मोदी लहर, भाजपा की एक तरफा जीत, मोदी के विकास नमूने चर्चे में थे। आइये! मोदी की जीत के पीछे की असलियत व विभिन्न पार्टियों की स्थिति पर ज़रा गौर करते हैं।

कांग्रेस की हार–जन विरोधी नीतियों का अनिवार्य परिणाम

2004 से 2014 तक सत्ता में रही कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पिछले 10 सालों से उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की जन विरोधी नीतियों पर अमल करती रही। जोर–शोर से प्रचारित उसका भारत निर्माण बहुत बड़ी बेमानी साबित हुई। 10 सालों में देश व जनता की स्थिति बद से बदतर हुई। भ्रष्टाचार के मामले में 2012 में 176 देशों में 94वें स्थान पर था। विदेशी कर्ज, बजट, वित्तीय, राजस्व व करंट अकाऊण्ट घाटा लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1995–2010 के बीच के 15 सालों में देश भर में 2,56,913 किसानों ने आत्महत्या की। लाखों करोड़ रुपयों के कइयों घोटालें सामने आये। महंगाई आसमान को छूने लगी। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ गये। देशी–विदेशी पूंजीपतियों के साथ किये गये एमओयू पर अमल करने किसानों व आदिवासियों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया गया। 5वीं अनुसूची, पेसा कानून जैसे आदिवासियों को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ। विस्थापन विरोधी आन्दोलन सहित जनवादी, क्रांतिकारी आन्दोलनों पर पाशविक दमन अमल हुआ। 2009 से देशव्यापी, फासीवादी, चौतरफा सैनिक हमला– ऑपरेशन ग्रीनहंट चालू करके देश की पीड़ित जनता पर युद्ध छेड़ा गया। कुलमिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस के 10 साल का शासन देश की अधिसंख्यक जनता के लिए असहनीय बोझ बन गया था। दूसरे सही विकल्प के अभाव में, मौजूदा चुनाव प्रणाली में ही जनता ने कांग्रेस शासन से छुटकारा पाने की कोशिश की जिसे कांग्रेस विरोधी लहर कहा जा सकता है। भाजपा ने इसका भरपूर फायदा उठाया।

इन चुनावों में कांग्रेस सहित उसके करीबन सभी सहयोगी दलों का भी वही हाल हुआ जो कांग्रेस का हुआ। नेशनल कांफ्रेंस, लालू की राजद, डीएमके आदि की करारी हार हुई। यूपी में सपा, बसपा हारी। मुजफ्फर नगर दंगों के जरिए वहां समाज का सांप्रदायिक विभाजन करके भाजपा ने नाजायज फायदा उठाया। मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करके उनका विश्वास जीतने में सपा नाकाम रही। इन चुनावों में सबसे बुरा हाल सीपीआई एवं सीपीआईएम का हुआ। सांप्रदायिक भाजपा को रोकने के नाम पर कांग्रेस के का पूंछ बन जाना, शोषक–शासक वर्गों की सेवा करने की दिवालिया व संशोधनवादी राजनीति अपनाने के चलते उनका हाल बेहाल हो गया। पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम के सामाजिक फासीवादी व भ्रष्ट शासन के खिलाफ उमड़ा जनाक्रोश का फायदा इस चुनाव में भी टीएमसी को मिला। अपने मंत्रियों, नेताओं के भ्रष्टाचार, घोटालों एवं कांग्रेस के साथ सांठगांठ का खामियाजा डीएमके को भुगतना पड़ा। वहीं दूसरे सही विकल्प के अभाव की जनता की मजबूरी का फायदा जयललिता को मिल गया। सत्ता विरोधी आक्रोश के बावजूद मजबूत विपक्ष के अभाव की स्थिति का फायदा ओडिशा में नवीन पट्नायक को भी मिला। पृथक तेलंगाना राज्य हासिल करने का श्रेय बटोरते हुए तेलंगाना विधान सभा चुनाव जीतकर टीआरएस सत्ता में आयी। लंबे समय से सत्ता से दूर रहे चंद्रबाबू नायडू को सीमांध्र में कांग्रेस विरोधिता का फायदा मिला।

तथा कथित मोदी लहर का निर्माण– कॉरपोरेट मीडिया का कमाल

दस साल तक सत्ता में रहकर साम्राज्यवादियों एवं दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों की सेवा करने के चलते कांग्रेस के प्रति देश की अधिसंख्यक शोषित–पीड़ित जनता आक्रोशित हो गयी थी। उसे और सहन करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसी स्थिति में साम्राज्यवादी ताकतों, खासकर अमेरिका एवं भारत के दलाल पूंजीपति वर्ग के सामने उनके हितों को बेरोकटोक आगे बढ़ाने वाले, एलपीजी नीतियों पर तेज रफ्तार से अमल करते हुए लंबित एमओयू पर त्वरित अमल करने वाले, फासीवादी दमन में बढ़ोत्तरी करते हुए, उनके हितों के खिलाफ जारी विस्थापन विरोधी, जनवादी, प्रगतिशील व मानवाधिकार आन्दोलनों सहित क्रांतिकारी जनयुद्ध को लौह बूटों तले रौंदने वाले विकल्प की जरूरत आन पड़ी थी। ऐसी स्थिति में कॉरपोरेट दुनिया के ताकतवर हिस्से ने भाजपा व मोदी का

चयन किया। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि एक सर्वेक्षण में दुनिया के सौ बड़े पूंजीपतियों में से 75 ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना था।

उसके बाद ही 'मोदी निर्माण', 'मोदी लहर' का निर्माण होने लगा था। पार्टी नेतृत्व और संघ पर दबाव बढ़ाकर मोदी पहले भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना। औद्योगिक समूह, कॉरपोरेट मीडिया, स्वयं मोदी का प्रचार तंत्र एवं जन संपर्क विभाग के द्वारा मोदी का महिमा मण्डन करते हुए मोदी की चारों ओर कृत्रिम आभा मंडल खड़ा किया गया। मोदी को 'नीतिवान', 'दूरदर्शी', 'सर्वांगीण विकास की पुख्ता योजना से लैस नेता', 'विकास पुरुष' के रूप में प्रचारित किया गया। कॉरपोरेट की प्रत्यक्ष भूमिका, धन प्रवाह के जरिए कॉरपोरेट प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया ने एक हत्यारे को अवतार पुरुष 'नमो'—महान शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। 10 हजार करोड़ के व्यापारिक विज्ञापनों, टीवी, गूगुल, सोशल मीडिया, यू ट्यूब एवं मोदी के स्वयं के प्रचार तंत्र का कमाल था, मोदी लहर। थ्रीडी होलोग्राम टेक्नॉलोजी, हर रैली व सभा में ऊंची क्वालिटी की कैमेरा युनिट, ट्वीटर, फेसबुक, कालर ट्यून, एसएमएस, रैलियों का लाइव कव्हरेज, वीडियो कांफ्रेंसिंग, आदि का बखूबी इस्तेमाल किया। औद्योगिक घरानों के हेलिकॉप्टरों व निजी विमानों का खुलकर इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में मोदी ने तूफानी दौरा किया। इस तरह कृत्रिम ढंग से मोदी लहर पैदा करके उसे सही मानने की भ्रमाजनित स्थिति निर्मित करने के प्रयास किये गये। मोदी के पक्ष में जनमत को बदलने की कोशिशों में लगे थे, पूंजी के चापलूस, हिन्दुत्व की विषैली विचारधारा वाले बुद्धिजीवि।

मोदी के विकास का गुजरात नमूना

गुजरात में समाज के सांप्रदायिक विभाजन के जरिए मोदी ने तीन बार—2002, 2007 फिर 2012 में गुजरात में सत्ता संभाली। 2002 के मुसलमानों के नरसंहार के बाद से मोदी के एजेण्डे में हिन्दुत्व और विकास साथ—साथ चले। मोदी का विकास मॉडल दरअसल बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा देश की सार्वजनिक संपत्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, खुली लूट व देश के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों के शोषण—दमन, बदहाली, विस्थापन, पर्यावरण विध्वंस एवं राज्य की देखरेख में एक कौम के नरसंहार का मिला—जुला रूप है। गुजरात राज्य की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। पिछले 10 वर्षों में गुजरात में मोदी सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायदा राज्य में निवेश करने वाले चार औद्योगिक घरानों — रिलयंस, अदानी, एस्सार एवं एल एंड टी को ही मिला। इन्हें हजारों करोड़ रुपयों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायदे पहुंचाये गये। मोदी के विकास कार्यों में शामिल हैं, बड़े—बड़े फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे, ऊंची—ऊंची गगनचुंबी इमारतें, विशेष आर्थिक जोनें, बड़े—बड़े मॉल, सुंदर रिवर फ्रंट आदि। यह है, विकास का मोदी नमूना।

लेकिन इस गुजरात नमूने पर चर्चा और आलोचना न के बराबर हुई। औद्योगिक विकास, युवाओं को रोजगार के रूप में ही उक्त विकास को प्रचारित किया गया। मोदी लहर के प्रचार तंत्र ने विकास के गुजरात नमूने की सच्चाई को सामने नहीं आने दिया। यही कारण है कि युवा वर्ग का एक खासा हिस्सा इन चुनावों में मोदी की ओर आकर्षित हुआ जो कि चिंताजनक व अफसोसनाक है।

इस सब के बावजूद कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण व पूर्वी राज्यों में मोदी लहर का कोई खास असर नहीं दिखा। इस संदर्भ में भाजपा की मोदी जीत के पीछे के अन्य कारणों पर गौर करना जरूरी है।

— भ्रष्टाचार के खिलाफ आरएसएस की मदद् से अण्णा हजारे ने जो आन्दोलन चालू किया था, उसे मध्य वर्ग का व्यापक समर्थन मिला था। इस पूरे आन्दोलन में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा। साथ ही आसमान छूती महंगाई ने आग में घी का काम किया। साथ ही दिल्ली बलात्कार कांड, उसके बाद उठे महिलाओं पर अत्याचार विरोधी आन्दोलन ने एक मजबूत कांग्रेस विरोधी नींव तैयार किया था। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी उस आन्दोलन की ऊर्जा, उम्मीद व ताकत को संभाल नहीं सकी। इस स्थिति का भाजपा ने भरपूर फायदा उठाया। असल में इसके पहले भाजपा हताश पार्टी थी। किसी मौके की तलाश में थी। यहां यह कहना लाजिमी होगा कि 'आप' भी शोषक—शासक वर्गों के एक गुट के संरक्षण से उपजी है और उन्हीं वर्गों की सेवा करने वाली है।

— भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के खुले लक्ष्य के साथ काम करने वाला आरएसएस जो मुसलमानों को उसके प्रधान दुश्मन मानता है लंबे समय से जमीन तैयार कर रहा है। 2014 के चुनावों में पहली बार आरएसएस एवं भाजपा—दोनों ने खुले तौर पर एवं गर्व से अपने आपसी रिश्तों का खुलासा किया था। 2014 के चुनाव में संघ परिवार के करीबन 55 संतानों ने खुलकर भाजपा के पक्ष में काम किया। संघ परिवार की यह तैयारी काफी पहले से जारी है। भारत स्वाभिमान आन्दोलन, आजादी बचाओ आन्दोलन और भी कई नामों से राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव, रविशंकर आदि कई छद्म रूपों में भाजपा के लिए जमीन तैयार करते आये।

— मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा के अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2002 के गुजरात प्रयोग को

दोहराया। इस सांप्रदायिक विभाजन से एक तरफ मुसलमानों को सपा, बसपा से दूर किया गया तो दूसरी तरफ हिंदू वोटों का धृवीकरण हो गया जिसका नतीजा है, उत्तर प्रदेश का भाजपा की झोली में चला जाना। 2014 के चुनावों में उत्तर भारत की संसदीय राजनीति में सांप्रदायिक यानी हिंदू वोटों का धृवीकरण स्पष्ट रूप से देखने को मिला है।

कॉरपोरेट लूट, फर्जी विकास नमूने एवं हिन्दुत्व फासीवाद का विरोध आज का मुख्य कर्तव्य है

मोदी ने अपनी जीत के बाद ट्वीट किया–'भारत वर्ष जीत गया, अच्छे दिन आयेंगे'। 'मोदी की आंधी, पूंजीपतियों की चांदी'–कुछ अखबारों में बैनर लगे। फिक्की (एफआईसीसीआई) से लेकर कई उद्योग समूहों ने मोदी से उद्योग अनुकूल नीतियों की आशा व्यक्त की। इन सबसे यह समझना कठिन नहीं होगा कि किसके लिए अच्छे दिन आ गये हैं। बेशक, देशी, विदेशी औद्योगिक घरानों के लिए पहले से भी और अच्छे दिन आ गये हैं।

मोदी के शासन काल में कॉरपोरेट लूट व फासीवादी शासन के विस्तार में, जन आन्दोलनों के दमन में एवं दक्षिण एशिया में विस्तारवादी नीतियों पर अमल में तेजी आयेगी। स्पष्ट जनादेश के बहाने मोदी किसी की परवाह किये बिना अपनी मनमानी करेगा। मोदी के शुरूआती कदमों से ही यह आहट स्पष्ट व मजबूती से सुनायी दे रही है।

अपनी जीत को भारत वर्ष की जीत कहने में भारतीय राष्ट्रीय दुरहंकार की बू आ रही है। उमा भारती के ये शब्द – 'हमारे खून में संघ के विचार दौड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद प्रचारक व स्वयंसेवक हैं', भविष्य में बढ़ने वाले हिंदुत्व के खतरे को भापंने के लिए काफी है। सोशल मीडिया में मोदी विरोधी व्यख्या के लिए लखनाऊ में गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। यह भिन्नमत को सड़क पर सहन न करने का ही संकेत है।

मोदी सरकार ने रेल भाड़े में 14.2 प्रतिशत एवं मालभाड़े में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके अपनी जन विरोधी नीतियों के अमल की शुरूआत की। अगला कदम होगा, गैस की कीमतों में वृद्धि।

सत्तासीन होने के बाद मोदी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। पूंजी निवेश को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बुनियादी ढ़ांचे का विस्तार, सड़कों पर जोर, नयी टैक्स व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट सम्मिट आयोजित करना, सौ आधुनिक शहरों का निर्माण, एफडीआई की अनुमति आदि इनमें शामिल हैं। इन तमाम प्राथमिकताओं से सीधा–सीधा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े दलाल पूंजीपतियों, बड़े ठेकेदारों को होने वाला है। मोदी की प्राथमिकताओं में देश का आम आदमी दूर–दूर तक नजर नहीं आ रहा है।

अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस–राष्ट्र एवं मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रित करके मोदी ने दक्षिण एशिया में अपनी विस्तारवादी मंसूबों को प्रकट किया है। एक हिंदुत्ववादी बुद्धिजीवि का यह कथन कि 'मोदी का यह निमंत्रण दक्षिण एशियाई राष्ट्रों–प्राचीन आर्यावर्त्त को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का शुभारंभ है', संघ के एजेंडा का व्यक्तीकरण ही है।

सत्ता संभालते ही गृहमंत्री राजनाथसिंह ने नक्सलवाद व आतंकवाद को देश के आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। यह पिछली कांग्रेस सरकार की ही नीति की निरंतरता है। मोदी ने सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ को अर्ध–सैनिक बलों की 10 बटालियन मंजूर किया है। नक्सल मोर्चे पर यूएवी सहित हाईटेक होने की बात कही गयी है। फोर्स की कमी नहीं होने देने, नक्सल ऑपरेशन के लिए मिलने वाले बजट में कटौती न करने, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि को छत्तीसगढ़ को भी देने की घोषणा की गई। भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध को खत्म करने के उतावलेपन को उक्त घोषणा में देखा जा सकता है।

एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय संकट गहराता जा रहा है और क्रांतिकारी जनयुद्ध, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन एवं जनवादी आन्दोलन तेज हो रहे हैं। दूसरी ओर इस संकट से बाहर आने, संकट के बोझ को उत्पीड़ित जनता एवं राष्ट्रीयताओं पर लादने एवं आन्दोलनों का सामना करने व सफाया करने साम्राज्यवादी ताकतें खासकर अमेरिका व दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग फासीवादी दमन का सहारा ले रहे हैं, नव फासीवादी रूपों में शासन स्थापित करना चाह रहे हैं। पूर्व सरकारों की विफलता से पैदा हताशा व रिक्तता को एक मसीहाई मुद्रा के साथ अपने हक में मोड़ते हुए फासीवादी सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। भाजपा की मोदी जीत को इसी तरह की शुरूआत के रूप में देखा जा सकता है। यह देश के जनवादी, प्रगतिशील, देशभक्त व क्रांतिकारी शक्तियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

इस चुनौती से निपटने मोदी के विकास के नमूने का देश की जनता खासकर युवा वर्ग के सामने पर्दाफाश करना होगा। राष्ट्र हित, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जरिए विकास व रोजगार कहते हुए भाजपा के द्वारा युवाओं के फासिजीकरण का जो प्रयास होगा, उसे रोकना होगा। रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर जनता की व्यापक गोलबंदी करनी होगी। आन्दोलनों को विकास की राह में बाधा के रूप में पेश करने के मोदी के फासीवादी विकास

दण्डाधिकारी व न्यायिक जांचों का प्रहसन जनता को दिग्भ्रमित करने की नाकाम कोशिश

मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों या नरसंहारों के मामले में जनता के आक्रोश को ठंडा करने के लिए या जनवादी आन्दोलनों की मांग के सामने झुककर सरकारें हालांकि मामलों की जांच के आदेश देती हैं और आयोग गठित करती हैं लेकन न ही जांच रिपोर्टें समय पर आती हैं और न ही उन आयोगों की सिफरिशों पर ठीक–ठाक अमल होता है। सब कुछ औपचारिकता बन कर रह जाता है। सभी मुठभेड़ों के मामले में दण्डाधिकारी जांच का आदेश देना साधारण बात है। अखबारों के माध्यम से यह विज्ञापन या बयान जारी किया जाता है कि लोग निडर होकर जांच अधिकारी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करें या बयान दर्ज करायें। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में, बेखौफ होकर बयान देना आम जनता के लिए कम मुसीबत वाली बात नहीं है। पुलिस प्रताड़ना का सामना करके कोई यदि बयान देने की हिम्मत भी करता है तो रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकार कूड़ेदान में फेंक देती है। फरवरी, 2014 में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव के सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राम सेवक पैकरा ने विधानसभा में न्यायकि जांच व दण्डाधि ाकारी जांच के लंबित मामलों का विवरण दिया था। निम्नांकित उस विवरण से यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा कि दण्डाधिकारी या न्यायिक जांच लोगों को भरमाने का प्रहसन भर है। गृह विभाग से संबंधित 47 दण्डाधिकारी जांच और 5 मामलों में न्यायिक जांच आयोग की जांच लंबित है।

28 जनवरी, 2014 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में सीतागांव क्षेत्र में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ की दण्डाधिकारी जांच 24 जनवरी 2013 से लंबित है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 23 फरवरी 2013 थी। कोरबा की एक, सुकमा की 4, बिलासपुर की 6, बीजापुर की 5, नारायणपुर की 7, सुरजपुर की 2, कांकेर की एक, कोंडागांव की एक, बलरामपुर की एक जांजगीर–चापा की एक, रायपुर की 13, बेमेतरा की एक, जगदलपुर की एक जांच लंबित है। इनमें से कई रिपोर्ट दो सप्ताह और ज्यादातर की एक माह के भीतर देनी थी। पैकरा ने यह भी बताया कि जिन 5 मामलों में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है, उनमें मीना खलको के मामले की जांच के लिए अनिता झा का एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग 29 अगस्त से कार्यरत है। चिंतलनार क्षेत्र में हुई घटना की जांच के लिए न्यायाधीश टीपी शर्मा जांच आयोग का गठन 12 मई 2011 को किया गया है। आयोग को गठन के तीन माह के भीतर आपनी रिपोर्ट देनी थी। सारकेगुड़ा–चिलगेर–चिमलीपेंटा में घटित घटना की जांच के लिए जस्टिस वी के अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग 11 जुलाई 2012 को गठित किया गया है। आयोग को गठन के तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह गंगालूर थाना के ग्राम एड़समेट्टा में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की जांच के लिए जस्टिस वी के अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन 19 मई, 2013 को किया गया। आयोग को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह बस्तर के दरभा थाना क्षेत्र के झीरमघाटी में घटित घटना की जांच के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन 28 मई, 2013 को किया गया है। आयोग को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। जबकि हालत यह है कि इन तमाम मामलों में अभी भी जांच जारी है। ये जांचें कब पूरी होती हैं यह कोई नहीं कह सकता है। जांच रिपार्टें कभी आती भी हैं तो पुलिस के पक्ष में ही। कभी–कभार पुलिस के खिलाफ आती भी हैं तो उन पर अमल का सवाल ही नहीं उठता है।

★

को बेनकाब करना होगा। देश के असली विकास का मतलब है, बहुसंख्यक जनता–मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ, दलित, आदिवासियों का विकास। स्वावलंबन पर आधारित जनता का समग्र व सर्वांगीण विकास। सबसे महत्वपूर्ण है, इनसान के द्वारा इनसान का शोषण–दमन न हो। सभी तरह के धार्मिक विचारों के लोग समान रूप से जिएं। इसे जनता के सामने जोरदार ढ़ंग से रखना होगा।

मजदूर, किसान, छात्र–युवा, बुद्धिजीवि, प्रगतिशील, जनवादी, मानवाधिकार, देशभक्त शक्तियों व जन हितैषियों को एकजूट व संगठित होकर विस्थापन विरोधी, दमन विरोधी, जनवादी, मानवाधिकार आन्दोलनों का संचालन करते हुए एक व्यापक, जुझारू व संगठित जनांदोलन का निर्माण करना आज एक मुख्य कर्तव्य है। देश के चार वर्गों की जनता की मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए नवजनवादी क्रांति जिसकी धुरी कृषि क्रांति है, को सफल बनाना ही एक मात्र रास्ता है। जनांदोलनों को क्रांतिकारी जनयुद्ध के साथ बेहतर तालमेल करके ही तमाम किस्म के प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रांतिकारी व फासीवादी शोषक–शासक वर्गों को उखाड़ फेंक सकते हैं।

★

छत्तीसगढ़ बजट 2014–15 – गरीबों की लूट–अमीरों को छूट

तीसरी बार मुख्यमंत्री बने रमन सिंह ने विगत 8 फरवरी को विधानसभा में 2014–15 का बजट पेश किया। बजट में 54,710 करोड़ का व्यय, 54,661 करोड़ की आय के स्रोत जबकि 49 करोड़ का घाटा दर्शाया। विगत 5–6 सालों के घाटे जिसका कोई अता–पता नहीं, को मिलाकर कुल घाटा 5,761 करोड़ तक पहुंच गया है। कर्ज में पहले से ही गले तक डूबी रमन सरकार को वर्तमान घाटे की पूर्ति के लिए और कर्जा करना होगा। जबकि राज्य पहले ही 40 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जदार है। यह बजट राज्य के गरीबों, किसानों का पेट मार कर कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियां भरने वाला है।

कुल 54,710 करोड़ के बजट में से आर्थिक क्षेत्र के लिए 18,054 करोड़ यानी 33 फीसदी, सामाजिक क्षेत्र के लिए 20,851 करोड़ यानी 38 फीसदी, वेतन भत्तों, पेन्शन, ब्याज चुकाने जैसे साधारण सेवाओं यानी सेवा क्षेत्र के लिए 19,365 करोड यानी 35 फीसदी आबंटित किये गये। नगर निगमों, विश्वविद्यालयों एवं वेतनभत्तों के लिए आबंटित 6 फीसदी को भी सामाजिक क्षेत्र में मिलाकर सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटित राशि को 38 फीसदी दिखाया गया। कृषि क्षेत्र जो कि राज्य की अर्थ व्यवस्था का आधार है, के लिए 15.5 फीसदी, शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए क्रमशः 12 व 5 फीसदी के हिसाब से बजट आबंटित किया गया। आय के स्रोतों में प्रत्यक्ष करों से 24,111 करोड़ यानी 44 फीसदी मिलने की उम्मीद है। बाकी में से केंद्र के द्वारा वसूल किये जाने वाले करों में राज्य के हिस्से के तहत 20 प्रतिशत, केंद्र सरकार की मदद से 17 प्रतिशत और 10 फीसदी ऋण, बांडों, छोटे बचत खातों, व अन्य जरियों से 9 प्रतिशत मिलने की संभावना जतायी गयी।

सालों से गंभीर संकट में फंसे कृषि क्षेत्र को बचाने व उभारने में बुरी तरह विफल रही राज्य सरकार के इस बार का बजट आबंटन भी इसी बात को दर्शाता है। कृषि के लिए आबंटित 8,459 करोड़ की राशि 2013–14 में आबंटित 8,542 करोड़ से 83 करोड़ कम है। एक ओर किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने की बात करते हुए अलग से कृषि बजट पेश करने वाली रमन सरकार दूसरी ओर उसमें कटौती की है।

धान की बिक्री पर किसानों को दिये जाने वाले बोनस के लिए 2,400 करोड़, सहकारी समितियों को 450 करोड़, बिना ब्याज के ऋणों के लिए 140 करोड़ सहित मार्कफेड, गोदामों के निर्माण, नष्ट हुए धान के लिए आबंटित राशियों को एक जगह में जोड़कर उसे कृषि बजट का नाम दिया गया है। बजट में कृषि परियोजनाओं के लिए आबंटन बहुत ही कम है। सरकार के प्रति किसानों में दिन–ब–दिन बढ़ते असंतोष को भटकाने के लिए ही इस विशेष कृषि बजट की नौटंकी है। किसानों की समस्याओं के असली हल की उम्मीद इस लुटेरी सरकार से कतई नहीं की जा सकती है। धान की बिक्री पर बोनस एवं गोदामों के अभाव में बरसात में सड़कर नष्ट होने वाले धान के लिए आबंटित राशियों को कृषि बजट में शामिल करना रमनसिंह की बेमानी को दर्शाता है।

खेती के विकास के लिए सिंचाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2013–14 के बजट में सिंचाई के लिए 2,010 करोड़ की राशि आबंटित थी जबकि 2014–15 में इसे 1,987 करोड़ तक घटाया गया। कुल बजट का यह सिर्फ 4 प्रतिशत ही है। बजट में 5 मंझोले, 68 छोटी परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिल गयी। बजट में आबंटित आधी–अधूरी राशि से ये योजनाएं कब पूरी हो सकती हैं, यह कोई नहीं कह सकता है। महानदी परियोजना के रीमॉडलिंग लाइनिंग के लिए सिर्फ 110 करोड़ आबंटित है जिससे कि इसे पूरा करना असंभव है। रमन सरकार जो कि बरसों से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा रही है, कॉरपोरेट पवर कंपनियों की मांग पूरा करने युद्ध स्तर पर नदियों पर एनीकट निर्मित करके पानी की आपूर्ति कर रही है। कारखानों की जरूरतों के लिए निर्माण करने वाली एनीकटों के लिए बजट आबंटन की जरूरत नहीं होती है। किसी भी मद से बदल देते है।

बीज, खाद, कीटनाशकों की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते खेती की लागत बहुत बढ़ रही है। सहकारी संस्थाओं व ग्रामीण बैंकों के जरिए सरकार के द्वारा दिये जाने वाले ऋण बहुत कम है। ब्याज रहित कर्ज के लिए आबंटित 140 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सरकारी ऋणों के न मिलने के कारण गरीब व मध्यम किसानों के पास सूदखोरों, निजी बैंकों से अधिक ब्याज पर कर्जा लेने के सिवाय दूसरा चारा नही हैं।

निजी बैंक किसानों के कर्ज पर 14 प्रतिशत ब्याज जबरन वसूल कर रहे हैं। अकाल, अतिवृष्ठि ओलावृष्ठि आदि प्राकृतिक विपदाओं, मिलावटी व निम्न गुणवत्ता के बीज एवं कीटनाशक दवाओं, कीट प्रकोप, एवं फसलों का समर्थन मूल्य न मिलने आदि के चलते किसान न केवल कर्ज में डूब रहे हैं बल्कि ब्याज भी आदा नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आत्म हत्याएं कर रहे हैं। रमनसिंह के 10 साल के शासनकाल के दौरान ही 2011 तक राज्य भर में 14,340 किसानों ने आत्महत्या की। यह आज भी बेरोकटोक जारी है। सिप्लंकर्स, निंदाई के ट्रान्स प्लांटर्स,

ट्रेक्टर ट्रैली, ड्रिप सिंचाई आदि में रियायतें मिल गयी हैं लेकिन 60–70 फीसदी गरीब व मंझोले किसानों को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। 3,600 करोड़ की बोनस बकाया राशि जो कि विगत 3 सालों से पेंडिंग पड़ा है, का इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं है। आखिरी सांसे गिन रहे कृषि क्षेत्र को कर्ज की सहूलियत से लेकर उचित समर्थन मूल्य देकर बचाने की बजाय सीधे कृषि क्षेत्र का ही कॉरपोरेटीकरण करने की योजनाएं बना रही है। रमन सिंह के किसानों के उद्धार की बात कोरी बकवास ही है।

सामाजिक कल्याण के तहत आने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला व बाल कल्याण, अनुसूचित जाति व जन जातीय कल्याण आदि के लिए विगत के 17,761 करोड़ की तुलना में इस बजट में राशि बढ़ाकर 20,851 करोड़ आबंटित की गयी। लेकिन कुल बजट का यह सिर्फ 38 प्रतिशत ही है। जबकि पिछले बजट में यह 41 प्रतिशत रहा। बजट में शिक्षा के लिए 6,565 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 2,735 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1,641 करोड़, एससी व एसटी कल्याण के लिए 4,376 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। बजट में शिक्षा को महत्व देने की बात करने वाला रमनसिंह प्राथमिक शिक्षा को हाशिये पर ला दिया। आज भी सैकड़ों गांवों में प्राथमिक शालाएं नहीं हैं। जहां हैं, शिक्षकों, शाला भवनों, आश्रम शालाओं का अभाव है। इसके चलते प्राथमिक शिक्षा का स्तर बरसाती पढ़ाई से ज्यादा विकसित नहीं है। बजट में 32 स्नातकोत्तर महाविद्यायलय, 20 कन्या आश्रम, 3 पॉलीटेक्निक एवं 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गयी। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्र–छात्राओं को 1 प्रतिशत ब्याज पर शैक्षणिक ऋण देने का प्रस्ताव है। रमन सरकार सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम तो रही ही, साथ ही वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में होने वाले खर्चों को कम करने की बजाय, उल्टे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने ब्याज युक्त कर्जा देने की बात कर रही है। उच्च शिक्षा चूंकि महंगी होती जा रही है इसलिए गरीब व मध्य वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। रमनसिंह का बहुप्रचारित नारा– 'बच्चों पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो', सस्ती लोकप्रियता के लिए ही है। इस बजट में शिक्षाकर्मियों के लिए कोई आबंटन नहीं है जबकि सालों से इनकी दो मांगें–संविलयन, समान वेतन मान लंबित हैं। विधान सभा चुनावों के अपने घोषणा पत्र में रमनसिंह ने यह वादा किया था कि सरकार 3,300 करोड़ रुपयों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड के जरिए 20 हजार लोगों का इलाज करायेगी। लेकिन बजट में इसके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। गंभीर बीमारियों का इलाज तो दूर की बात है, सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के चलते साधारण बीमारियों जैसे उल्टी–दस्त, पतली दस्त, मलेरिया से हर साल बड़े पैमाने पर लोगों खासकर आदिवासियों की मौतें हो रही हैं।

रमनसिंह की किसान विरोधी नीतियों के चलते आजीविका की तलाश में हर साल 30 लाख से ज्यादा भूमिहीन व गरीब किसान खेती बाड़ी के कामकाज के बाद पलायन करते हैं और वहां तरह–तरह के शोषण, जुल्म, अत्याचारों के शिकार होते हैं। इस बजट में पलायन को रोकने, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई, इलाज के लिए पूर्व में संचालित योजनाओं का जिक्र भी इस बजट में नहीं है।

महिलाओं को सही रोजगार उपलब्ध कराने में नाकाम सरकार उन्हें कम ब्याज पर ऋण सुविधा देने के नाम पर उनकी मेहनत को लूटने की बैंकों की योजना पर अमल कर रही है।

राज्य गठन को हालांकि 13 साल पूरे हो गये हैं, बावजूद इसके 8,815 गांवों में शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। फिर भी बजट में आबंटन नाममात्र का ही है। गांवों के विद्युदीकरण के लिए आबांटित 1 करोड़ रुपये किसी भी कोने के लिए नहीं पूरेगा। राज्य में 10,906 गांव, टोले घुप अंधेरे में हैं। आज भी 20 लाख परिवारों तक बिजली नहीं पहुंची है। गांवों के स्थाई विद्युदीकरण की योजना पर अमल करने की बजाय गरीबों को एकल बत्ती कनेक्शन तक सीमित करके बाकी बिजली को सब्सिडी दरों पर बड़ी कंपनियों को उपलब्ध करा रही है। सभी गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने एवं संपूर्ण ग्रामीण विद्युदीकरण के लिए एक समग्र योजना बनाने में नाकाम सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला मार्गों के निर्माण के लिए बड़ी राशि 2,618 करोड़ आबंटित की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह बजट आम जन हित का नहीं है।

गंभीर आर्थिक संकट में फंसे छोटे कारखानों के मालिकों की आशाओं पर यह बजट एक तरह से कुठाराघात है। बजट में बंद पड़े, बंद के कगार पर खड़े छोटे इस्पात संयंत्रों को रियायतें देकर बचाने की बात रमनसिंह ने अपने बजट भाषण में कही। बंद इस्पात संयंत्रों को फिर से खुलवाने करों में कटौती दिखायी। इन कारखानों के उत्पादों पर बिक्री कर 2 से 1 प्रतिशत, पिग आयरन, स्क्रैप, आयरन ओर पैलेट, फेर्रो अल्लॉय आदि कच्चामाल की खरीदी पर वैट (मूल्य युक्त कर) 5 से 2 प्रतिशत घटाया। उसी तरह छोटे व मंझोले उद्योगों को रियायत देते हुए बाहर से मंगाने वाले आयरन ओर पैलेट, बिलेट पर मौजूदा

1 प्रतिशत एंट्री टैक्स को हटा दिया। इससे 100 स्पांज आयरन उद्योगों, 150 मिनी स्टील प्लांटों, 190 रोलिंग मिलों को सीधा फायदा होने, लौह अयस्क को सस्ते में आयात करने की बात रमनसिंह ने कही। सतही तौर पर देखने से यह लगता है कि वैट, सेल टैक्स घटाकर, एंट्री टैक्स हटाकर रमनसिंह ने छोटे व मंझोले उद्योगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। लेकिन गहराई से देखने पर इसका खोखलापन समझ में आता है। राज्य के बैलाडिला के लौह अयस्क खदानों से सालाना दसियों लाख टन लौह अयस्क कौड़ियों के भाव–600 रु. प्रति टन चीन, जापान, कोरिया निर्यात किया जाता है। जबकि खुले बाजार में इसे 5,600 रु. प्रति टन के हिसाब से खरीदना पड़ता है। स्पंज आयरन उद्योगों के मालिकों ने बैलाडिला के लौह अयस्क के 10 प्रतिशत हिस्से को उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे केंद्र–राज्य सरकारों ने ठुकरा दिया। सिर्फ वैट, सेल टैक्स घटाकर, एंट्री टैक्स हटाकर इन उद्योगों को नहीं बचाया जा सकता है। कच्चा माल और बिजली की आपूर्ति के जरिए ही इन्हें पूरी तरह डूबने से बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार का इरादा तो बड़े पूंजीपतियों की सेवा व उनके हित में काम करने का है। छोटे उद्योगपतियों को चाहिए कि वे सस्ती दर पर लौह अयस्क की आपूर्ति की मांग को लेकर सरकार से संघर्ष करे। छोटे कारखानों को मदद् पहुंचाने के नाम पर बाक्साइट पर वैट घटाकर वेदांता के अनिल अग्रवाल को एवं सोया पर वैट हटाकर अड़ानी को फायदा पहुंचाने का काम रमनसिंह ने किया। यूपीवीसी पर वैट को 14 से 5 प्रतिशत घटाया गया। इससे एक तरफ प्लास्टिक कॉरपोरेटों के मुनाफे में बेतहाशा वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर बढ़ाई काम करने वाले दस्तकार कारीगारों की आजीविका हड़पी जायेगी। उसी तरह विदेशों से आयातित कोकिंग कोल पर एंट्री टैक्स को 6 से 1 प्रतिशत घटाया गया। इससे भिलाई इस्पात संयंत्र के मुनाफे बढ़ेंगे। मजदूरों की मेहनत को लूटकर मुनाफा कमाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी उद्योगों से कहीं भी पीछे नहीं है।

हर साल की तरह इस बार भी पुलिस बजट को और बढ़ाया गया। 2003 में पुलिस बजट 288 करोड़ था। वही 2013–14 में 1,862 करोड़ तक पहुंच गया। पुलिस बलों की संख्या 27 हजार से बढ़कर 67 हजार तक बढ़ गयी है। राज्य में अब तक सीआरपीएफ की 27, बीएसएफ की 7, आईटीबीपी की 3 एवं आईआरबी की 9 बटालियन तैनात हैं। और चार आईआर बटालियनों के गठन की अनुमति देकर बजट में इसके लिए 4 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। साथ ही कांकेर व बलरामपुर थानों को भी मंजूरी दी गयी। माओवाद प्रभावित इलाकों के नाम पर बस्तर, सरगूजा, गरियाबंद जैसे संघर्ष इलाकों में सड़क निर्माण को तेज कर रहे हैं। पुलिस थानों, कैंपों के भवन निर्माण, खुफिया तंत्र की मजबूती एवं सिविक एक्शन प्रोग्रामों के लिए बड़े पैमाने पर धन राशि खर्च किया जा रहा है। माओवादी आन्दोलन के उन्मूलन की रणनीतिक तैयारियों के तहत ही यह सब किया जा रहा है। जनता की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति न कर सकने वाली सरकार जमींदारों व कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति की रक्षा करने वाली पुलिस विभाग के लिए हजारों करोड़ रुपये पानी की तरह खर्च कर रही है। जल, जंगल, जमीन पर अधिकार के लिए, विस्थापन के विरोध में संघर्षरत जनता खासकर आदिवासियों के दमन के लिए राज्य बलों सहित केंद्र के अर्ध–सैनिक बलों को बड़े पैमाने पर तैनात करके छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस छावनी में बदला जा रहा है।

बजट में सामान्य व्यय (वेतन–भत्तों, पेन्शन, ब्याज, नगर निगमों, विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन भत्तें) के लिए 19,365 करोड़ आबंटित हैं। इसमें से ब्याज के एवज में ही 1,822 करोड़ खर्च हो रहे हैं। यह बजट का 35 फीसदी है। मंत्रियों– विधायकों व उच्चाधिकारियों के वेतन भत्तों के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का वेतन 90 हजार प्रति माह है जबकि विधायकों का प्रति माह वेतन 40 हजार से 75 हजार तक बढ़ा दिया गया है। पिछले साल विधानसभा में बिना किसी चर्चा के ही यह वेतन बढ़ोत्तरी बिल पास हो गया था। एक ओर सरकारी खर्च में बेरोकटोक बढ़ोत्तरी, दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाओं में कटौती की जा रही है। बढ़ते खर्चों के लिए रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसियन डेवेलपमेंट बैंक आदि से कर्जा लाना और ब्याज भरना हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार ने 2013–14 में ब्याज के रूप में 1,246 करोड़ का भुगतान किया जबकि 2014–15 बजट में ब्याज के लिए ही 1,822 करोड़ का आबंटन है। ब्याज भुगतान, बढ़ते घाटे की पूर्ति के लिए आगामी समय में और कर्जा करना होगा। कॉरपोरेट घराने परस्त नीतियों पर अमल करते हुए रमनसिंह सरकार एक तरफ उनकी कंपनियों के लिए जमीन, पानी, बिजली, सड़क आदि बुनियादी ढांचा तैयार करके दे रही है और साथ ही उन्हें पूंजी निवेश में मदद, ब्याज माफी, विद्युत शुल्क में छूट एवं मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान आदि रियायतें दे रही है। कान मरोड़ कर जनता से वसूले गये करों से प्राप्त जनधन को इसमें लगा रही है, जबकि राज्य की जनता कर्ज के बोझ तले दब रही है।

बजट में आसमान छूती महंगाई पर नियंत्रण से संबंधित कोई उपाय नहीं है। आम जनता की दैनिक जरूरत की वस्तुओं–साबून, तेल, चायपत्ती, बिस्कुट, पेस्ट,

खाद्य पदार्थ, अगरबत्ती, मोमबत्ती, साइकिल ट्यूब, टायर, कृषि औजार, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं आदि पर मौजूदा 5 प्रतिशत वैट को नहीं घटाया गया। कोई राहत नहीं दी गयी। आखिर, सरकार के इस बजट ने गरीबी रेखा से नीचे यानी सिर्फ 26 रुपये प्रति दिन की आमदनी के साथ जीवनयापन करने वालों से भी कर वसूल करने से बाज नहीं आयी। सौ रुपये के बिस्कुट या खाद्य तेल पर 4.76 रुपये, 418 रुपये के सब्सिडी सिलंडर पर 83 रुपयों का वैट, एक लीटर पेट्रोल पर 14 रु, डीजल पर 12 रुपये वसूल रही है। इनके अलावा जमीन कर, मकान कर, पानी व बिजली शुल्क, नगर निगम शुल्क आदि कमरतोड़ वसूली कर रही है। इन करों की कुल राशि गरीबों के परिवारिक आय का 20 प्रतिशत से भी बढ़ गयी है। प्रति हजार रुपये के खर्च में ही करीबन 200 रुपये के कर निर्दयतापूर्वक वसूल रही है। जनता से कर वसूलने में आगे रहने वाली सरकार उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में घोर लापरवाही बरत रही है। पुलिस, शासन, प्रशासन के खर्च साल–दर–साल बढ़ रहे हैं। इससे जन जीवन पर असहनीय बोझ बढ़ रहा है।

रमन सरकार के बजट में जनता की आकांक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं है। गहरे संकट में फंसे कृषि क्षेत्र को उभारने की बजाय आबंटन में कटौती की गयी। यह आपराधिक लापरवाही है। शिक्षा को उचित महत्व देने की बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त करने विद्यार्थियों को कर्जा करने कहा गया है। सबला, बाल हृदय, स्मार्ट कॉर्ड आदि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए चुनावी वादे के मुताबिक भी विशेष पैकेज नहीं दी गयी। 17 लाख खेत मजदूरों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण की कोरी बखान के सिवाय बजट में कोई आबंटन नहीं है। शुद्ध पेयजल, सिंचाई, विद्युदीकरण आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराने समग्र योजनाओं के बारे में भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है। हर साल काम की तलाश में पलायन करने वाले 30 लाख से भी ज्यादा भूमिहीन व गरीब किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने, उनके बच्चों–बूढ़ों के कल्याण के बारे में भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई पर एक लफ्ज नहीं। आधे–अधूरे अमल हो रही कल्याणकारी योजनाओं को भी बीच में रोककर अपने राजनीतिक फायदे के लिए आकर्षक व सस्ती लोक प्रियता की नयी योजनाओं का ऐलान जारी है। ये योजनाएं अमल के लिए कम, प्रचार के लिए ज्यादा हैं। विभिन्न परियोजनाओं व जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आबंटित राशि को मंजूर न करके बीच में रोकना, यह शासकों की सोची–समझी चाल है। बची हुई राशि को वापस मंगायी जाती है। हमें यह भी स्पष्ट समझना चाहिए कि बजट आंकड़ों का ऐसा खेल है जिससे जनता को छला जाता है, भरमाया जाता है। पिछले साल स्वास्थ्य के लिए आबंटित राशि का 78 प्रतिशत राशि ही खर्च की गयी थी। जबकि पुलिस विभाग के लिए आबंटित 1,862 करोड़ राशि की जगह 1,903 करोड़ खर्च किये गये। बजट आबंटन व खर्च की गयी राशि में काफी फर्क होता है। करों की वसूली में गरीबों की लूट अमीरों को छूट। आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखकर कॉरपोरेट घरानों के लिए जनधन से ढ़ांचागत संरचना तैयार करके लाल कालीन बिछाया गया। बजट घाटे की पूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया। विगत 10 सालों के बजट घाटे की कुल राशि 5,761 करोड़ की पूर्ति करने जनता पर और करों का भार बढ़ेगा। गले तक कर्ज में डूबी सरकार और कर्जा करेगी। कर्ज चुकाने व ब्याज भुगतान के लिए नया कर्ज। कुल मिलाकर जनता के कंधों पर ही बोझ लाद दिया जायेगा। बजट के पहले के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रति व्यक्ति आय 5,069 रुपये तक बढ़ेगी लेकिन यह दावा झूठा साबित हुआ। जबकि सच्चाई यह है कि प्रति व्यक्ति पर 14,267 रुपये का कर्ज लाद दिया गया। रमनसिंह की नित नयी, आकर्षक व सस्ती लोकप्रियता की येजनाओं– एक रुपये में किलो चावल, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन, नोनी सुरक्षा, सबलायोजना, अटल आवास, घरेलू श्रमिकों का कल्याण, ई–छात्रवृत्ति, लैपटोप, सोलार लैंप, एकलबत्ति, मध्यान्ह भोजन, दाल–भात, रेडी टू ईट आदि से जनता की मूलभूत समस्याओं–जोतने वालों को जमीन, जल–जंगल–जमीन पर अधिकार, खाना, कपड़ा, मकान, इलाज, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई आदि का हल नहीं हो सकता है।

दरअसल रमनसिंह का बजट गरीबों, किसानों, मध्यवर्ग, मजदूरों, महिलाओं एवं आदिवासियों को लूट कर कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियां भरने वाला है। लूटेरी सरकारों के बजट से उत्पीड़ित–शोषित वर्गों की जनता की मूलभूत समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सरकारें सत्ताधारी शोषक शासक वर्गों की ही प्रतिनिधि हैं। इसलिए लुटेरी सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जुझारू, व्यापक, संगठित आन्दोलनों की जरूरत है। शोषक–शासक वर्गों की सत्ता को उखाड़ फेंककर उत्पीड़ित–शोषित वर्गों के नवजनवादी संयुक्त मोर्चे की सरकार की स्थापन के जरिए ही असली आजादी, स्वावलंबन पर आधारित असली विकास संभव है। इस दिशा में मजदूर, किसान, छात्र, युवा, बुद्धिजीवि, छोटे व्यापारी, दुकानदार, शिक्षक, कर्मचारी सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा।

★

सैद्धांतिक लेख

पार्टी के भीतर गलत विचारों को सुधारने के बारे में

–कॉमरेड माओ

(पिछले अंक का शेष)

निरपेक्ष समानतावाद के बारे में

लाल सेना में निरपेक्ष समानतावाद किसी समय बहुत गंभीर सीमा तक बढ़ गया था। इसकी कुछ मिसालें इस प्रकार हैं: घायल सिपाहियों को दवा की गंभीरता के अनुसार अलग–अलग भत्ते देने पर आपत्ति करना और सबको एक समान भत्ते देने की मांग करना, अफसरों का घोड़े चढ़ना काम के लिए जरूरी नहीं समझना और उसे असमानता का द्योतक समझना, सप्लाई के एकदम समान बंटवारे की मांग करना और खास हालत के लिहाज से सप्लाई का कुछ ज्यादा हिस्सा देने का विरोध करना, उमर या शारीरिक हालत को देखे बगैर, चावल ढ़ोने में सब के लिए एक जैसी मात्रा की मांग करना, रहने की जगह बांटते समय बराबर–बराबर जगह की मांग करना और हेडक्वार्टर द्वारा कुछ बड़ा मकान लेने पर उसकी भी निन्दा करना, फैटीग ड्यूटी में बराबर–बराबर काम मांगना और दूसरों के मुकाबले तनिक भी ज्यादा काम करने से इन्कार करना आदि यहां तक कि जब घायल दो हों और स्ट्रेचर सिर्फ एक ही हो, तो किसी एक को ले जाने के बजाय दोनों को छोड़ देना बेहतर समझना। निरपेक्ष समानतावाद, जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में बताया गया है, लाल सेना के अफसरों व सिपाहियों में अब भी गंभीर रूप में मौजूद है।

राजनीतिक मामलों में मौजूद अतिजनवाद की ही तरह निरपेक्ष समानतावाद भी दस्तकारी व लघु किसान अर्थव्यवस्था की ही उपज है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से एक तो राजनीतिक जीवन में प्रकट होता है और दूसरा भौतिक जीवन में।

इसे सुधारने के उपाय ये हैं :

यह बताना आवश्यक है कि पूंजीवाद के निर्मूलन से पहले निरपेक्ष समानतावाद केवल किसानों का और निम्न–पूंजीपति वर्ग के अन्य हिस्सों का भ्रममात्र ही होता है तथा समाजवाद के अन्तर्गत भी निरपेक्ष समानता कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि तब भी भौतिक चीजों का वितरण ''हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार, और हर एक को उसके काम अनुसार'' के उसूल तथा काम की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाएगा। कुल मिलाकर लाल सेना के सैनिकों में भौतिक चीजों का समान बंटवारा होना चाहिए, मसलन अफसरों और सिपाहियों को समान वेतन मिलना चाहिए क्योंकि संघर्ष की मौजूदा परिस्थितियों का यही तकाजा है। लेकिन अयुक्तिसंगत निरपेक्ष समानतावाद का विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि वह हमारे संघर्ष के लिए जरूरी नहीं है, इसके विपरीत वह हमारे संघर्ष में बाधक होता है।

मनोगतवाद के बारे में

कुछ पार्टी–सदस्यों में मनोगतवाद गम्भीर सीमा तक मौजूद है, जो राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करने और काम का निर्देशन करने में बहुत ही हानिकारक होता है। कारण, राजनीतिक परिस्थिति के मनोगतवादी विश्लेषण और काम के मनोगतवादी निर्देशन का लाजमी नतीजा या तो अवसरवाद होता है या मुहिमजोई। जहां तक पार्टी के अंदर की जाने वाली मनोगतवादी आलोचना, गैर–जिम्मेदाराना व निराधार बातचीत या पारस्परिक संदेह का सवाल है, इन सबसे अक्सर बेउसूली विवाद उठ खड़े होते हैं और पार्टी का संगठन टूटता है।

पार्टी के अंदर की जाने वाली आलोचना के बारे में एक बात का जिक्र और कर देना चाहिए और वह यह कि कुछ साथी अपनी आलोचना में बड़ी समस्याओं पर ध्यान न देकर व केवल छोटी–छोटी समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। वे नहीं समझते कि आलोचना का मुख्य कार्य राजनीतिक और संगठनात्मक गलतियां बताना है। जहां तक व्यक्तिगत खामियों का सवाल है, जब तक उनका सम्बन्ध राजनीतिक और संगठनात्मक गलतियों से न हो, तब तक जरूरत से ज्यादा नुक्ताचीनी करने और सम्बन्धित साथी को परेशानी में डालने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा एक बड़ा खतरा यह है कि यदि एक बार ऐसी आलोचना का सिलसिला चल गया, तो पार्टी सदस्यों का ध्यान मामूली खामियों पर ही पूरी तरह केन्द्रित हो जाएगा, हर कोई दब्बू बन जाएगा, जरूरत से ज्यादा सशंकित रहेगा और पार्टी के राजनीतिक कार्यों को भूल जाएगा।

इसे सुधारने का मुख्य उपाय है :

पार्टी सदस्यों को शिक्षित करना, जिससे कि उनके चिन्तन और पार्टी–जीवन को राजनीतिक और वैज्ञानिक सतह तक ऊँचा उठाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें चाहिए कि :

(1) राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करने और वर्ग–शक्तियों को आंकने में पार्टी सदस्यों को मनोगतवादी विश्लेषण और मूल्यांकन के बदले मार्क्सवादी–लेनिनवादी तरीका लागू करना सिखाएं, (2) पार्टी सदस्यों का ध्यान सामाजिक और आर्थिक छानबीन और अध्ययन की ओर खींचे जिसके आधार पर संघर्ष की कार्यनीति और काम के तरीकें निर्धारित किए जाएँ तथा यह समझने में साथियों की मदद करें कि वास्तविक परिस्थितियों की छानबीन किए बिना हवाई कल्पना और मुहिमजोई के गढ्ढे में जा गिरेंगे, तथा (3) पार्टी के अन्दर की जाने वाली आलोचना में मनोगतवाद, स्वेच्छाचारिता और घटिया दर्जे की नुक्ताचीनी से सावधान रहें, जो कुछ कहा जाए, वह तथ्यों पर

आधारित हो और आलोचनाओं का केन्द्र–बिन्दू राजनीति को बनाया जाए।

व्यक्तिवाद के बारे में

लाल सेना के पार्टी–संगठन में व्यक्तिवादी प्रवृति इन रूपों में प्रकट होती है :

(1) बदला लेने की मनोवृत्ति। कुछ साथी पार्टी के अंदर किसी सैनिक साथी द्वारा आलोचना किए जाने पर उससे पार्टी के बाहर बदला लेने के अवसर ढूंढ़ते हैं। मारपीट या गाली–गलौज बदला लेने का एक तरीका है। वे पार्टी के अन्दर भी बदला लेने का मौका ढूंढते हैं। ''तुमने मेरी इस मीटिंग में आलोचना की है, इसलिए मैं दूसरी मीटिंग में तुम्हारे दोष दिखाकर तुमसे बदला लूंगा'' बदला लेने की इस मनोवृत्ति का एक मात्र कारण है व्यक्तिगत बातों को प्रस्थान–बिन्दु बनाकर वर्ग के हितों और समूची पार्टी के हितों की अवहेलना करना। इस मनोवृत्ति का निशाना शत्रु–वर्ग नहीं होते, बल्कि अपनी ही पांतों के व्यक्ति होते हैं। यह एक ऐसा घुन है जो संगठन की और उसकी जुझारू क्षमता को कमजोर बना देता है।

(2) संकीर्ण ग्रुपवाद। कुछ साथी केवल अपने छोटे से ग्रुप के हितों को ही ध्यान में रखते हैं और आम हितों को नजरअन्दाज कर देते हैं, हालांकि ऊपर से देखने पर तो यह व्यक्तिगत हितों की तलाश नहीं जान पड़ती, लेकिन वास्तव में इसमें एक बहुत ही संकीर्ण किस्म का व्यक्तिवाद निहित होता है। इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत ही विनाशकारी और विघटनकारी होता है। लाल सेना में संकीर्ण ग्रुपवादी मनोवृत्ति का बराबर बोलबाला रहा है। हालांकि आलोचना करने से अब स्थिति उतनी गम्भीर नहीं रह गई है, फिर भी उसके अवशेष अब तक मौजूद हैं और उन्हें दूर करने के लिए और भी कोशिश करना जरूरी है।

(3) मुलाजिमों जैसी मनोवृत्ति। कुछ साथी यह महसूस नहीं करते कि पार्टी और लाल सेना, जिनके वे सदस्य हैं ये दोनों ही क्रांतिकारी काम पूरा करने के साधन हैं। वे यह नहीं समझते कि वे खुद क्रांति के निर्माता हैं, बल्कि यह महसूस करते हैं कि वे केवल किसी वरिष्ठ अफसर के प्रति ही उत्तरदायी हैं, क्रांति के प्रति नहीं। क्रांति के प्रति यह निष्क्रिय, मुलाजिमों जैसी मनोवृत्ति भी व्यक्तिवाद का ही एक रूप है। इससे यह मालूम हो जाता है कि क्रांति के बिना शर्त काम करने वाले सक्रिय तत्वों की तादाद् इतनी कम क्यों है। अगर मुलाजिमों जैसी मनोवृत्ति दूर न की गई तो सक्रिय तत्वों की संख्या नहीं बढ़ेगी और क्रांति का भारी बोझ इने–गिने लोगों के कंधों पर ही रहेगा जिससे संघर्ष को गहरा धक्का लगेगा।

(4) ऐशो–आराम की मनोवृत्ति। लाल सेना में ऐसे लोग भी काफी हैं जिनका व्यक्तिवाद ऐशो–आराम की मनोवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। वे हमेशा इस बात की आशा लगाए रहते हैं कि उनकी युनिट बड़े शहरों में कूच करेगी। वे काम करने के लिये नहीं, बल्कि ऐशो–आराम करने के लिए बड़े शहरों में जाना चाहते हैं। उन्हें लाल इलाकों में, जहां का जीवन कठिन है, काम करना कतई पसन्द नहीं है।

(5) निष्क्रियता। कुछ साथी, जब कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध जान पड़ती है, निष्क्रिय हो जाते हैं और काम करना बन्द कर देते हैं। इसका मुख्य कारण राजनीतिक शिक्षा की कमी है, हालांकि कभी–कभी इसका कारण नेतृत्व द्वारा अनुचित ढ़ंग से काम बांटना या अनुचित ढ़ंग के अनुशासन लागू करना भी होता है।

(6) सेना को छोड़ देने की इच्छा। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो लाल सेना छोड़कर स्थानीय काम करना चाहते हैं। इसका कारण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत नहीं बल्कि यह भी है :

(1) लाल सेना में जीवन की भौतिक कठिनाइयां,

(2) लम्बे संघर्ष के बाद थकान का एहसास, और

(3) नेतृत्व द्वारा अनुचित ढंग से कामकाज चलाना, अनुचित ढंग से काम बांटना या अनुचित ढंग से अनुशासन लागू करना।

इसे सुधारने का मुख्य उपाय यह है कि विचारधारा के क्षेत्र में व्यक्तिवाद को दूर करने के लिए राजनीतिक शिक्षा का काम जोरों से बढ़ाया जाय। इसके अलावा, उचित ढ़ंग से कामकाज चलाना चाहिए, उचित ढ़ंग से काम बांटना चहिए और उचित ढ़ंग से अनुशासन लागू करना चाहिए। साथ ही भौतिक परिस्थिति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए लाल सेना के भौतिक जीवन को सुधारने के उपाय खोजने चाहिए तथा आराम और बहाली का जो भी मौका मिले उससे फायदा उठाना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा का काम करते समय हमें यह जरूर बता देना चाहिए कि सामाजिक उत्पति की दृष्टि से व्यक्तिवाद पार्टी के भीतर निम्न–पूंजीवादी और पूंजीवादी विचारों का ही प्रतिबिम्ब है।

घुमन्तू विद्रोहियों की विचारधारा के बारे में

लाल सेना में घुमन्तू विद्रोहियों की राजनीतिक विचारधारा इसलिए पैदा होती है क्योंकि उसमें खानाबदोश लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद है और चीन में, खास तौर से उसके दक्षिणी प्रान्तो में खानाबदोश लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

यह विचारधारा इन रूपों में प्रकट होती है:

(1) कुछ लोग आधार–क्षेत्रों और जनता की राजनीतिक सत्ता के कठिन कार्य करने में और इस तरह अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में आना–कानी करते हैं उसे केवल चलती–फिरती छापामार कार्यवाही के तरिके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

(2) कुछ लोग लाल सेना को बढ़ाने के लिए स्थानीय लाल रक्षक दलों और स्थानीय लाल सेना को बढ़ाने और इस प्रकार नियमित लाल सेना को बढ़ाने की कार्यदिशा

अपनाने के बजाय ''आदमी भाड़े पर रखने और घोड़े खरीदने'' तथा ''भगोडों की भर्ती करने और बागियों को शामिल करने'' की कार्यदिशा अपनाते हैं।

(3) कुछ लोग आम जनता के साथ मिलकर कठोर संघर्ष चलाने का धीरज नहीं रखते और केवल बड़े शहरों में जाकर शाहखर्ची से खाने–पीने की आशा लगाए रहते हैं। घुमन्तू विद्रोहियों की विचारधारा के ये तमाम रूप लाल सेना के समुचित कर्तव्य में भारी रुकावट डालते हैं। इसलिए इस विचारधारा का निर्मूलन करना दरअसल लाल सेना के पार्टी–संगठन के भीतर होने वाले विचारधारात्मक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह समझ लेना होगा कि हवाङ छाओ[1] या ली छवाङ[2] जैसी घुमन्तू विद्रोही की मनोवृत्ति को आज की हालत में हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती।

इसे सुधारने के उपाय इस प्रकार हैं :

(1) राजनीतिक शिक्षा का काम तेजी से चलाओ, गलत विचारों की आलोचना करो और घुमन्तू विद्रोहियों की मनोवृत्ति का निर्मूलन कर दो।

(2) लाल सेना के बुनियादी दस्तों और नए भर्ती किए गए बन्दी सैनिकों के बीच आवारागर्दी के दृष्टिकोण के खिलाफ शिक्षा का काम बढ़ाओ।

(3) लाल सेना की वर्ग–संरचना बदलने के लिए संघर्ष के अनुभव से सम्पन्न सक्रिय मजदूरों और किसानों को उसकी पांतों में लेने की कोशिश करो।

(4) जुझारू मजदूरों और किसानों के जनसमुदाय के बीच से लाल सेना के नए दस्तें बनाओ।

मुहिमजोई के अवशेषों के बारे में

लाल सेना के पार्टी–संगठन के खिलाफ पहले ही संघर्ष चला चुके हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसलिए लाल सेना में मुहिमजोई की विचारधारा के अवशेष अब भी बने हुए हैं। वे इन रूपों में प्रकट होते हैं।

(1) मनोगत और वस्तुगत परिस्थितियों का ध्यान रखे बिना आंख मूंदकर काम करना,

(2) शहरों के लिए पार्टी की नीतियों को अपर्याप्त रूप से और पूरा जोर लगाए बिना अमल में लाना,

(3) शिथिल फौजी अनुशासन, खास कर हारने के वक्त,

(4) कुछ दस्तों द्वारा घरों में आग लगाने का कुकर्म किया जाना एवं

(5) भगोड़ों का गोली मार देने की व्यवस्था और शारीरिक दंड देने की व्यवस्था। इन सबों से ही मुहिमजोई की प्रवृत्ति प्रकट होती है। सामाजिक उत्पत्ति की दृष्टि से मुहिमजोई का जन्म आवारा–सर्वहारा विचार और निम्न–पूंजीवादी विचार के मेल से होता है।

इसे सुधारने के उपाय इस प्रकार हैं :

(1) विचारधारा की दृष्टी से मुहिमजोई को नेस्तनाबूद कर दो।

(2) नियम–विनियमों और नीतियों के जरिए मुहिमजोई के व्यवहार का अन्त कर दो।

नोट

1. हवाङ छाओ नामक व्यक्ति थाङ वंश के अंतिम दिनों में किसान विद्रोहों का नेता था। 875 ईसवीं में हवाङ छाओ ने लोगों को इकठ्ठा करके विद्रोह कर दिया। हवाङ छाओ के विद्रोही दस्ते ने शानतुङ से निकलकर दो बार अभियान किया। अन्त में उसने शाही राजधानी छङआन पर कब्जा करके सम्राट छी के नाम से छाङ आन में गद्दी पर बैठ गया। उसके सेनानायक चू वन ने थाङ वंश की फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। शाथो कबीले के सरदार ली ख–युङ की फौज के हमलों से मजबूर होकर हवाङ छाओ को छाङ आन छोडना पड़ा और शानतुङ में पराजय का सामना करने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। हवाङ छाओ द्वारा दस वर्ष तक चलाया गया युद्ध चीन के इतिहास में एक अत्यंत प्रसिद्ध किसान युद्ध था। चीनी राजवंशो के इतिहासकारों ने लिखा है कि ''जो लोग भारी करों और तरह–तरह की वसूली से पीडित थे, वे सभी उसके चारों ओर गोलबन्द हो गए।'' चूंकि वह केवल सरल रूप से घुमन्तू युद्ध ही चलाता रहा और उसके अपेक्षाकृत दृढ़ आधार–क्षेत्र स्थापित नहीं किए, इसलिए उसकी फौज 'घुमन्तू विद्रोही दल' कहलाती थी।

2. ली छवाङ शेनशी प्रान्त के मीचि नामक स्थान के राजा थे। मिङ वंश के अन्त में एक किसान विद्रोह का नेता था। 1628 ईसवीं में उत्तरी शेनशी के किसानों ने विद्रोह छेड़ दिया। ली उस विद्रोही दस्ते में शामिल हो गया जो काओ इङ–श्याङ के नेतृत्व में था। उसने हनान में और आनहेवई में तथा फिर शेनशी में मुहिमें चलाई। 1636 में काओ की मृत्यु होने के बाद ली ने उसका पद सम्भाल लिया और राजा छवाङ की उपाधि धारण कर ली। जनसुदाय में उसका मुख्य नारा था, ''राजा छवाङ का साथ दो, गल्ला टैक्स मत दो।'' अपने सैनिको में अनुशासन कायम रखने के लिए उसने यह नारा दिया था, ''किसी की हत्या का मतलब होगा मेरे बाप की हत्या, किसी के साथ बलात्कार का अर्थ होगा मेरी मां के साथ बलात्कार।'' इस तरह उसने आम जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया और उसका आन्दोलन किसान विद्रोहों की मुख्य धारा बनकर समूचे देश में फैल गया। लेकिन उसने भी दृढ आधार–क्षेत्र कायम नहीं किए और जगह–जगह घुमता रहा। उसने हुपे और हनान में मुहिमें चलाई और हुपे प्रान्त के याङयाङ पर कब्जा कर लिया। फिर हनान होकर शेनशी प्रान्त में शीआन पर कब्जा कर लिया। अन्त में 1644 ईसवीं में उसने शानशी से होकर पेकिङ पर अधिकार कर लिया। कुछ ही दिन बाद उसे मिङ वंश के एक सेनानायक ऊ–सान–क्वेई से पराजित होना पड़ा था।

★

आह्वान

28 जुलाई से 3 अगस्त तक गांव–गांव में शहीदी सप्ताह मनायेंगे।
वीर शहीदों के खून से सने सुर्ख लाल झंडे को ऊंचा उठायेंगे।
शहीद योद्धाओं के सपनों को साकार करने
आखिरी सांस तक उनकी राह में संघर्ष करेंगे।

दण्डकारण्य की पार्टी कतारों, पीएलजीए के कमांडरों व लाल योद्धाओं एवं प्यारे लोगों!

भारत की क्रांति के महान नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक एवं प्यारे शहीद कामरेड चारु मजुमदार एवं कामरेड कन्हाई चटर्जी के दर्शाये दीर्घकालीन जन युद्ध के रास्ते पर अमल करते हुए भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने नक्सलबाड़ी से लेकर आज तक दस हजार से भी ज्यादा क्रांतिकारियों व क्रांतिकारी जनता ने पीड़ित जनता के मुक्ति संग्राम में अपना गरम खून बहाया। पिछले 28 जुलाई, 2013 से लेकर इस साल भर में देश के विभिन्न संघर्ष इलाकों– दण्डकारण्य, बिहार–झारखंड, उत्तर तेलंगाना, एओबी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असोम आदि में सौ से ज्यादा हमारे प्रिय कामरेडों ने सर्वोच्च कुरबानी दी। जबकि सिर्फ दण्डकारण्य में ही इस दौरान 40 कामरेडों ने अपनी जानें कुरबान की। मजदूर वर्ग के इन उत्तम संतानों में पार्टी नेतृत्व से लेकर पीएलजीए के कमांडरों व लाल योद्धाओं सहित क्रांतिकारी जनता भी शामिल हैं। आगामी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होने वाले शहीदी सप्ताह के दौरान इन तमाम कामरेडों को सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनकी यादों को ताजा व साझा करते हुए लक्ष्य को हासिल करने तक उनकी कुरबानियों की राह पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे।

कामरेड चारू मजुमदार　　कामरेड कन्हाई चटर्जी

देश में मजबूती से अपनी जड़े जमाये संशोधनवाद पर जबर्दस्त प्रहार करके भारत की नवजनवादी क्रांति की सही दिशा तय करने वाले कॉमरेड चारू मजुमदार एवं कॉमरेड कन्हाई चटर्जी को सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।

भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी की पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुशील राय उर्फ बरुण दा जिनकी उम्र 78 वर्ष थी, की लंबी अस्वस्थता के बाद 18 जून, 2014 को शहादत हुई। 21 सितंबर, 2004 को भाकपा (माओवादी) के गठन के कुछ ही समय बाद वे कोलकाता से गिरफ्तार हुए थे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी। दुश्मन के दमनात्मक हथकंडों व जेल में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों के चलते उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। दुश्मन के चंगुल में रहते हुए भी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद पर अटूट विश्वास के साथ क्रांतिकारी जनयुद्ध के झण्डे को ऊंचा उठाये रखने वाले प्रियतम नेता, वरिष्ठ व अनुभवी क्रांतिकारी योद्धा कॉमरेड सुशील राय को शीश झुकाकर विनम्रतापूर्वक जोहार अर्पित करेंगे।

नक्सलबाड़ी के समय से लेकर अपनी आखिरी सांस तक दीर्घकालीन जनयुद्ध की दिशा को ऊंचा उठाये रखने वाले, संशोधनवाद के खिलाफ अविराम संघर्ष करते हुए भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी की स्थापना में महत्वपूर्ण व नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाले अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्यारे कॉमरेड शेख अब्दुल रऊफ जिनकी गंभीर अस्वस्थता के कारण 89 वर्ष की उम्र में 9 फरवरी को शहादत हुई, को इस मौके पर सिर झुकाकर श्रद्धपूर्वक लाल सलाम् पेश करेंगे। पिछले 1 मई को भाकपा (माओवादी) एवं भाकपा (मा–ले) नक्सलबाड़ी के विलय की घोषणा का उल्लेख यहां लाजिमी होगा।

1946 के ऐतिहासिक तेभागा किसान आन्दोलन से लेकर आखिरी तक किसी न किसी तरह भारत के कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी आन्दोलन के साथ जुड़े रहे अनुभवी, वयोवृद्ध एवं प्रिय कॉमरेड सुनीति कुमार घोष का विगत 11 मई को 96 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे आखिरी सांस तक हमारी पार्टी के दोस्त, शुभचिंतक व समर्थक बने रहे। बुनियादी तौर पर नक्सलबाड़ी की राजनीतिक लाइन को आखिरी दम तक ऊंचा उठाये रखने वाले आदरणीय क्रांतिकारी बुद्धिजीवि कॉमरेड सुनीति कुमार घोष को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

वीर शहीदों की कुरबानियों के जरिए ही क्रांतिकारी आन्दोलन ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की।

मुठ्ठीभर लोगों के द्वारा प्रांरभ क्रांतिकारी आन्दोलन आज देश के कई राज्यों में फैल गया है। दण्डकारण्य, बिहार–झारखंड समेत कई संघर्ष इलाकों में जोतने वालों को जमीन मिल गयी। सैकड़ों गांवों में दुष्ट मुखियाओं का प्रभुत्व खत्म हो गया। वन विभाग के उत्पीड़न का अंत हो गया। पंचायत स्तर से लेकर डिविजन स्तर तक जन राज सत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनताना सरकारों का गठन होकर जनता के हाथों सत्ता आ गयी है। जन संघर्षों व जनयुद्ध के जरिए जनता जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को कॉरपोरेट कंपनियों के कब्जे में जाने से बचा पायी।

हमारे वीर शहीदों की कुरबानियों के बगैर हम इन उपलब्धियों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शोषक–शासक वर्गों के द्वारा देश की संघर्षरत शोषित व उत्पीड़ित जनता, उसका नेतृत्व करने वाली पार्टी, उसकी सेना पीएलजीए एवं जन राज सत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनताना सरकारों पर अन्यायपूर्ण युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट चलाया जा रहा है। साम्राज्यवादियों खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों की देखरेख में यह फासीवादी चौतरफा सैनिक हमला दिन–ब–दिन व्यापक व तेज होता जा रहा है। हाल ही में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इसे और तेज करने की योजना पर अमल कर रही है। आज साम्राज्यवाद का आर्थिक व वित्तीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। उससे बाहर आने के लिए वह पिछड़े देशों के संसाधनों को लूटने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। हमारे देश के दलाल शासक पहले से ही साम्राज्यवादियों के हितों के अनुरूप देश की नीतियां बदल कर उनके सामने नतमस्तक हो गये हैं। हमारे देश के छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र बिहार–झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में अकूत प्राकृतिक संपदाएं हैं। शासक वर्गों के द्वारा इन संपदाओं की लूट में बाधा बने क्रांतिकारी आन्दोलन का सफाया अब शोषक–शासकों की पहली प्राथमिकता बन गयी है। इसीलिए जनता पर शोषकों ने युद्ध थोप दिया है। दण्डकारण्य के चारगांव, रावघाट, कुव्वेमारी, बुधियारी माड़, आमदाय, तुलाड् एवं महाराष्ट्र के कोरची लौह प्रकल्प, दमकोडी, सुरजागढ़ आदि लौह अयस्क व बाक्साइट खदानों को शुरू करने के प्रयास तेज हो रहे हैं। टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, टीपीजी आदि कॉरपोरेट कंपनियां अपने वृहद् उद्योगों की स्थापना के लिए एड़ी–चोटी एक कर रही हैं। कारखानों के लिए कच्चामाल की आपूर्ति एवं वहां से बाजार तक माल ढुलाई को सस्ता बनाने एवं अपनी लूट व शोषण के खिलाफ संघर्षरत जनता का दमन करने सशस्त्र बलों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए ही, जनता के जबर्दस्त विरोध के बावजूद लुटेरी सरकारें सशस्त्र बलों की संगीनों के साये में रेल्वे लाइन को पूरा करने पर तुली हुई हैं। चारों तरफ अर्ध–सैनिक बलों के अड्डे बनाकर रावघाट खदान को लूटकर ले जाने की षड़यंत्र चल रही है। बड़े कारखानों को बिजली व पानी की आपूर्ति करने बड़े बांधों के निर्माण की कोशिशें भी तेज हो रही है। बड़े बांधों, बड़े खदानों व बड़े उद्योगों के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में यहां लंबे समय से जन संघर्ष जारी हैं। रावघाट खदान को बचाने के लिए शहीद कामरेड सुकदेव के नेतृत्व में प्रारंभ संघर्ष आज भी जारी है। इन संघर्षों के फलस्वरूप ही कॉरपोरेट कंपनियों की योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। क्रांतिकारी आन्दोलन के द्वारा उत्पन्न चेतना का ही नतीजा है, बैलाडीला प्रदूषण विरोधी जन आन्दोलन। आम जनता की लूट, शोषण, विस्थापन व विनाश पर आधारित शोषक–शासकों के विकास के नमूने को लात मारकर स्वावलंबन पर आधारित असली विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए यहां की संघर्षरत जनता अपनी राजनीतिक सत्ता के अंग–क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत कर रही है एवं उनका विस्तार कर रही है। शोषणमूलक सत्ता को उखाड़ फेंकने के तहत जारी इन संघर्षों व संघर्षरत जनता को कुचलने, जनता का नेतृत्व करने वाली पार्टी, पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकारों का सफाया करने के लिए शोषक–शासक वर्गों की सरकारें एड़ी–चोटी का जोर लगा रही हैं।

विगत साल भर के दमन में दसियों कामरेड शहीद हो गये हैं। इनमें से कुछेक कामरेडों की दुश्मन ने फर्जी मुठभेड़ों में क्रूरतापूर्वक हत्या की। जबकि कुछ और कामरेडों ने दुश्मन के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने प्राणों को न्योछावर किया। अस्वस्थता और दुर्घटनाओं के चलते भी कुछ कामरेड्स शहीद हुए हैं।

17 फरवरी को बेतकाठी गांव के पास उत्तर गढ़चिरोली–गोंदिया डिविजन के सात कॉमरेडों की दुश्मन ने षड्यंत्र रचकर बर्बरतापूर्वक हत्या की। इनमें डीवीसीएम कॉमरेड लालसू, एसी स्तर के कॉमरेड्स सुनिल, पुन्नी, वीरू, नवीन, श्यामको एवं पीपीसी सदस्य कॉमरेड राजेश शामिल हैं। ये कॉमरेड्स दुश्मन के विश्वासघाती दांव–पेंच

के शिकार होकर शहीद हुए हैं। इनके अलावा एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार की अध्यक्षा कॉमरेड धन्नी, कॉमरेड रामसु (पार्टी सदस्य), कॉमरेड रीता (पीपीसीएम), कॉमरेड सरिता (पार्टी सदस्य) दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गयीं। विस्फोटक दुर्घटना में कॉ. माधुरी शहीद हो गई।

तेलंगाना, दक्षिण बस्तर की सरहद में दुश्मन के खिलाफ साहस के साथ संघर्ष करते हुए खम्मम जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड नरेश, एवं मिलिशिया सदस्य कॉमरेड रामू शहीद हुए।

दक्षिण बस्तर डिविजन में दुश्मन का प्रतिरोध करते हुए कॉमरेड अपका शांति, एरिया मिलिशिया कमांडर–इन–चीफ कॉमरेड माडवी सोमाल (पीएम), कॉमरेड मूसाकि अड़माल (पीएलजीए सदस्य), कॉमरेड जोगाल (मिलिशिया), कॉमरेड ककेम मुन्नी (मिलिशिया), पीएल–4 की सदस्या कॉमरेड मुसाकि पायके शहीद हुईं।

पश्चिम बस्तर डिविजन में दुश्मन के साथ हुई मुठभेड़ में कॉमरेड ताति सन्नू (कंपनी–2 का सदस्य) एवं कॉमरेड पामुला चंदू (गार्ड) वीरगति को प्राप्त हुए। गंगालूर की साहसिक सैनिक कार्रवाई में कॉमरेड पोट्टामि बदरू (मिलिशिया) शहीद हो गये। दुश्मन के अभियान का डटकर मुकाबला करते हुए जन मिलिशिया कमांडर कॉमरेड फागू ने अपनी जान की कुरबानी दी। पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाईयों के दौरान दुर्घटनावश कॉमरेड राजेश (मिलिशिया) ने शहादत को पाया। विस्फोटक दुर्घटना में कॉ. सुरेश शहीद हो गये।

पूर्व बस्तर में दुश्मन के हमलों में सीनियर एसीएम कॉमरेड दरबार मंडावी, कॉमरेड ज्योति (गार्ड), कामरेड जानो (मिलिशिया) शहीद हुईं। कॉमरेड रोण्डा (गार्ड) बरगढ़ जिले के गंधमर्दन पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में शहीद हो गये।

विगत साल भर में फर्जी मुठभेड़ों में कई कॉमरेडों ने अपनी जानें कुरबान की। पूर्व बस्तर के डिविजन कार्रवाई दस्ते के कॉमरेड विजय, पश्चिम बस्तर डिविजन के नेशनल पार्क एरिया के गरतुल गांव के पास कॉमरेड नवीन, कॉमरेड मासे, कॉमरेड सन्नु की बर्बर यातनाएं देने के बाद हत्या की गयी। कॉमरेड मासे के साथ दुष्कर्म किया गया था। गंगालूर एरिया के तोड़का गांव के ग्रामीण आदिवासी किसान ताति बुद्धू, ईसुलनार गांव के कुरसम लच्छू (मिलिशिया) को पकड़कर बाद में उनकी हत्या की गयी। दक्षिण बस्तर में आन्ध्रप्रदेश–छत्तीसगढ़ राज्यों के संयुक्त बलों के ऑपरेशनों के दौरान दुश्मन की अंधाधुंध फायरिंग में मड़काम उंगाल एवं काका धर्माल शहीद हो गये। माड़ डिविजन के करका जंगल में तीन साधारण आदिवासी किसानों–करकानार गांव के 65 साल के लकमो मंडावी, 23 साल के विज्जोन मंडावी, गोटा जमरी के रामसाई कौडो एवं उत्तर बस्तर डिविजन के कोयलीबेड़ा एरिया के आमाखड्डा गांव के दो आदिवासी किसान तुलसीराम दर्रो एवं सोमारू को पकड़कर गोली मार दी गयी।

करीबन तीन दशक तक क्रांतिकारी आन्दोलन में दृढ़तापूर्वक काम करने वाली आदर्शवान वरिष्ठ महिला कम्युनिस्ट योद्धा कॉमरेड गज्जला सरोजा (शहीदा, अमरा) केंसर बीमारी की वजह से 11 दिसंबर को शहीद हुईं। दक्षिण बस्तर के जेगुरगुण्डा एलजीएस कमांडर कॉमरेड कुर्सम बोज्जाल, एवं एसजेडसी स्टाफ कॉमरेड राकेश (मोनु) सांप के डंसने से शहीद हो गये। कॉमरेड अमिता की दुखद मौत हुई। गिरफ्तार होकर जेल में सजा काट रहे कॉमरेड रामलाल जगदलपुर जेल में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों के चलते गंभीर अस्वस्थता के शिकार होकर जेल अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही की वजह से शहीद हो गये।

आन्ध्रप्रदेश राज्य में 4 जुलाई, 2013 को वरिष्ठ माओवादी नेता कॉमरेड गण्टि प्रसादम की जघन्य हत्या करने वाले शासक वर्गों ने 25 दिसंबर को पृथक जनवादी तेलंगाना राज्य आन्दोलन के नेता कॉमरेड आकुला भूमय्या की हत्या करवाई।

एओबी के क्रांतिकारी आन्दोलन के कई साथी इस साल भर में शहीद हुए हैं। खासकर लंबे समय से क्रांतिकारी आन्दोलन को अपनी सेवाएं देते आये वरिष्ठ नेता कॉमरेड मंगन्ना (डीवीसीएम), कॉमरेड डुंब्री (डीवीसीएम) को दुश्मन ने एक साजिश के तहत पकड़कर उनकी हत्या की। कॉमरेड शिरीषा (एसीएम) की एक दुर्घटना में शहादत हुई।

शासक वर्ग दमन के जरिए आन्दोलनों को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया के क्रांतिकारी आन्दोलनों के इतिहास ने इसे कई बार साबित कर दिया है कि कोई भी प्रतिक्रियावादी ताकत जनान्दोलनों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती है और क्रांतिकारी जनान्दोलनों की जीत को कभी नहीं रोक सकती है। जब तक दुनिया में शोषण एवं उत्पीड़न जारी रहेंगे तब तक जन विद्रोह व जन संघर्ष उठते रहेंगे। तमाम अड़चनों को लांघते हुए अंतिम जीत की ओर अग्रसर होंगे। यह जन युद्ध है। सैकड़ों करोड़ पीड़ित लोग जिस दिन एक हो जायेंगे, मुठ्ठीभर शोषकों को दुनिया की कोई भी प्रतिक्रियावादी सेना बचा नहीं सकती है। अत्याधुनिक हथियार चाहे जितने भी हों, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। अंतिम जीत जनता की ही होगी। जनता ही इतिहास की निर्माता है। जनता पर इस अटूट विश्वास के साथ ही कई योद्धा जनयुद्ध में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अनगिनत कुरबानियां दे रहे हैं। उनकी कुरबानियों की विरासत को दृढ़ता से अपनाना होगा। उस विरासत को और सुसंपन्न करना होगा। शहीद योद्धाओं के आदर्शों पर बेहिचक अमल करना होगा। उनके सपनों को साकार करने एवं उनके अधूरे आशयों को पूरा करने हमें अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। इसके उल्टे, अस्थायी नुक्सानों से घबराकर

नक्सलबाड़ी की पीढ़ी के वयोवृद्ध, अनुभवी एवं प्रिय कॉमरेड सुनीति कुमार घोष को लाल–लाल सलाम्

पश्चिम बंगाल के असनसोल में विगत 11 मई, 2014 को उम्र के 96 साल के पड़ाव में कॉमरेड् सुनीति कुमार घोष (1918–2014) ने आखिरी सांस ली। उन्होंने एक लंबा व उदाहरणीय क्रांतिकारी जीवन जिया। एक युवा क्रांतिकारी कार्यकर्ता की हैसियत से वे 1946 के ऐतिहासिक तेभागा किसान आन्दोलन में शामिल हुए। तब से लेकर आखिरी तक वे किसी न किसी तरह भारत के कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी आन्दोलन के साथ जुड़े रहे। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन के प्रमुख मोड़ों पर संशोधनवाद एवं नव संशोधनवाद के खिलाफ कटु आंतरिक संघर्षों में वे दृढ़तापूर्वक शामिल हुए। भारत की राजनीतिक धरातल को झकझोर करने वाले नक्सलबाड़ी किसान सशस्त्र संघर्ष के परचम को ऊंचा उठाकर भाकपा (मा–ले) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। नक्सलबाड़ी संघर्ष के धक्का खाने के बाद हालांकि उन्होंने क्रांतिकारी आन्दोलन के निर्माण की प्रक्रिया से अपने आपको अलग किया था, लेकिन वे आखिरी सांस तक भाकपा (माओवादी) के दोस्त, शुभचिंतक व समर्थक बने रहे। हमारे देश में मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के लाल झंडे को ऊंचा उठाए रखने वाली अन्य सर्वहारा पार्टियों व शक्तियों का भी वे समर्थक, हितैषी बने रहे। नये व पुराने किस्म के संशोधनवाद के खिलाफ उनके द्वारा जीवन पर्यंत किये गये संघर्ष के लिए कॉमरेड घोष याद किये जाएंगे। उनके कई पुराने सहयोगियों के गद्दार, संशोधनवादी एवं अवसरवादी बन जाने के बावजूद कॉमरेड घोष ने बुनियादी तौर पर नक्सलबाड़ी की राजनीतिक लाइन को ऊंचा उठाये रखा। उन्होंने इस काम को आखिरी दम तक जारी रखा जिसके लिए वे क्रांतिकारियों के हमेशा पसंदीदा व आदरणीय बने रहेंगे। इस अनुभवी क्रांतिकारी को प्रभात अपने समस्त पाठकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारजन एवं बंधु–मित्रों के प्रति गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करता है।

कॉमरेड सुनीति घोष 1946 के ऐतिहासिक तेभागा किसान सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। उस समय किसान आन्दोलन का नेतृत्व कर रही भाकपा के आह्वान पर शहरी छात्र एवं युवा बड़ी संख्या में किसानों को संगठित करने देहातों की ओर निकल पड़े थे। 28 साल के युवा कम्युनिस्ट कॉमरेड घोष ने आन्दोलन में शामिल होने ग्रामीण इलाके में कदम रखा था। वर्ग संघर्ष के तीव्र होते ही दुश्मन के सशस्त्र दमन का मुकाबला करने किसानों ने हथियारों की मांग की थी। लेकिन भाकपा के केंद्रीय नेतृत्व संशोधनवाद से ग्रसित था और किसानों को हथियारबंद करने का उसके पास कोई कार्यक्रम न था और न ही उसके लिए मानसिक तैयारी थी। इसका

उन्हें स्थायी समझकर दिग्भ्रमित होना एवं जनता पर विश्वास खोकर, कम्युनिस्ट मूल्यों व आदर्शों को तिलांजलि देकर, कुरबानी से डरकर दुश्मन के सामने घुटने टेकने का मतलब है, पीड़ित जनता के साथ गद्दारी। आत्म समर्पण से तीखी नफरत करने, आत्म सम्मान के साथ जीने व उसके लिए लड़ने, वीर शहीदों के खून से रंगे सुर्ख लाल झंडे को हमेशा व आखिरी दम तक ऊंचा उठाये रखने का शपथ लेंगे। शहीदों के स्मृति सप्ताह के दौरान गांव–गांव में शहीदों की याद में स्मारक चिन्हों का निर्माण करेंगे। सभा–सम्मेलनों का आयोजन करके उनकी कुरबानियों, वीरता एवं उनके आदर्शों का स्मरण करेंगे। उनको अपनायेंगे। उन पर अमल करेंगे। शहीदों के रास्ते में आगे कदम बढ़ायेंगे। हमारे प्यारे शहीद योद्धाओं को दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी।

- **कॉमरेड चारू मजुमदार एवं कॉमरेड कन्हाई चटर्जी को लाल–लाल सलाम्।**
- **क्रांतिकारी जनयुद्ध में जान कुरबान करने वाले तमाम वीर शहीदों को लाल–लाल सलाम्।**
- **दुश्मन की विश्वासघाती एलआईसी युद्ध नीति का मुकाबला करते हुए सभी स्तरों के पार्टी नेतृत्व की रक्षा करेंगे। नुकसानों को कम करेंगे।**
- **जनयुद्ध को तेज करके ऑपरेशन ग्रीनहंट को हरायेंगे।**
- **भारत की नवजनवादी क्रांति–जिंदाबाद**

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ...
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

नतीजा यह हुआ कि शासकों ने किसान संघर्ष को खून की नदी में डुबोया। इस आन्दोलन के दौरान सुनीति कुमार घोष जैसे जमीनी नेतृत्व व जनता को वर्ग संघर्ष के अमूल्य व आचरणात्मक अनुभव प्राप्त हुए। इन अनुभवों ने देश में क्रांतिकारी किसान संघर्षों के अगले दौर के लिए जमीन तैयार की। साथ ही तेभागा और तेलंगाना के किसान सशस्त्र संघर्षों के अनुभवों ने कॉमरेड घोष एवं अन्य क्रांतिकारियों को संशोधनवादी गद्दारी के खतरे एवं अवसरवाद के खिलाफ समझौता विहीन व दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के प्रति सावधान किया था। तेलंगाना, तेभागा के अलावा उसके बाद के सशस्त्र किसान उभारों ने भाकपा की संशोधनवादी लाइन को बेनकाब कर दिया। 1956 में आयोजित पालाघाट कांग्रेस में सीपीआई ने खुलाकर संशोधनवादी लाइन अपनाते हुए सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसयू) की संशोधनवादी 20वीं कांग्रेस के द्वारा कॉमरेड स्तालिन एवं मार्क्सवाद–लेनिनवाद पर किये गये हमले का समर्थन किया। इसका कड़ा विरोध करते हुए कइयों ने पार्टी छोड़ी या सक्रिय राजनीति से दूर हो गये। कॉमरेड सुनीति कुमार घोष ने भी 1956 में पार्टी की गलत लाइन का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था।

1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में महान बहस छिड़ी थी। इसे संशोधनवादी, गद्दार कृश्चेव जो सीपीएसयू के भीतर पूंजीवादी पुनर्स्थापना का पक्ष लेने वाली गुट का नेतृत्व कर रहा था, के खिलाफ माओ के नेतृत्व वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चला रही थी। इस तीखे संघर्ष के दौरान कॉमरेड घोष ने बिना किसी पार्टी की संबद्धता के सपीसी का समर्थन किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय सीपीआई ने राष्ट्रीय दुरहंकार की नीति अपनाते हुए 'चीन के खुला आक्रमण के खिलाफ मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजूट होने' का आह्वान किया था। सीपीआई छोड़ने के बाद अंग्रेजी के अध्यापक की नौकरी करने वाले कॉमरेड घोष ने सीपीआई के रुख का विरोध किया। एक ऐसे माहौल में जहां प्रतिक्रियावादियों के द्वारा चीन विरोधी युद्ध के समर्थन को ही देश भक्ति कहा जा रहा था, कॉमरेड घोष एवं अन्य कम्युनिस्टों के द्वारा सही राजनीतिक व वैचारिक रुख अपनाने का साहस दिखाया गया था। भारत–चीन युद्ध को लेकर सीपीआई के भीतर आंतरिक संघर्ष और तीखा हुआ। अंततः सीपीआई का विभाजन होकर सीपीआईएम का गठन हुआ। महान बहस एवं भारत–चीन युद्ध दोनों ही मामलों में यद्यपि सीपीआईएम को चीन समर्थक माना गया था लेकिन सच यही है कि सीपीआई एवं सीपीआईएम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा क्रांतिकारी नियमों व उसूलों से संबंधित सवालों पर बुनियादी फर्क नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीपीएसयू की संशोधनवादी लाइन एवं देश में दक्षिण पंथी अवसरवादी लाइन को अपनाकर सीपीआइएम ने अपने संशोधनवादी राजनीतिक पतन को प्रकट किया था। सीपीआई के अवसरवाद से ऊब चुके सही क्रांतिकारियों को विभाजन में आशा की नई किरण दिखी थी। सीपीआईएम के गठन को एक सकारात्मक कदम मानकर वे सीपीआई छोड़कर सीपीआइएम में शामिल हुए। कॉमरेड सुनीति कुमार घोष 1964 में सीपीआईएम में शामिल हुए थे। पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने लेख लिखे। लेकिन सीपीआइएम के नेतृत्व का अवसरवाद बहुत जल्द ही सामने आया। नवंबर, 1964 में संपन्न पार्टी कांग्रेस में पारित पार्टी संविधान ने 'शांतिपूर्ण तरीकों में जनता के जनवाद की स्थापना एवं समाजवादी तब्दीली' को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस तरह सीपीआईएम के नेतृत्व का दक्षिणपंथी अवसरवाद का चेहरा खुलकर सामने आया था। सीपीआइएम के भीतर मौजूद असली क्रांतिकारियों ने पार्टी नेतृत्व के नव संशोधनवाद के खिलाफ आंतरिक संघर्ष शुरू किया था। इस आंतरिक संघर्ष का नेतृत्व करते हुए कॉमरेड चारू मजुमदार ने उत्तरी बंगाल के देहाती इलाकों में माओवादी राजनीतिक व सैद्धांतिक विचारों पर आधारित होकर किसान संघर्षों का नेतृत्व किया। इसी के तहत उन्होंने आठ दस्तावेजों को प्रकाशित किया। सीपीआईएम के भीतर के असली क्रांतिकारियों का उन्होंने आह्वान किया कि वे सैद्धांतिक, राजनीतिक व सांगठनिक तौर पर संशोधनवाद के साथ विभाजन रेखा खींच लें। कॉमरेड कन्हाई चटर्जी एवं अन्य जिन्होंने दक्षिण देश पत्रिका का प्रकाशन किया था, कॉमरेड अमूल्या सेन के नेतृत्व वाली चिंता गुट एवं अन्य क्रांतिकारी सीपीआइएम के संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखे हुए थे। कॉमरेड घोष सीपीआइएम की गलत लाइन के विरोध में 1965 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

संशोधनवाद के खिलाफ क्रांतिकारियों का लंबा राजनीतिक व वैचारिक संघर्ष महान नक्सलबाड़ी उभार के साथ चरम पर पहुंच गया था। कॉमरेड घोष ने नक्सलबाड़ी उभार का जोशीला स्वागत किया था। कॉमरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व को ऊंचा उठाया और वे सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। 1967 में वे पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारियों की समन्वय समिति के सदस्य बन गये। बाद में 1968 में जब एआईसीसीसीआर का गठन हुआ, वे उसका भी सदस्य बने। भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में एक गुणात्मक छलांग के तौर पर 1969 में भाकपा (मा–ले) का गठन हुआ। 1970 में सफलतापूर्वक संपन्न भाकपा (मा–ले) की आठवीं कांग्रेस में कॉमरेड सुनीति कुमार घोष केंद्रीय कमेटी सदस्य चुने गये थे। केंद्रीय कमेटी सदस्य के रूप में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व करने के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही वे

पार्टी के साप्ताहिक बांगला मुखपत्र 'देशब्रति' एवं मासिक अंग्रेजी मुखपत्र 'लिबरेशन' के लिए 'सौम्या' के नाम से नियमित रूप से लिखते थे। कॉमरेड घोष नवंबर, 1967 से यानी प्रारंभिक अंक से ही लिबरेशन की संपादकीय टीम का हिस्सा थे। उनके संपादकत्व एवं कॉमरेड सीएम के नजदीकी मार्गदर्शन में लिबरेशन ने सैद्धांतिक, वैचारिक लेखों की श्रंखला प्रकाशित की। विभिन्न संघर्ष इलाकों के वर्ग विश्लेषण, संघर्ष की रिपोर्ताज, संशोधनवाद का पर्दाफाश करते हुए एवं माओवाद को ऊंचा उठाते हुए सैद्धांतिक बहसों को छापा। कैडरों व जनता का आह्वान करते हुए संपादकीय लेख लिखे गये। पार्टी संगठक की भूमिका निभाने वाले मुखपत्र के रूप में लिबरेशन ने अद्‌भुत मिसाल पेश की। लिबरेशन के संपादक के रूप में कॉमरेड घोष ने क्रांतिकारी लाइन को ऊंचा उठाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाकपा (मा–ले) एवं उसके नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के सफाये के लिए दुश्मन ने अभूतपूर्व दमन अभियान चलाया था। अप्रैल, 1970 में कोलकाता स्थित पार्टी पत्रिकाओं के कार्यालय पर हमला करके उसे तहस–नहस किया गया था। उसके बावजूद दो साल और, तीव्र दमन के चलते 1972 की शुरूआत में पत्रिका को बंद करते तक कॉमरेड घोष उसका संपादक बने रहे। पार्टी की दोनों पत्रिकाओं के महत्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशब्रति का सरकुलेशन 40,000 प्रतियों से भी ज्यादा एवं लिबरेशन का 4000 से ज्यादा हो गया था।

पार्टी के भीतर मौजूद दक्षिणपंथी अवसरवादियों एवं संशोधनवादियों ने जब पार्टी लाइन एवं कॉमरेड सीएम पर हमला किया था, कॉमरेड घोष ने तीव्र दमन के बीच ही मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद पर अटूट विश्वास के साथ नक्सलबाड़ी की क्रांतिकारी लाइन एवं कॉमरेड सीएम के नेतृत्व का बचाव किया था।

भाकपा (मा–ले) के गठन के पूर्व, एआईसीसीसीआर में मौजूद दक्षिणपंथी अवसरवादियों के खिलाफ संघर्ष करके ही नक्सलबाड़ी लाइन को संरक्षित व विकसित किया जा सका था। भाकपा (मा–ले) के गठन के बाद भी संशोधनवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ संशोधनवादियों एवं दक्षिणपंथी अवसरवादियों के खिलाफ संघर्ष करते रहने तथा दूसरी तरफ क्रांतिकारी आन्दोलन के दौरान हुई गलतियों, कमियों व खामियों जिनका फायदा उठाकर संशोधनवादी सशस्त्र कृषि क्रांतिकारी युद्ध की लाइन को ही खारिज करने का प्रयास कर रहे थे, को चिन्हित करके, उनका मूल्यांकन करने की जरूरत थी। उस दौर की पार्टी की गलतियों, कमियों व खामियों के बारे में अपने स्वयं के आत्मालोचनात्मक आंकलन के बावजूद कॉमरेड घोष ने संशोधनवादियों व अवसरवादियों के हमलों का डटकर मुकाबला किया था।

1970 की शुरूआती सालों में, क्रांतिकारी आन्दोलन के धक्का खाने के बाद पार्टी की कुछ सही क्रांतिकारी ताकतें स्वतंत्र रूप से, अलग–अलग धाराओं में विकसित हुई। इस क्रम में वे अपने–अपने हिसाब से नक्सलबाड़ी के अनुभवों का मूल्यांकन किया, विगत की गलतियों, कमियों व खामियों को चिन्हित किया। 1972 में कॉमरेड सत्यम, कॉमरेड कैलासम, कॉमरेड सरोज दत्ता, कॉमरेड सीएम एवं अन्य नेतृत्वकारी कॉमरेडों की शहादत एवं कुछ अन्यों की गद्‌दारी के बाद भाकपा (मा–ले) की आठवीं कांग्रेस में चुनी गयी केंद्रीय कमेटी के सदस्यों में से कुछेक ही बचे रह गये थे जिनमें से कॉमरेड सुनीति कुमार घोष एक थे और पार्टी की बुनियादी राजनीतिक लाइन के प्रति वचनबद्ध थे। पार्टी एवं क्रांतिकारी आन्दोलन को पुनर्जीवित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने परिस्थितियां परिपक्व थीं। बची हुई क्रांतिकारी शक्तियां आशा कर रही थीं कि वे अखिल भारतीय आन्दोलन का नेतृत्व करेंगे और पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे। दरअसल 1973 में गठित केंद्रीय सांगठनिक कमेटी (सीओसी) के जरिए कॉमरेड घोष मार्क्सवादी–लेनिनवादी ताकतों को पुनस्संगठित करने की प्रक्रिया में शामिल हो गये थे। लेकिन सीओसी के सदस्य संगठनों में विगत के मूल्यांकन एवं कार्यनीति के सवालों पर मौजूद अनसुलझे मतभेदों के चलते वह संभावना खत्म हो गयी। कॉमरेड घोष ने विगत के क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में अपने स्वयं का आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन पेश किया था जो सीओसी के अन्य संगठनों को मंजूर नहीं था। इस तरह सीओसी क्रांतिकारी आन्दोलन की एकता व निर्माण के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही और 1975 तक व्यवहार में सीओसी नाकाम हो गयी थी। इस विफलता के चलते कॉमरेड घोष क्रांतिकारी शक्तियों को एकताबद्ध करके पार्टी निर्माण नहीं कर सके। उसके बाद वे शोध कार्य एवं लेखन पर ध्यान देने के लिए स्वयं को सांगठनिक गतिविधियों से दूर कर लिया।

आपातकाल के खत्म होने व 1977 के आम चुनावों जिनमें जनता पार्टी की जीत हुई थी और क्रांतिकारियों को निशाना बनाने के राज्य दमन में कुछ ढ़ील आयी थी, के बाद कॉमरेड घोष अपने भूमिगत जीवन को समाप्त कर लिया था। तब से वे गंभीर राजनीतिक अध्ययन एवं लेखन में लग गये थे। दशकों की बौद्धिक मेहनत के आधार पर उन्होंने कई किताबें व लेख लिखी। उनकी किताबें व लेख नक्सलबाड़ी की राजनीतिक दिशा एवं मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद के प्रति कॉमरेड घोष की प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं।

अपने जीवन के अखिरी दिनों में कॉमरेड घोष ने नक्सलबाड़ी

बेतकाठी झूठी मुठभेड़ के शहीदों को लाल जोहार

महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा छल–कपट तरीके से की गयी फर्जी मुठभेड़ में दिनांक 17 फरवरी, 2014 की रात 11 बजे, बेतकाठी बाजार गांव, कोरची तहसिल, जिला गड़चिरोली में गोंदिया डिविजन के 7 कॉमरेड्स–कॉमरेड लालसू, डीवीसीएम; कॉमरेड विरू, एसीएम देवरी; कॉमरेड पुन्नी, एसीएम देवरी; कॉमरेड सुनिल, एसीएम देवरी; कॉमरेड नविन, एसीएम कोरची; शामको, एसीएम कोरची एवं कॉमरेड राजेश, प्लाटून सदस्य शहीद हुए हैं। इन कामरेडों से पुलिस ने एक एके–47, दो एसएलआर, एक 303 राईफल, एक 8 एमएम, एक स्टेन, एक 9 एमएम पिस्टल जब्त की। एक वॉकीटाकी एवं शहीद साथियों के सामान भी पुलिस ने जब्त किया।

कॉ. लालसू

अब तक मिली सूचनाओं के मुताबिक इन साथियों को कहीं खाने में जहर देकर, उनकी हत्या करने के बाद बेतकाठी में मुठभेड़ दिखाया गया। मानवाधिकार संगठन ने भी तुरंत जाकर जांच की और गांव के लोगों से की गयी पूछताछ के हवाले से इसे झूठी मुठभेड़ करार दिया है। मानवाधिकार संगठन ने यह भी कहा कि उक्त माओवादी बेतकाठी गांव में गये ही नहीं। इन अमरवीरों को 'प्रभात' अपनी भावभिनी श्रद्वांजली अर्पित करता है।

कॉमरेड लालसू उर्फ बिदाल

कॉमरेड लालसू उर्फ बिदाल (42) पामेड़ एरिया, दक्षिण बस्तर डिविजन के गोम्मुगुड़ेम गांव में पैदा हुए थे। 1998 से गोंदिया डिविजन में कार्यरत थे। पहले परसवाडा एलजीएस में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए फिर पीपीसीएम बने। उन्होंने परसवाडा एलजीएस कमांडर की जिम्मेदारी भी निभाई। जनता से उनका गहरा रिश्ता था। बाद में प्लाटून बनने के बाद प्लाटून में रहे। वे बहुत दिनों तक प्लाटून कमांडर रहे। 2010 में जब डीके–गोंदिया बॉर्डर प्लाटून बनाया गया था, कॉमरेड लालसू उसका कमांडर बनाये गये थे।

कॉमरेड लालसू 2006 में संपन्न डिविजन अधिवेशन में सब डीवीसीएम के रूप में चुने गए थे। वे 2008 में आयोजित डिविजन प्लीनम में डीवीसीएम चुने गये थे। वे 2011 में डिविजन कमांडर–इन–चीफ बने और 2013 से देवरी एरिया के इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे। कॉमरेड लालसू ने कई प्रतिरोध कार्रवाईयों, एम्बुशों में हिस्सा लिया। एक लड़ाकू जनयोद्धा के रूप में वह उभरकर आये थे। वह बहुत सहजता से दुश्मनों पर कार्रवाई की योजना बनाते थे और जनता का सहयोग लेत थे। युद्ध के लिए लगने वाला गोलाबारूद व अन्य सामान स्थानीय स्तर पर जुटाने में हमेशा सजग रहते थे। एक अनुशासनबद्ध नेतृत्व के रूप में उनकी मान्यता थी। कठिन परिस्थिति वाले इलाकों में काम करने के लिए कॉमरेड लालसू पहली पंक्ती में तैयार रहते थे। वह एक ऐसे लड़ाकू बहादुर जनयोद्धा थे जिनकी उपस्थिति से कतारें हिम्मत महसूस करती थी। कॉमरेड लालसू साहस और हिम्मत की मिसाल थे। वे दक्षिण बस्तर से पार्टी में भर्ती होकर महाराष्ट्र आये थे। गड़चिरोली, गोंदिया जिलों में, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान आदि तहसिलों में तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कॉमरेड लालसू ने सैनिक कार्रवाइयों में

आन्दोलन की स्मृतियां प्रकाशित की। आन्दोलन की बुनियादी दिशा को ऊंचा उठाते हुए ही उन्होंने भाकपा (मा–ले) व कॉमरेड चारू मजुमदार के कामकाज के तौर तरीकों व कार्य नीति से संबंधित अपनी आलोचनाओं व असहमितियों को उक्त किताब में व्यक्त किया। भा.क.पा. (माओवादी) कॉमरेड घोष के द्वारा निर्धारित कुछ मूल्यांकनों व निष्कर्षों के प्रति अलग दृष्टिकोण रखती है और उनके तमाम निष्कर्षों व आलोचनाओं से सहमत नहीं हो सकती है। इसके बावजूद यह सच है कि बुनियादी तौर पर वे नक्सलबाड़ी की राजनीतिक दिशा के साथ जुड़े रहे और आजीवन क्रांतिकारी बुद्धिजीवि बने रहे।

जनयुद्ध को आगे बढ़ाते हुए नक्सलबाड़ी के परचम को ऊंचा उठाने वाली क्रांतिकारी धाराओं के कामरेड सुनीति कुमार घोष दोस्त व शुभचिंतक थे। आन्दोलन के धक्का खाने के बाद 1970 के दशक में पार्टी के पुनर्निर्माण में एवं विभिन्न धाराओं को एकताबद्ध करने में उनकी असमर्थता के बावजूद कॉमरेड घोष एक अनुभवी कॉमरेड की हैसियत से क्रांतिकारियों को कुछ मूल्यवान सुझाव व सलाह देते रहे। पार्टी एवं पीड़ित जनता ने कॉमरेड घोष के निधन से एक महान दोस्त एवं सहयात्री को खोया है। क्रांति एवं पीड़ित जनता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता हमेशा के लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमारे शहीद क्रांतिकारी योद्धाओं एवं कॉमरेड सुनीति कुमार घोष जैसे साथियों की विरासत में मिले लाल झंडे को ऊंचा उठाये रखना ही उन्हें दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ★

भाग लिया। इस इलाके की जनता से उनका अच्छा रिश्ता रहा। पार्टी ने जब पश्चिम घाट स्थित क्रांतिकारी आंदोलन की मदद के लिए जाने की अपील की थी तब लालसू स्वयं तैयार हुए थे। उन्होंने कर्नाटक तथा तमिलनाडू में वहां के क्रांतिकारी गुरिल्लाओं को प्रशिक्षण देने में भी अपना योगदान दिया। इस दौरान पश्चिम घाट पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उस समय धैर्य, साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए, दुश्मन के खिलाफ लड़कर नेतृत्व और अपने साथियों को फायरिंग रेंज से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी।

कॉमरेड वीरू उर्फ विनय उर्फ दुलेश कुंजीलाल नैताम

अपनी शहादत के समय 40 वर्ष की उम्र के कॉमरेड वीरु गांव सावली, तहसील कोरची, जिला गड़चिरोली में पैदा हुए थे। आदिवासियों पर जारी सरकारी दमन और शोषण को देखकर, आक्रोशित होकर पढ़ा–लिखा कुंजीलाल पार्टी में भर्ती हुए थे। अपनी राजनीतिक, सांगठनिक, और सैनिक समझदारी को बढ़ाते हुए, सक्रिय रूप से पार्टी में कार्य कर रहे थे। सन 2003 में एक कॉमरेड को गुरिल्ला जोन से बाहर निकालते समय पुलिस मुखबिरी की सूचना के आधार पर वीरू को गिरफ्तार किया गया था। लगभग साड़े पांच साल तक जेल में रहे। 2009 में छूटकर आने के बाद क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता रहा। वे पहले कोरची एसी में व बाद में देवरी एसी में एसीएम के रूप में कार्य करते रहे। कठिन परिस्थिति में भी पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में वह जनयुद्ध में कार्यरत थे। स्थानीय कॉमरेड होने के कारण जनता का प्यार, अपनापन और विश्वास उन्हें हासिल था। इनकी शहादत से जनता ने अपना प्यारा बेटा खो दिया है। यह जनता के कलेजे पर सत्ता का बहुत बड़ा हमला है।

कॉमरेड नवीन उर्फ सत्तारसिंग तोफा

गांव मुरकुडी, तहसिल कोरची, जिला गड़चिरोली में 40 वर्ष पहले कॉमरेड नवीन का जन्म हुआ। बचपन से पार्टी और क्रांतिकारी कार्यकलापों को नजदीक से देखते हुए विकसित हुए कॉमरेड नवीन अपनी किशोरावस्था में ही पार्टी में भर्ती हुए थे। जनता पर हो रहे अन्याय और अत्याचारों ने नवीन के मन में चिड़ उत्पन्न की और वह व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निकल पड़ा। पार्टी के द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारी को निभाते समय कॉमरेड विरू के साथ गिरफ्तार हुए। इतनी कम उम्र के होने के बाद भी दुश्मन की यातनाओं से बिल्कुल भी न डरे और न ही विचलित हुए। इस जुल्मी सत्ता ने उन्हें कम उम्र होने के कारण बाल कारागृह में डाल दिया था। वहां से पुलिस को चकमा देकर बाल कारागृह से भाग आये और जनयुद्ध में शामिल हुए। अपने कार्यों को वे पहलकदमी और वफादारी के साथ निभाता था। शहादत के समय वे कोरची एसी में एसीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। यह स्थानीय कॉमरेड थे, इसलिए जनता उन्हें अपने लाडले बेटे की तरह प्यार करती थी। हर गांव की जनता खासकर युवओं से उनका जीवंत संबंध रहता था। जनता के विस्थापन विरोधी कोरची आंदोलन में मिलिशिया को गोलबंद करने में उनकी भूमिका यादगार रहेगी। इन्होंने डिविजन में संचालित लगभग हर टीसीओसी तथा प्रतिरोधी गतिविधियों में स्काउट के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभायी थी। सक्रिय रूप से व पहलकदमी के साथ काम करने वाले कॉमरेड नवीन के शहीद हो जाने से डिविजन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

कॉमरेड सुनिल उर्फ कुमार ताडावी

शहादत के समय 28 वर्ष के कॉमरेड कुमार ताडावी महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित गांव गोटाटोला, जिला राजनांदगांव के रहवासी थे। वे 2006 में पार्टी में भर्ती हुए। उन्होंने दर्रेकसा, तांडा एरिया में कार्य किया। प्लाटून सदस्य एवं छोटी आर्गनाईजिंग टीम में भी कार्य किया। एक्शन टीम में भी काम किया। दुश्मन के खिलाफ हमलों व एम्बुशों में भाग लिया। जनद्रोही एवं मुखबिरों पर पार्टी निर्णयों के मुताबिक कार्रवाई करने में उनकी पहलकदमी रहती थी। उनकी दृढ़ता और लड़ाकूपन देखते हुए, उन्हें नेतृत्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गयी

थी। तीन साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद से लेकर शहादत तक वह देवरी एसीएम के रूप में कार्यरत थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी जनता से संपर्क बनाए रखने में महात्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह कॉमरेड भी स्थानिय होने के कारण जनता में लोकप्रिय थे।

कॉमरेड पुन्नी उर्फ रत्ती नरोटी

कॉमरेड पुन्नी उर्फ रत्ती नरोटी 36 वर्ष पहले गांव कोईदुड, गट्टा एरिया में जन्म लिया था। घर में रहते समय ही पार्टी के संपर्क में आयी थी। वह पहले क्रांतिकारी महिला संगठन में तथा बाद में मिलिशिया में सक्रिय थी। पार्टी में भर्ती होने के बाद वह पीएल–7 में रही। बाद में उन्होंने गड़चिरोली एवं गोंदिया जिले के बॉर्डर पर गठित बार्डर प्लाटून में पीपीसी मेंबर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान प्रतिरोध कार्रवाइयों, टीसीओसी में सक्रिय सहभागी रही। बाद में उनका देवरी एसी में तबादला किया गया। शहादत के समय वह देवरी एसीएम के रूप में भूमिका निभा रही थी। कॉमरेड पुन्नी अनुशासनबद्ध नेत्री थी। कठिन परिस्थिति में भी महिला मुक्ति का झंडा बुलंद रखने वाली क्रांतिकारी नेत्री के रूप में कॉमरेड पुन्नी जनता एवं पार्टी के लिए आदर्श स्थापित कर शहीद हो गई।

कॉमरेड शामको उर्फ शांता कोरचा

कॉमरेड शांता का जन्म कसनसुर एरिया के गांव तोडसापेठ में हुआ था। शहादत के समय वह 26 वर्ष की थी। क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर वह पार्टी में भर्ती हुई। वह जन कलाकार थी। चेतना नाट्य मंच में क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्मी के रूप में कार्य करते हुए पीएलजीए में प्लाटून सदस्या के रूप में रही। फिर विकसित होकर एरिया कमेटी सदस्य बनकर कोरची एसी में अपनी भूमिका निभा रही थी। अपनी कला के माध्यम से जनता के बीच में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार–प्रसार करने का उनका योगदान हमेशा याद रखा जायेगा।

कॉमरेड राजेश उर्फ लालसू उर्फ सोबेराय तोफा

कॉमरेड राजेश का जन्म 27 वर्ष पहले ग्यारापत्ती गांव में हुआ था। शहादत के समय वे गोंदिया डिविजन के प्लाटून 56 के सदस्य थे। पीपीसीएम के रूप में काम करते हुए किसी कारणवश वह फिर सदस्य के रूप में ही भूमिका निभा रहे थे। वह एक लड़ाकू एवं बहादुर जनयोद्धा थे। मरकानार एम्बुश में घायल होने पर भी हार नहीं माने और लड़ते रहे। विस्तार के लिए गठित प्लाटून में भी उनकी भूमिका रही। एम्बुश में, रेक्की करने में, स्काउटों में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कमांड के आदेश पर तुरंत पहलकदमी लेकर काम करते थे। उनकी शहादत से गोंदिया डिविजन ने एक बहादुर जनयोद्धा को खो दिया है।

इन सभी सात कॉमरेडों का गोंदिया डिविजन के क्रांतिकारी आंदोलन में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें खोना डिविजन आन्दोलन के लिए अपूरणीय क्षति है। इन अमर शहीदों को लाल–लाल सलाम।

इंदूर फर्जी मुठभेड़ के शहीदों को लाल–लाल सलाम!

गढ़चिरौली पुलिस की क्रूरता के इतिहास में 28 अक्टूबर, 2013 को एक और अध्याय जुड़ गया था। इंदूर की फर्जी मुठभेड़ में दो महिला छापामारों कॉमरेड रीता एवं कॉमरेड सरिता की क्रूरतापूर्वक हत्या की गयी। जड़ीबूटि (आयुर्वेदिक) इलाज के लिए डेरे से दूसरे गांव गयी कॉमरेड सरिता को लाने कॉमरेड रीता सादे कपड़ों में उस गांव में गयी थी। उसी समय में मुठभेड़ शुरू हुई थी। दोनों महिला छापामारों को अपनी बंदूक एवं वर्दी तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला था। दोनों कॉमरेडों को घर से निकालकर यातनाएं देकर गांव वालों के सामने ही गोली मार दी थी। इसके पहले बटपरि गांव में फर्जी मुठभेड़ में शहीद हुई दो ग्रामीण युवतियों की लाशों को पुलिस द्वारा रीता एवं सरिता की लाश कहकर घर वालों को जोर जबर्दस्ती करके दिया गया था। दरअसल फर्जी मुठभेड़ को सही मुठभेड़ करार देने की साजिश के तहत ग्रामीण युवतियों को

सरिता, रीता के रूप में जबरन प्रचारित किया गया था। लेकिन कॉमरेड सरिता एवं रीता की शहादत ने पुलिस की साजिश का पर्दाफाश किया।

कॉमरेड रीता उर्फ पाक्ली रेय्या

कॉमरेड रीता का जन्म पश्चिम बस्तर डिविजन के भैरमगढ़ एरिया के मसला गांव में हुआ था। 2005 में सलवा जुडूम पाशविक दमन अभियान के शुरू होने के बाद बस्तर के संघर्ष इलाकों की आदिवासी जनता के सामने अपने अस्तित्व व जल–जंगल–जमीन को बचाने लड़ाई के अलावा दूसरा चारा नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में मां–बाप के प्रोत्साहन पाकर कॉमरेड पाक्ली जनवरी, 2007 में पेशेवर क्रांतिकारी बनी थी। भर्ती होने के बाद पार्टी निर्णय के मुताबिक वह गढ़चिरौली पहुंच गयी थी। रीजनल सप्लाई टीम में रहकर उन्होंने दोनों डिविजनों एवं मेन फोर्स के लिए युद्ध सामग्री सहित तमाम जरूरतों की आपूर्ति करने में काफी मेहनत की। उसी समय उन्होंने अपनी टीम के कमांडर कॉमरेड महरू के साथ 2010 में शादी की। 2010 की आखिरी में दोनों प्लाटून–7 में तबादला हुआ था। कॉमरेड महरू प्लाटून कमांडर बन गये थे। बाद में कॉमरेड महरू की शहादत हुई। बावजूद इसके कॉमरेड रीता अविचलित व मजबूती से क्रांतिकारी आन्दोलन में डटी रही। राजनीतिक व सैनिक मामलों में उनकी पकड़ को देखते हुए उन्हें पीपीसी सदस्य की पदोन्नति दी गयी थी। टीसीओसी के दौरान वह सैनिक कार्रवाइयों में बढ़–चढ़कर भाग लेती थी। विकास की संभावनाओं से भरपूर एक उभरती कमांडर की फर्जी मुठभेड़ के चलते असमय मौत हो गयी। गढ़चिरौली की संघर्षरत जनता कॉमरेड पाक्ली के योगदान को हमेशा याद रखेगी।

कॉमरेड सरिता उर्फ ज्योति पुंगाटि

कॉमरेड सरिता दक्षिण गढ़चिरौली डिविजन के गट्टा एरिया के एटापल्ली तहसील के गुडजूर गांव में 20 साल पहले पैदा हुई थी। उनकी मां का नाम राजे एवं बाप का नाम वत्ते पुंगाटि है। गरीब परिवार में जन्मी ज्योति ने मां–बाप की मदद् के लिए दो साल तक घरेलु श्रमिक का काम किया था। इसी दौरान वह सीएनएम के नाच गानों के प्रति आकर्षित होकर उसकी सदस्या बनी। 2009 में वह पेशेवर क्रांतिकारी बन गयी। वह पहले जन मिलिशिया दस्ते की सदस्या के रूप में काम करते हुए गांवों की युवाओं की उन्होंने मिलिशिया में भर्ती की। लुटेरी सरकार को खत्म करके क्रांतिकारी जनताना सरकारों को खड़ा करने, व मजबूत करने के लिए लड़ाई ही एक मात्र रास्ता है, यह कहते हुए मिलिशिया को सैनिक कार्रवाइयों के लिए तैयार करती थी। बाद में दो साल उन्होंने पीएल–7 में काम किया। शादी के कुछ समय बाद उनके जीवन साथी ने पार्टी छोड़ी थी। उसके बावजूद कॉमरेड ज्योति मजबूती से क्रांतिकारी आन्दोलन में डटी रही। जनयुद्ध ही मेरी जान है, 'जनता ही मेरी सांस है' कहती हुई कॉमरेड ज्योति ने जनयुद्ध में अपनी जान कुरबान की। कॉमरेड ज्योति पुंगाटि के आदर्श पर अमल करेंगे।

★

(...46 पेज से)

जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ऐसी जिंदगी व नौकरी को छोड़कर जनता व अपने परिवारजनों के साथ मिलकर खुशी की जिंदगी बिताइये। अनावश्यक अपनी जान मत गंवाइये।

पिछले 35 सालों से हम शोषित जनता के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। लुटेरे समाज को बदलना हमारा लक्ष्य है। जनता को रोटी, कपड़ा, मकान और आत्म सम्मान मिले इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसके लिए हंसते–हंसते अपनी जान कुरबान कर रहे हैं। दुनिया का सर्वहारा वर्ग व शोषित जनता हमारे बलिदानों को ऊंचा उठाते हुए हमारे संघर्ष को मदद दे रहे हैं। हमारा युद्ध न्यायपूर्ण है। यह जनयुद्ध है। जनयुद्ध के रथ के पहियों को रोकने का व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण प्रयास मत करो। आप जनता के खिलाफ युद्ध मत करो। कमाण्डों नौकरियों से इस्तीफा दो। नव जीवन योजना एक ढोंग है व धोखेबाजीपूर्ण है। वह लूटखोर जीवन योजना है। आप सचमुच अच्छी जिंदगी जीना चाहोगे तो कमाण्डो की नौकरी छोड़ दीजिये। जनता के साथ मिलकर, निर्भीक होकर सम्मानपूर्ण जिंदगी बिताइये। हमारी विज्ञप्ति को स्वीकार कीजिए। हम कदापि नहीं चाहते हैं कि आपकी मौत हो। सोच लीजिए और उचित निर्णय लीजिए

★

श्रद्धांजलि

जनताना सरकार शाला के आदर्श गुरूजी कॉमरेड दरबार मंडावी को लाल–लाल सलाम्!

कॉमरेड दरबार मंडावी कुवानार एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक आश्रम पाठशाला के आदर्श गुरूजी थे। वे एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार की विद्या विभाग कमेटी के प्रमुख थे। कुवानार एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। 23 साल की अपनी क्रांतिकारी जीवन में कॉमरेड दरबार ने युवा पीढ़ी के क्रांतिकारियों के सामने एक आदर्शपूर्ण व्यवहार को प्रस्तुत कर गये हैं। केशकल एरिया के कोरोहबेडा गांव के पास 11 मई 2014 को दुश्मन के द्वारा किये गये घेराव दमन हमले में कॉमरेड दरबार ने अपनी जान की कुरबानी दी। जिंदा पकड़ने के बाद दुश्मन के बलों ने कॉमरेड दरबार को अमानवीय यातनाएं दी गयी। सिर और छातियों में लगी दो गोलियों के अलावा उनके शरीर पर 25 गंभीर घाव थे जो धार–धार हथियारों से किये गये थें इससे न सिर्फ दुश्मन की क्रूरता का बयान होता है बल्कि कॉमरेड दरबार की क्रांति के प्रति निष्ठा, कर्मठता भी इसमें झलकता है। वे पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से दुश्मन के निशाने पर थे। जनता के बीच रहते हुए, जनता पर निर्भर रहकर वे हमेशा दुश्मन को चक्मा देते रहे।

कॉमरेड दरबार का जन्म 50 साल पहले उत्तर बस्तर कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के मुरनार गांव जो कि आन्दोलन के केशकल इलाके में आता है, में हुआ। मध्य वर्गीय आदिवासी किसान परिवार में जन्में कॉमरेड दरबार ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। अपने समाज में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने वे रात्रि पढ़ाई के गुरूजी बने थे।

1990 के दशक की शुरूआत में जब केशकल एरिया में क्रांतिकारी आन्दोलन का विस्तार हुआ, तब समाज सेवा एवं समाज में बदलाव की भावना रखने वाले कॉमरेड दरबार सहज ही तुरंत पार्टी संपर्क में आये थे। शहीद कॉमरेड सुखदेव की कॉमरेड दरबार पर अमिटछाप थी। कॉमरेड दरबार पर कॉमरेड सुखदेव का राजनीतिक प्रभाव आखिरी तक कायम रहा।

कॉमरेड दरबार ने अपना राजनीतिक जीवन डीएकेएमएस से शुरू किया था। धीरे–धीर वे रेंज कमेटी सदस्य बन गये थे। वन विभाग एवं व्यापारियों की लूट के खिलाफ जनता को गोलबंद करने में वे आगे रहते थे। 1992 में रावघाट खनन परियोजना के खिलाफ अंतागढ़ में आयोजित 10 हजार लोगों की विशाल रैली को सफल करने में कॉमरेड दरबार की भी भूमिका थी। खदान खोलने में लगी मशीनों तोड़–फोड़ करने में भी वे शामिल रहे। अंतागढ़ के आसपास के गांवों में जन संगठन को मजबूत करने में विस्तार करने में उनकी अहम् भूमिका थी। तेंदूपत्ता तोड़ाई दर बढ़ाने, वनोपजों के दाम बढ़ाने के संघर्षों में वे जनता का नेतृत्व करते रहे। गुरूजी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी आदि तबकों से चर्चा करते हुए, पार्टी राजनीति से उन्हें अवगत कराकर पार्टी के पक्ष में खड़ा करने में उनकी भूमिका याद करने लायक थी। दमन व झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ जनता को गोलबंद करने में वे आगे रहते थे। एरिया के जन विरोधी सियानों, मुखबिरों के खिलाफ जन अदालतों में तय की गयी कार्रवाइयों को अंजाम दिलाने में वे आगे रहते थे।

1992 में डीएकेएमएस के गांव अध्यक्ष बनने वाले दरबार 1995 में उसकी रेंज कमेटी अध्यक्ष बन गये थे। वे एरिया के लोकप्रिय नेता थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उन्हें पसंद करते थे। 1995 में ही वे पार्टी सदस्य बन गये थे। केशकल एरिया में जब धौंसा में पहला क्रांतिकारी जनताना सरकार का गठन किया गया था, कॉमरेड दरबार उसका पहला अध्यक्ष बने थे। केशकल एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार का जब गठन हुआ था, तब कॉमरेड दरबार उसका उपाध्याक्ष चुने गये थे। अंतागढ़ इलाके में गठित पहली ग्राम पार्टी कमेटी का सचिव भी वे ही थे। पार्टी व जनताना सरकार का नेतृत्व करते हुए वे अपने गांव, पंचायत ही नहीं पूरे इलाके में पार्टी व जनताना सरकारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जनताना सरकारों की रक्षा के लिए मिलिशिया को मजबूत करने उन्हें बहुत कोशिश की। 2008–2009 में संपन्न विधान सभा एवं लोकसभा चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को सफल बनाने के लिए उन्होंने जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद किया था।

क्रांतिकारी आन्दोलन में और ज्यादा सेवाएं देने जब पार्टी ने उनके सामने पेशेवर क्रांतिकारी बनने का प्रस्ताव रखा वे सहर्ष तैयार हो गये थे। 2007 से 2010 तक वे एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार कमेटी में रहते हुए जनता के असली विकास के लिए काफी प्रयास किये।

कॉमरेड दरबार पाशविक पुलिस दमन के बीच में ही जनता का नेतृत्व करते रहे। पुलिस उनके लिए गांव पर

लगातार हमले करती थी लेकिन जन सहयोग से वे बच निकलते थे। दसियों बार पुलिस ने उनके घर पर हमला किया था। उनके मनोबल को घटाने उनके बड़े भाई, एवं उनके बेटों, स्वयं दरबार की पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। फर्जी केसों में फंसाया गया था। घर में लूट पाट करके सोना–चांदी के जेवरात, रुपये लूट ले गये थे। पूरे गांव वालों की पिटाई की गयी थी। डराया–धमकाया गया था। कॉमरेड दरबार के परिवार सहित पूरे गांव ने उनका हमेशा साथ दिया। कॉमरेड दरबार के बड़े भाई जिनकी 2013 में बीमारी की वजह से मृत्यु हुई, के ये शब्द क्रांतिकारियों के परिवार जनों के लिए आदर्श बने रहेंगे ''खेती–कमाई करके जिएंगे, पार्टी की ओर से मदद् की जरूरत नहीं है, जरूरत मंदों को दो, हमें सिर्फ पार्टी की तरफ से हिम्मत चाहिए, राजनीतिक बातें चाहिए, हम पार्टी व जनता को नहीं छोड़ेंगे''।

कॉमरेड दरबार 2008 में केशकल एसी सदस्य बन गये थे। उनकी क्षमता एवं उम्र को ध्यान में रखकर उन्हें उत्तर रीजनल मास टीम के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 2012 में उन्हें कुवानार एरिया क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक आश्रम पाठशाला के प्रधान अध्यापक के रूप में भेजा गया था। साथ ही अपनी शहादत के समय तक वे जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे परिवार जनों से मिलने केशकल गये हुए थे। परिवार जनों से वे सिर्फ कुछ घंटे ही बिताकर वापस दस्ते के पास आये थें शहादत के पहले वे 2014 के लोकसभा चुनाव बहिष्कार एवं प्रतिरोध में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे।

कॉमरेड दरबार पार्टी के एक अनुशासित सिपाही थे। वे पार्टी में मौजूद गलत रूझानों के खिलाफ हमेशा चर्चा करते थे, उन्हें दूर करने कैडरों को सुझाव, देते थे। अपनी जिम्मेदारी को क्रांतिकारी जिद के साथ पूरा करते थे। हर मामले में उनका पारदर्शी व्यवहार था। 50 साल की उम्र में भी वे सभी समिष्टि कार्यो में शामिल होते थे। युवाओं के साथ होड़ लगाते हुए कसरत करते थे। वे आत्मसमर्पण एवं गद्दारी से नफरत करते थे।

क्रांतिकारी राजनीति एवं जनता पर अटूट विश्वास रखकर आखिरी सांस तक संघर्ष की राह में चलने वाले आदर्श कम्युनिस्ट एवं बच्चों के प्यारे गुरूजी कॉमरेड दरबार अपने खून से जनमुक्ति मार्ग को लाल बना गये हैं। वे अपने पीछे पत्नी, दो बेटों एवं एक बेटी को छोड़ गये हैं।

कॉमरेड दरबार को मुठभेड़ के दौरान पकड़कर, अमानवीय यातनाएं देकर, क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या करके लाश को नारायणपुर ले जाया गया था। कॉमरेड दरबार की शहादत की खबर पाकर जनता नारायणपुर जाकर पुलिस के साथ लड़कर उनकी लाश को गांव में लायी थी। गांव में ही अपने प्यारे नेता को लोगों ने अंतिम विदाई दी

कॉमरेड दरबार मंडावी के आदर्शों पर अमल करेंगे।

कॉमरेड पंडरू उर्फ मुरहा को लाल सलाम!

कॉमरेड पंडरू की 23 फरवरी 2014 को छोटे टेमुरगांव के पास पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शहादत हुई। उनका जन्म पूर्व बस्तर डिविजन, नारायणपुर जिले के वयानार इलाके के छोटे टेमुरगांव में 23 वर्ष पहले ईकूल परिवार में हुआ था। बचपन में ही मां–बाप का साया उठ चुका था। बड़े भाई के पास रहकर पला, बढ़ा। गांव में दलम के पहुंचने की वह दौड़कर आता था। और वह बाल संगठन में शामिल हुआ था। गांव के सभी बालक, बालिकाओं को बाल संगठन में लाता था। 2007 में वह सीएनएम में शामिल हुए थे। 2008 में वह मिलिशिया में भर्ती होकर जनताना सरकार की रक्षा करने लगे थे। मिलिशिया में रहते हुए वह 2008 के विधान सभा चुनवों एवं 2009 में लोकसभा चुनावों के बहिष्कार अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे और प्रतिरोध कार्रवाइयों में भाग लिये थे। उन्होंने कुछ समय तक जनताना सरकार के कृषि क्षेत्र में भी काम किया था। 2011 में वह पूर्णकालिन कार्यकर्ता के रूप में पीएलजीए में भर्ती हुए थे। कुछ समय तक वयानार एलओएस में काम करने के बाद वह पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए भरमार परियोजना में शामिल हुए थे। वह बहुत मेहनती थे। हंसमुख थे। जितना भी काम करे, उनके चेहरे पर थकान का दूर–दूर तक कोई निशान नहीं होता था। 2012 में उन्हें पार्टी सदस्यता दी गयी थी। घर की कमजोर परिस्थिति का हवाला देकर कुछ समय के लिए वह घर गये थे। बाद में वापस आकर पार्टी के निर्णय अनुसार वयानार इलाके में काम कर रहे थे। किसी काम से जाते समय टेमुरगांव में ही अचानक पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कॉमरेड पंडरू शहीद हुए। पूर्व बस्तर डिविजन की जनता एवं मिलिशिया कॉमरेड पंडरू के योगदान को हमेशा याद रखेगी।

आइये कॉमरेड पंडरू के अधूरे आशय को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। ★

दृढ़ संकल्प रखो, कुरबानियों से न डरो और हर तरह की कठिनाइयों को दूर करते हुए विजय प्राप्त करो!

दक्षिण रीजियन

क्रांतिकारी आन्दोलन के सफाये के लक्ष्य से रीजन भर में जनवरी से अप्रैल 2014 के बीच हजारों सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा कई दफे अभियान चलाये गये। इन अभियानों के दौरान कइयों जगह जनता एवं छापामारों पर दुश्मन बलों ने फायरिंग की। बीजापुर एवं सुकमा जिलों में कुल आठ लोगों, जिनमें निहत्थे क्रांतिकारी एवं जनता शामिल हैं, की निर्मम हत्या की गयी। कइयों को गिरफ्तार करके यातनाएं दी गयी एवं जेलों में ठूंसा गया। कई गांवों में जनता की बेदम पिटाई हुई। महिलाओं पर अत्याचार किये गये। गांवों पर पुलिस हमलों के दौरान, जनता की संपत्ति को ध्वस्त करना, नकदी, सोना–चांदी के आभूषणों, कपड़े बर्तन, औजारों को लूटकर ले जाना, मुर्गों, बकरों एवं सुआरों को काटकर खाना, उठाकर ले जाना, तालाबों से मछली पकड़कर खाना आम बात हो गयी है।

पश्चिम बस्तर डिविजन मद्देड़ एरिया के अईपेटा, मर्रिमल्ला, लोदेड़, कर्रेमेट्टा, तेल्लानील्लु, वेंगलवाय एवं लिंगपल्ली गांवों के दायरे में 17 से 21 जनवरी तक दुश्मन बलों ने आतंक मचाया। इसी समय दक्षिण बस्तर डिविजन के तोंडामरका से केड़वाल तक के सभी गांवों पर हमले किये गये। इस अभियान में जेगुरगुण्डा, चिंतलनार, बुरकापाल, चिंतागुफा एवं बेज्जि कैंपों के करीबन 1500 पुलिस जवान शामिल हुए। केड़वाल गांव के पास पुलिस व छापामारों के बीच फायरिंग हुई जिसमें कुछ किट् बैग एवं चार बंदूक – एक 303 रायफल, एक सिंगल शॉट, एक 12 बोर और एक भरमार दुश्मन ने जब्त की। इसी क्रम में एक जगह हुई फायरिंग में एक पुलिस जवान मारा गया।

6 से 11 फरवरी के बीच नेशनल पार्क एरिया के अधिकांश इलाके को कव्हर करते हुए महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के सशस्त्र बलों ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान 7 फरवरी को गर्तुल गांव के पास तीन निहत्थे कामरेडों– नवीन, मासे एवं सन्नू को पकड़कर, यातनाएं देकर 8 फरवरी को बड़े काकिलेर गांव के निकट गोली मार दी गयी थी। इनमें से कामरेड् मासे एवं नवीन क्रांतिकारी दंपति थे। कॉमरेड मासे के साथ दुष्कर्म किया गया था।

28 फरवरी से 3 मार्च के बीच भैरमगढ़ एवं गंगालूर एरियाओं में दुश्मन ने एक बड़ा अभियान चलाया। दुश्मन बलों को नुक्सान पहुंचाने आकवा गांव के पास बूबी ट्रॉप लगाते समय दुर्घटनावश मिलिशिया कॉमरेड राजेश शहीद हो गये।

लोकसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के बाद दुश्मन के हमलों में तेजी आयी थी। 19 से 27 मार्च के बीच दुश्मन बलों के द्वारा चलाये गये देशव्यापी अभियान के दौरान किरंदूल एवं बीजापुर के सशस्त्र बलों ने भी संयुक्त अभियान चलाया था। 22 मार्च को पुलिस के द्वारा की गयी फायरिंग में जन मिलिशिया दस्ते का कमांडर फागू शहीद हो गया।

2 से 4 अप्रैल के बीच तेलंगाना एवं किष्टारम के सरहदी गांवों में दुश्मन ने अभियान चलाया। इस दौरान पालोड़ गांव के पास जनता पर की गयी अंधाधुंध गोलीबारी में छोटे केड़वाल का आदिवासी किसान मड़काम उंगाल ने अपनी जान गंवायी। भद्राचलम तक जाकर पुलिस के साथ लड़–भिड़कर लाश को लाने में ग्रामीण सफल हुए है। इसी इलाके में 8 से 11 अप्रैल के बीच एक और अभियान चलाया गया था। पुलिस की गोलीबारी में करिंगुंडम गांव का आदिवासी किसान धर्माल की मौत हुई। पीएलजीए के सेकंडरी व बुनियादी बलों ने मिलकर गोंदिगूड़ा गांव के पास ग्रेहाऊण्ड्स बलों पर फायरिंग की थी। पुलिस के साथ हुई इस गालीबारी में दुग्गुम गांव का मिलिशिया कॉमरेड मड़काम मासाल घायल होकर पुलिस के हाथ लग गया था। इसके अलावा गोंदिगूडा के चार ग्रामीणों को गिरफ्तार करके ले गये थे। गांव की जनता गोल्लपल्ली थाना जाकर आन्दोलन के जरिए गिरफ्तार लोगों को छुड़ा लाया।

चुनावों के समय सुकमा जिले के पोंदुम के दसियों ग्रामीणों को बेदम पीटा गया था, महिलाओं को अपमानित किया गया था।

13 से 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र सीमा में एक और अभियान चलाया गया था। 20 से 26 अप्रैल के बीच जिला बल एवं सीआरपीएफ ने मिलकर बीजापुर जिले के गंगालूर, चेरपाल के आसपास के गांवों पर हमले किये। तोड़का गांव के गरीब आदिवासी किसान ताती बूदु की गोली मारकर निर्मम हत्या करके पुलिस ने यह झूठा प्रचार किया कि मुठभेड़ में माओवादी मारा गया। पुलिसवालों ने मर्रुम, मनकेली, पोटानार आदि गांवों पर हमलों के दौरान तालाबों से ग्रामीणों की मछली पकड़कर खायी। पुंबाड़ के ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गयी। महिलाओं के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया गया बल्कि उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गयी थी।

इस तरह दुश्मन लगातार हमलों के द्वारा ग्रामीणों को आतंकित कर रहा है। साथ ही कॉरपेट सेक्युरिटी के तहत कैंपों को बढ़ाते जा रहा है। 28 जनवरी को दक्षिण बस्तर के दोरनापाल–जेगुरगुण्डा सड़क पर पूसवाड़ के पास एवं 4 मार्च को जेगुरगुण्डा एरिया के नरसापुरम के पास दो नये कैंप खोले गये।

पीएलजीए का प्रतिरोध

दरभा डिविजन के मलिंगेर एरिया के नकुलनार–बचेली सड़क पर कट्टेपाल घाटी के पास 28 फरवरी को दुश्मन पर पीएलजीए बलों के द्वारा किये गये एंबुश में पुलिस के 5 जवान मारे गये एवं 4 घायल हो गये। इस हमले में पीएलजीए के छापामारों ने दो एसएलआर, तीन इंसास, एक पिस्तोल, 419 गोली जब्त की।

दक्षिण बस्तर डिविजन के जेगुरगुण्डा एरिया के बुरकापाल कैंप के टॉवर बंकर पर छापामारों के द्वारा 4 अप्रैल को की गयी गोलीबारी में एक पुलिस जवान घायल हुआ था, जो इलाज के लिए चिंतलनार ले जाते समय मर गया।

तोंगपाल एंबुश–ऑपरेशन ग्रीनहंट के श्वेत आतंक का अपरिहार्य परिणाम

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के तोंगपाल के नजदीक जगदलपुर–कोण्टा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 221 पर भारत के भाड़े के अर्धसैनिक बल व जिला पुलिस के संयुक्त बलों पर 11 मार्च, 2014 को जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के कमांडरों व लाल योद्धाओं के द्वारा किये गये साहसिक हमले में सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन के 11 जवान एवं जिला बल के 4 जवान मारे गये। मारे गये जवानों से 6 एके–47, 2 एसएलआर, 7 इन्सास, 3 ग्रेनेड लांचर्स, 1 एलएमजी कुल 19 हथियार, गोली– बारूद एवं अन्य सैनिक सामग्री को पीएलजीए ने जब्त किया। केंद्र–राज्य सरकारों के द्वार जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट के श्वेत आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में पीएलजीए के द्वारा देश भर में चलाये जा रहे कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान का ही हिस्सा है, तोंगपाल एंबुश। इस हमले को सफल बनाने वाले पीएलजीए बलों का हमारा 'प्रभात' अपने सभी पाठकों की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ जय–जयकार करता है। इस हमले ने एक तरफ सैनिक, अर्ध–सैनिक, पुलिस बलों के लौह बूटों तले दबी, कुचली भारत की उत्पीड़ित जनता में उत्साह व जोश भर दिया तो दूसरी तरफ शोषक सरकारों व उनके पिट्ठुओं को हिलाकर रख दिया।

इसी डिविजन में 7 अप्रैल को पीएलजीए ने चिंतागुफा कैंप के बंकर के बाजू में खड़ा सीआरपीएफ के उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी पर फायरिंग करके उसे घायल किया गया था। 9 अप्रैल को चिंतागुफा के आस–पास पीएलजीए ने एंबुश किया था। जिसमें कोबरा फोर्स के तीन जवान मारे गये और पांच घायल हो गये। इस एंबुश में पीएलजीए ने एक टावोर रायफल, एक इन्सास रायफल, इन्सास/टावोर की 572 गोलियां, एके की 47 गोलियां, एसएलआर की 225 गोलियां, एक ग्रेनेड, पांच यूजीबीएल शेल्स, एक सैटेलाइट फोन एवं दो मोबाइल फोन जब्त की।

पश्चिम बस्तर डिविजन के गंगालूर एरिया के कीकिलेर गांव के पास 9 अप्रैल को ही पीएलजीए के द्वारा किये गये हमले में तीन पुलिस जवान घायल हो गये थे। दुग्गयागूडेम में दो जवान घायल हुए।

दरभा डिविजन के दरभा–कामानार के बीच पीएलजीए के एंबुश में पांच जवान मारे गये एवं चार घायल हो गये।

कुलमिलाकर रीजन में 28 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच पीएलजीए ने 24 पुलिस जवानों को खत्म किया जबकि तीस को घायल किया। 28 बंदूक एवं 2,653 गोलियां जब्त की।

पश्चिम रीजन

उत्तर, दक्षिण गढ़चिरोली डिविजनों में सूचना आधारित गश्त बढ़ गया है। एक ही समय में तीन बैच समन्वय के साथ घूमती है। बैचों को बदलते हुए गश्त को लगातार जारी रखा जा रहा है। जमीन पर बलों के गश्त के समय आसमान में यूएवी व हेलिकॉप्टर उड़ान भरते रहते है। आत्म समर्पित व गद्दारों को रास्ता दिखाने वालों के रूप में इस्तेमाल कर रहे है। छापामारों के खत्म करने पैदल रास्तों में एंबुश बैठ रहे है। पुलिस भर्ती पर जोर दे रहे है।

माओवादियों की मदद करने के झूठे आरोप लगाकर इस बीच 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सुरजागढ़ खनन परियोजना को चालू करने के प्रयासों को तेज करते हुए 27 जनवरी को हेड्री में नया पुलिस कैंप खोला गया। 10 दिसंबर को उत्तर गढ़चिरोली के चारगांव एरिया के गोड्डेलिवाय गांव में भी कैंप खोला गया।

भाकपा (माओवादी) के तमाम राजनीतिक अभियानों को विफल करने प्रति अभियान चलाये जा रहे हैं। तरह–तरह के गैर–सरकरी संगठन सक्रिय हो रहे है।

जनजागरण मेड़ावों को अंदरूनी गांवों में विस्तार कर रहे हैं। यह लगातार जारी है। नव जीवन योजना – प्रारंभ कर दी गयी। नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ विशेष बैठकें आयोजित की जा रही है। आपला महाराष्ट्र दर्शन के

तहत लगातार एक के बाद एक बैचों का पर्यटन जारी है। शोधयात्रा के नाम पर एक और किस्म की शांति यात्रा शुरू हुई है। 2 से 11 जनवरी तक यह यात्रा कोरची से सिरोंचा तक चली। किष्टापुर में मुखबिरों पर कार्रवाई के विरोध में जिम्मलगट्टा में भूख हड़ताल आयोजित किये गये। 'माओवादी कॉमरेडों को' संबोधित करते हुए पर्चा, पोस्टर बांट रहे हैं।

कुलमिलाकर शासक वर्ग एक तरफ थाना, कैंपों को बढ़ाते हुए लगातार गश्त अभियानों को तेज करते हुए माओवादी आन्दोलन के खात्मे के लिए दमन में अभूतपूर्व वृद्धि ला रहे हैं तो दूसरी ओर एलआईसी के तमाम दूसरे दावपेंच भी अमल में ला रहे हैं।

शासक वर्गों के इन दमन अभियानों व जनविरोधी दांव–पेंचों को धत्ता बताते हुए प्रति दांव–पेंच के सहारे पीएलजीए ने विगत छह महीनों में दुश्मन के बलों पर मुरमुरी सहित कुछ अच्छी कार्रवाइयों को अंजाम दिया एवं नक्सल विरोधी क्रूर सी–60 कमांडो बलों को जबर्दस्त धक्का पहुंचाया।

पीएलजीए ने तोंडेरा के नजदीक किये हमले में सी–60 कमांडो गिरिधर आत्रम खत्म हुआ और अन्य पांच जवान जख्मी हुए। उसके बाद पीएलजीए के त्वरित कार्यवायी दस्ते ने ग्यारापत्ती मंडाई में दिनदहाड़े सी–60 कमांडो लाल्सू पुंगाटी को खत्म करके एके–47 बंदूक और 164 जिंदा कारतूस जब्त किया। जिम्मलगट्टा, तेरेनार मंडाई और कोडगुल के एर्मुलकस्सा बाजारों में विठल कुडमेथे, रणबीर हलामी, जयकरण नामक तीन एसपीओ को त्वरित कार्यवाही दस्तों ने खत्म किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मई 11 तारीख को चामोर्शि–गोट रोड पर मुरमुरी गांव के नजदीक बारूदी सुरंग विस्फोट किये, जिसमें 7 सी–60 कमांडों मरे और दो गंभीर रूप से जख्मी हुये।

उत्तर रीजन

कॉरपेट सेक्युरिटी के विस्तार के तहत रीजन भर में इस साल अब तक 5 नये कैंप/थाने खोले गये हैं। आरकेबी डिविजन के कच्चे–मुल्ला के बीच भैंस कन्हार के पास, पूर्व बस्तर डिविजन के माडली मोड के पास जो कि रावघाट के नजदीक है, कुव्वेमारी एरिया के सिंगनपुर के पास, कुवानार एरिया के हर्राकोडेर में एवं बारसूर एरिया के बूर्गुम–मुत्तेनपाल के बीच ये कैंप खोले गये हैं।

जनवरी से लेकर अब तक पूरे रीजन में दर्जनों गश्त अभियान संचालित किये गये। संयुक्त डिविजन के आदेर, इंद्रावति, जारा, नेलनार एवं पूर्व बस्तर के कुवानार, खासकर वयानार इलाके में ये गश्त लगातार जारी हैं। गश्त के दौरान गांवों को घेरकर जनता पर गोलीबारी करना, ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करके फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजना, ग्रामीणों की बेदम पिटाई करना आम बात हो गयी है।

इन हमलों के दौरान हाथ लगे युवाओं को गिरफ्तार करके थानों में ले जाकर दबाव–धौंस, धमकी के सहारे आत्मसमर्पण का नाटक कर रहे है। पूर्व बस्तर के वयानार इलाके के सभी थानेदारों का यह रोज का खेल बन गया है। वारण्ट होने, केस करने का डर दिखाकर हजारों रुपयें एंठकर मीडिया के सामने आत्मसमर्पण दिखा रहे हैं।

इस साल पूरे रीजन में पुलिस के 14 हमले हुए। पूर्व बस्तर में 2 जगहों पर जनता पर पुलिस ने गोलीबारी की जबकि पीएलजीए पर तीन हमले हुए जिनमें से एक छोटे टेमुरगांव में 23, फरवरी 2014 को हुई। इस मुठभेड़ में पार्टी सदस्य पंडरू शहीद हुए हैं। एक और मुठभेड़ किसकोडो एरिया के कोरोहवेडा में 11 मई को हुई जिसमें एसीएम कॉमरेड दरबार मंडावी शहीद हुए।

संयुक्त डिविजन में पुलिस के द्वारा आम जनता पर की गयी गोलीबारी की दो अलग–अलग घटनाओं में 5 ग्रामीणों ने अपनी जानें गंवायीं। माड़ डिविजन के करका जंगल में तीन साधारण आदिवासी किसानों–करकानार गांव के 65 साल का लकमो मंडावी, 23 साल का विज्जोन मंडावी (बाप–बेटा) एवं गोटा जमरी का रामसाई कौडो, को मार डाले। आस–पास के ग्रामीण बड़े पैमाने पर जमा होकर नारायणपुर गये। वहां पुलिस के साथ लड़कर लाशों को गांव लाये थे। पुलिस गोलीबारी की एक और घटना में रावघाट इलाके के जंगल में शिकार करने गये आमाकड़ा (किसकोड एरिया) के दो आदिवासी किसान तुलसीराम दर्रो एवं सोमारू को पकड़कर गोली मार दी गयी।

तीन मई को गश्त पर आई पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पीएलजीए के दो कामरेड घायल हुए हैं।

आरकेबी में हुए तीन हमलों में पीएलजीए का एक योद्धा शहीद हुआ, जबकि एक ग्रामीण की भी पुलिस गोलीबारी में मौत हुई।

नारायणपुर के ओरछा से गश्त पर आयी पुलिस पर 30 मई को छोटे तोंडावेडा के पास हमला करके पीएलजीए ने एक पुलिस जवान को मौत के घाट उतारा एवं एक अन्य को घायल किया। तोंडावेडा गांव में डेरा डालकर शाम को वापस जाते समय 3:30 बजे छापामारों ने पुलिस पर हमला किया था। पुलिस जवानों को ग्रामीणों से यह कहते सुना गया कि यदि माओवादी आते हैं तो उन्हें मजा आयेंगा और वे उनसे खेलना चाहते हैं। हमले के बाद पुलिस ने मारे गये जवान की लाश एवं घायल को ढ़ोते हुए रास्ता बदल कर छह घंटे चलकर ओरछा पहुंचे थे जबकि घटनास्थल से ओरछा की दूरी सिर्फ दो घंटे की है।

★

09 जनवरी 2014

सुकदेव उर्फ गुम्माडावेल्लि वेंकटा कृष्ण प्रसाद के आत्मसमर्पण पर

(डीकेएसजेडसी के सदस्य सुकदेव उर्फ गुम्माडावेल्लि वेंकटा कृष्ण प्रसाद के आत्मसमर्पण पर डीकेएसजेडसी के सचिव द्वारा 09 जनवरी, 2014 को मीडिया को जारी बयान)

हमारी पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य व प्रवक्ता–गुड़सा ऊसेंडी के रूप में विगत कुछ सालों से काम करते आये सुकदेव उर्फ गुम्माडावेल्लि वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने राजनीतिक व नैतिक रूप से पतित होकर कम्युनिस्ट मूल्यों व आदर्शों को तिलांजलि देकर पार्टी, जनता व क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ विश्वासघात करके पार्टी छोड़कर भाग गया और 8 जनवरी, 2014 को शोषक–शासक वर्गों के सामने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दिया।

उत्पीड़ित जनता के जल–जंगल–जमीन व मुक्ति के लिए जारी शोषित–शासित वर्गों की जनता के जनयुद्ध को दबाने के लिए देश के शासक वर्गों ने सितम्बर, 2009 से ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर पीड़ित जनता पर युद्ध छेड़ रखा है। पार्टी के नेतृत्व में पी.एलजीए, जनसंगठन, क्रान्तिकारी जनताना सरकारें लुटेरी सरकारों के द्वारा थोपे गये इस नजायज युद्ध का बहादुराना ढंग से, अनन्य कुरबानियां देते हुए मुकाबला कर रही है। जबकि दुसरी ओर कुछ कमजोर लोग इस युद्ध से भयभीत होकर, जान बचाने, स्वार्थ भावना से, सुख–चैन की जिन्दगी जीने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इनमें जीवीके प्रसाद भी एक है। दर असल आजीवन निस्वार्थ भाव से पीड़ित जनता की राजसत्ता के लिए लड़ने व जीने–मरने के दृढ़ संकल्प के साथ काम करना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों का मौलिक गुण है। जब यह गुण लुप्त होता है, इसमें ढ़ीलापन, कमजोरी आती है तब कोई भी शासकों के शरण में ही जाता है। प्रसाद भी इसी राजनीतिक कमजोरी के चलते पार्टी व जनता को धोखा देकर पार्टी छोड़कर चला गया।

जब तक दुनिया में शोषण–दमन जारी रहेगा तब तक जन प्रतिरोध व जन संघर्ष जारी रहेंगे। आखिर, जीत जनता की ही होती है। क्यों कि इतिहास की निर्माता जनता ही है, न कि कुछेक नायक। यह बात दुनिया भर में कइयों बार साबित हो चुकी है। इस ऐतिहासिक सच्चाई को सुकदेव ने भुला दिया। इसीलिए न सिर्फ उसका आ्त्मविश्वास बल्कि पार्टी व जनता पर से उसका विश्वास घट गया था और पार्टी में मौजूद कुछ कमजोर लोगों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा जारी दिवालिया आत्मसमर्पण नीति को जरिया बनाकर प्रसाद दुश्मन के पास पहुंच गया। जनता के बीच में रहकर, जनता पर निर्भर होकर, जनता की सेवा करने की बजाय उसने शोषकों के टुकडों पर पलने, उनसे दया की भीख मांगने व उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। क्रान्तिकारी जनयुद्ध में जान कुरबान करने वाले हजारों वीर योद्धाओं की शहादत से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बजाय उसने पूर्व में आत्मसमर्पित लोगों की राह पकड़ ली।

प्रसाद के जिस पत्नी के साथ आत्मसमर्पण की खबरें मीडिया में छायी हुई हैं, दरअसल वह उसकी पत्नी नहीं है। वह प्रसाद के साथ हमारे प्रेस यूनिट में काम करती थी। प्रसाद की पत्नी – कॉमरेड राजे अभी भी पार्टी में हैं। पत्नी को छोड़कर अन्य महिला कैडर को भगा ले जाना उसके नैतिक पतन की पराकाष्टा थी।

पार्टी में प्रसाद के उत्थान व पतन का लंबा सिलसिला रहा। वह 80 के दशक में पार्टी में भर्ती हुआ था। बालाघाट डिविजन में काम करते समय उसने 1993 में ऐसे समय पार्टी छोड़ी थी जब वहां सांगठनिक व सैनिक रूप से कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। 1993–96 के बीच उसने बाहर साधारण जिंदगी बितायी। इस दौरान वह वहां फिर से पार्टी के संपर्क में आया था। काफी समय उसके व्यवहार को देख–परखने के बाद फिर से पार्टी में भर्ती होने के उसके प्रस्ताव को पार्टी ने मंजूर कर लिया था। तब से लेकर अत्मसमर्पण करते तक वह पार्टी में विभिन्न ओहदों पर काम करता रहा। सितम्बर 2006 में संपन्न दण्डकारण्य के चौथे आधिवेशन में उसे दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। तभी से वह पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारी निभाता आया। इस दौरान वह एक ओर पार्टी के द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारियों को मेहनत व लगन के साथ पूरा करता रहा जबकि दूसरी ओर कुछेक कमजोरियों व गलत रूझानों से जूझता भी रहा। पार्टी की ओर से संबंधित कमेटियों में समय–समय पर उसकी कमजोरियों के खिलाफ आलोचना–आत्मालोचना के जरिए एकता–संघर्ष का तरीका अपनाते हुए संघर्ष चलाया गया था। प्रसाद के अंदर मुख्य रूप से व्यक्तिवाद, नौकरशाही, संकीर्णतावाद, पितृसत्ता आदि गैर–सर्वहारा रूझान मौजूद रही। पेट्टी बूर्जआ अहम के साथ "मैं ही सही सोचता हूं" वाली मानसिकता बढ़ गयी थी।

पार्टी कमेटियों की ओर से प्रसाद की कमजोरियों की न सिर्फ आलोचना होती रही बल्कि उसके अनैतिक व्यवहार के लिए एक बार उसे दण्डित भी किया गया था। उसकी पहली पत्नी के रहते ही 1999 में उसने एक अन्य महिला कैडर के साथ अनैतिक व्यवहार किया था जिसके चलते उसे उसकी जिम्मेदारी से निलंबित किया गया था। आत्मालोचना करके सजा भुगतने के बाद उसे फिर से उसकी जिम्मेदारी दी गयी थी। पहली पत्नी कॉमरेड मिड़को उर्फ सबिता की एक मुठभेड़ में शहादत के बाद 2002 में पार्टी अनुमति से उसने दुबारा

शादी की। दुसरी पत्नी – कॉमरेड राजे को छोड़कर अब जैनी उर्फ ललिता उर्फ संतोषी मरकाम नामक कैडर के साथ भागा है। व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोच्च महत्व देकर पार्टी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने वाले प्रसाद में दरअसल पार्टी के सामने अपने अनैतिक व्यवहार को स्वीकार करके पार्टी के द्वारा की जाने वाली अनुशासन हीनता की कार्रवाई पर अमल करने की हिम्मत नहीं थी। क्रान्ति की विजय का रास्ता सीधा, सरल व सपाट नहीं होता है। वह टेढ़ा–मेढ़ा, उत्तर–चढ़ाव वाला होता है। कठिन व प्रतिकूल परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलाम के क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनों के धक्का खाने के बाद मुठ्ठी भर लोगों ने ही साहस के साथ संघर्ष करते हुए व्यापक किसान सशस्त्र आन्दोलनों का निर्माण किया। 1980 में दण्डकारण्य में प्रवेश करने वाले छोटे दस्तों ने ही आज के दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन की नींव डाली। लेकिन प्रसाद में कठिन व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का साहस नहीं था। बढ़ते दमन की परिस्थितियों में उसके अंदर दबी पुरानी कमजोरी अभर कर सामने आयी। आखिरी सांस तक उत्पीड़ित जनता की सेवा करने वाले हमारी पार्टी नेताओं – कॉमरेड चारू मजूमदार, कॉमरेड कन्नाई चटर्जी, कॉमरेड्स बीके, प्रसाद, पटेल सुधाकर, अजय दा, जानकी दी, आजाद दा, किशनजी, शाकामूरी अप्पाराव, मंगतू, विकास व अपनी अनमोल जाने न्योछावर करने वाले हमारे वीर शहीदों व सलवा जुडूम, ऑपरेशन ग्रीन हंट के पाशविक सैनिक हमलों में अपना सब कुछ खोने वाली, अनगिनत कुरबानियां देते हुए आन्दोलन को आगे बढ़ाने वाली क्रान्तिकारी जनता के द्वारा स्थापित उच्च मूल्य व आदर्शों पर चलने व उनसे प्रेरणा लेकर अपने अंदर मौजूद गैर–सर्वहारा रूझानों, कमजोरियों व खामियों के खिलाफ लड़ते रहने व बाहर आने की बजाय आखिर प्रसाद ने सुख लालसा में राजनीतिक व नैतिक रूप से अधः पतित होकर पार्टी से भाग निकला।

क्रान्तिकारी जन संघर्षों व जनयुद्ध से ही तपकर क्रान्तिकारी नेतृत्व का उदय व विकास होता है। कोई व्यक्ति अपने–आप नेता नहीं बन सकता है। कैडरों व जनता की मेहनत एवं उनके बलिदानों के बगैर नेतृत्व के विकास के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन ने विगत 33 वर्षों में अपने कई लाड़ले लडाकों को क्रान्तिकारी नेतृत्व में विकसित किया है। प्रसाद उन्हीं में से एक था। लेकिन प्रसाद या कोई भी जब भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले क्रान्तिकारी आन्दोलन को छोड़ देता है तब वह उसे इतिहास के कुड़ेदान में फेंककर आगे बढ़ता है। उत्पीड़ित जनता का क्रान्तिकारी आन्दोलन अपनी जरूरत के नेतृत्व को लगातार विकसित करते रहता है।

दण्डकारण्य की क्रान्तिकारी जनता प्रसाद जैसे लोगों के आत्मसमर्पण से न दिग्भ्रमित होती है और न ही हताश होती है। वह 1910 के महान भूमकाल लड़ाई की प्रेरणा से ओतप्रोत है। गुंडाधूर, गेंदसिंह, वीर नारायणसिंह जैसे वीर योद्धाओं की विरासत के परचम को उठायी हुई है। आत्मसमर्पित लोगों से नफरत करती है। आत्मसमर्पण करके दुश्मन की ओर खड़े रहने वाले लोगों को सरेआम थप्पड मारने, उन्हें जान से मारने की मांग करने जैसी घटनाएं दण्डकारण्य के गांवों में देखने को मिलती हैं। इस तरह सबक सिखाने की जनता के उपरोक्त व्यवहार देशभर में अनुकरणीय है।

पार्टी नेतृत्व में से कुछेक लोगों का राजनीतिक पतन व आत्मसमर्पण हमारी पार्टी व क्रान्तिकारी जनता के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। आत्मसमर्पण करने वालों में प्रसाद न पहला है, न ही आखिरी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से लेकर अब तक के पार्टी इतिहास में ऐसे ढ़ेरों अनुभव हैं। इन अनुभवों से सबक लेते हुए, गैर–सर्वहारा रूझानों से लड़ते हुए पार्टी मजबूत होते आ रही है। न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन का इतिहास भी इसका गवाह है।

अपनी कमजोरियों पर परदा डालने प्रसाद ने अपने आत्मसमर्पण के लिए आम जनता पर हो रहे हमलों व पार्टी की कार्यनीति व पॉलसियों पर केंद्रीय कमेटी के साथ उसके मतभेदों को वजह बताया जो कि सफेद झूठ है। उसने कभी भी पार्टी कमेटी की बैठकों में कार्यनीति व पॉलसियों पर मतभेद दर्ज नहीं किया। न ही इस संबंध में लिखित में कुछ पेश किया। यदि मतभेद वाली बात सही है तो वह पार्टी में रहकर लड़ सकता था। पार्टी में मतभेदों पर अंदरूनी लड़ाई का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। पार्टी संविधान इसकी अनुमति देती है। पार्टी के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। हर बार पार्टी अंदरूनी संघर्ष से तपकर व अपने क्रान्तिकारी व्यवहार के अनुभवों से अपनी लाइन व पॉलसियों को विकसित व मजबूत करती आयी। कार्यनीतिक मामलों पर कमेटी बैठकों में हमेशा बहस होती है और जनवादी केंद्रीयता जो कि पार्टी का संचालक नियम है, के तहत बहुमत व अल्पमत के हिसाब से निर्णय लिये जाते हैं।

रही बात आम नागरिकों पर हमलों की, पार्टी व पीएलजीए की भूलचूक की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे जनता की जान–माल को नुक्सान पहुंच रहा है। ऐसी घटनाओं के लिए पार्टी जब का तब सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है और उन घटनाओं का विश्लेषण करके सबक लेती है। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई भी करती है। प्रवक्ता की हैसियत से स्वयं प्रसाद ने भी ऐसी घटनाओं पर खेद जताया था। हमारी पार्टी पीड़ित–शोषित वर्गों की जनता की मुक्ति व उनकी जान–माल की रक्षा की खातिर लड़ रही है। उन्हें किसी भी तरह के नुक्सान पहुंचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए प्रसाद जानबूझकर, अवसरवादी ढंग से झूठ बोल रहा है। शोषक–शासकों के दुष्प्रचार का राग अलाप रहा है।

राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के समर्थन में 23 से 29 मार्च तक संघर्ष सप्ताह मनाने, 29 मार्च, 2014 को दण्डकारण्य बंद सफल बनाने का आह्वान

(20 मार्च, 2014 को प्रवक्ता के द्वारा मीडिया को जारी बयान)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जनता, जनवादी – प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, वकीलों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं एवं जेल बंदियों के परिवारजनों का आह्वान करती है कि वे आगामी 23 से 29 मार्च के बीच राजनीतिक जेल बंदियों के अधिकारों के समर्थन में संघर्ष सप्ताह मनावें एवं 29 मार्च को एक दिनी दण्डकारण्य बंद सफल बनावें। संघर्ष सप्ताह के दौरान जगह – जगह जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन, सड़क मीटिंग करें, जेल बंदियों के संघर्षों की मदद् में भाईचारा प्रकट करें।

देश के सामंती, दलाल बड़े पुंजिपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जन विरोधी केन्द्र–राज्य सरकारों के द्वारा बड़े बांधों, वृहत् कारखानों व बड़ी खनन परियोजनाओं के लिए जनता के जल–जंगल –जमीन को हड़पने, तद्वारा होने वाले विस्थापन के विरोध में जारी जन संघर्षों, प्रगतिशील – जनवादी आन्दोलनों के दौरान एवं माओवादी मामलों में राज्य यंत्र के द्वारा जबरन गिरफ्तार करके फर्जी मुकद्दमों में फंसाकर जेलों में बंद करना लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की पांचों केन्द्रीय कारागारों, जिला जेलों व उप जेलों में हजारों लोग बंद हैं। इनमें से अत्यधिक लोग आदिवासी हैं। हमारे आन्दोलन के उन्मूलन के लिए जारी देश व्यापी चौतरफा सैनिक हमले के तहत राज्य के संघर्ष इलाकों में दसियों हजार अर्ध–सैनिक बलों को तैनात करते हुए, राज्य पुलिस बलों को लगातार बढ़ाते हुए कार्पेट सेक्युरिटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नये पुलिस थानों व कैम्पों को स्थापित किया जा रहा है। गांवों पर लगातार हमलें, अवैध गिरफ्तारियां, फर्जी केसें, झूठी व पुलिसिया गवाही के आधार पर लंबी व उम्र कैद की सजाएं देना बेरोकटोक जारी है।

2007 में गिरफ्तार हमारी महिला कॉमरेड निर्मला जो कि जगदलपुर जेल में बंद हैं, के ऊपर 145 केस लगाए गये थे जिनमें से अब तक वो सौ से ज्यादा केसों में बाइज्जत बरी हो गई हैं। इसमें करीबन 7 साल का समय लग गया है। इस एक उदाहरण से यह स्पष्ट है कि सरकार माओवादियों को झूठे मामलों में कैसे फंसा रही है। हमारी महिला कार्यकर्ता कॉ. मालती को सलवा जुडूम के अत्याचारों पर आधारित सीडी के वितरण के मामलें में बिना गवाही के ही 10 साल की सजा सुनाई गयी। जबकि कोर्ट में मालती के द्वारा सिडी बनाना न ही उसका वितरण करना साबित हुआ था। हथियारों से संबंधित एक और फर्जी मामले में झूठी व पुलिसिया गवाही पर हमारी महिला कार्यकर्ताएं मालती, मीना सहित स्वतंत्र पत्रकार प्रपुल्ल झा, बेगुनाह युवक– प्रतीक झा, सिद्धार्थ शर्मा को जबरन 7–7 साल की सजा दी गयी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इनकी अपील को आंख मूंदकर खारिज किया है। बिलासपूर के दो व्यवसायी भाइयों व रायपुर के एक टेलर को जबरन 3–3 साल की सजा सुनायी गयी। हमारे कार्यकर्ता कॉ. रैनू, कॉ. मधु सहित दो ग्रामीणों को हत्या के एक फर्जी केस में कांकेर कोर्ट के द्वारा फर्जी गवाही पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। इस तरह के दसियों उदाहरण हैं। कॉ मरकाम गोपन्ना उर्फ सत्यम रेड्डी, कॉ जयपाल रेड्डी सहित सैकड़ों लोग दसियों केसों में बरी होने के बावजूद बचे हुए मुकद्दमों के फैसले के इंतजार में हैं।

जैनी उर्फ संतोषी मरकाम हमारे प्रेस यूनिट में डीवीसी स्तर की कॉमरेड थी। उसने पार्टी नियमों का उल्लंघन करके, अंध आराधना एवं पितृसत्तात्मक विचारों के प्रभाव से प्रसाद के साथ चली गयी। उसने अपने स्वार्थ के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन को छोड़कर जनता के साथ विश्वासघात किया।

अंततः मैं पार्टी कैडरों से अपील करता हूं कि वे शहीदों की राह पर आखिरी सांस तक जनयुद्ध में डटे रहे और उत्पीड़ित जनता की सेवा करें। जनता से अपील करता हूं कि वह आत्मसमर्पण से नफरत करे, आत्म सम्मान के लिए लड़े व जिये। आत्मसमर्पण का मतलब है – दुश्मन के झूठन पर निर्भर होना, दुश्मन के ईनाम का मतलब है – ईमान बेचकर जीना, बेमान बनना। आत्मसमर्पण से मिलने वाली अपमानित जिंदगी से अच्छा है लड़कर मरना। पीड़ित जनता के लिए जीना और मरना हिमालय से भी वजनदार होता है जबकि शोषकों के लिए जीना या मरना पंख से भी हल्का होता है।

मैं जनवादी व प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, लेखक, कलाकारों, मीडिया कर्मियों से अपील करता हूं कि वे प्रसाद के आत्मसमर्पण के पीछे की असलियत को जानें, समझें व उत्पीड़ित जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन के पक्ष में खड़े रहे।

रामन्ना

सचिव

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

बिना गवाही, फर्जी या पुलिसिया गवाही के आधार पर लंबी सजाएं सुनाने वाले जन विरोधी जजों को हम सावधान करते हैं कि कल की जन अदालतों में सजा भुगतने तैयार रहे।

दरअसल हमारे गिरफ्तार साथियों व संघर्षरत जनता को जबरन जेलों में सड़ाने की साजिश के तहत ही दसियों झूठे केसों में फंसाया जाता है। साथ ही एस्कार्ट न होने का बहाना करके पेशियों में लगातार नहीं ले जाया जाता है जिससे साधारण केसों में भी बरसों बंद रहना पड़ता है। सजा होने पर भी 6 महीने से 2–3 सालों में छुटने वालों को भी इस तरह 5–6 साल जबरदस्ती बंद रखा जाता है। चार्ज शीट पेश करने में देरी करने से लेकर पेशी में न ले जाने एवं छूटने के बावजूद जेल गेट से ही दोबारा गिरफ्तार करके झूठे व नये केसों में फंसाया जाता है। भिलाई से गिरफ्तार महिला कॉमरेड पद्मा को बाइज्जत बरी होने के बावजूद फिर से केस लगा कर जगदलपुर जेल में बंद किया गया है।

संघर्ष इलाकों में जारी अवैध व बेरोकटोक गिरफ्तारियों के चलते यहां की जनता खासकर आदिवासी युवाओं से जेलें पट पड़ी हैं। 110, 109, 151 धाराओं के तहत सैकड़ों आदिवासी युवाओं को जेलों में सालों सड़ाया जा रहा है। क्षमता से काफी अधिक संख्या में–दोगुने, तीन गुने, कहीं – कहीं तो चार गुने संघर्षरत लागों को जेलों में ठुंसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की जेलों की अव्यवस्था व असुविधाओं का आलम यह है कि वहां आमानवीय, दयनीय व पाशविक परिस्थितियां बनी हुई हैं। जेलें दरअसल दमनकारी राज्य यंत्र का ही हिस्सा हैं। जेलों को सुधार गृह कह कर प्रचारित करना न सिर्फ बेमानी है बल्कि संघर्षरत इंसानों को तोड़कर रख देने के शासक वर्गों की साजिश पर परदा डालने के लिए ही है। अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल को नाम मात्र के संशोधनों के साथ यथावत लागू किया जा रहा है। एक तो इन मैनुअलों में बंदियों के साथ जनवादी व सम्मानजनक व्यवहार से संबंधित बदलावों के अलावा आज के मूल्य सूचकांक एवं महंगाई के मुताबिक काफी संशोधन करने की जरूरत है तो दुसरी ओर वर्तमान जेल मैनुअलों का भी पालन कहीं नहीं हो रहा है। खाने–पीने, पहनने–ओड़ने, रहने, पढ़ने – लिखने अदि बंदियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं में काफी व व्यापक कटौती करके जेल अधिकारी से लेकर गृह मंत्री तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं। कीड़े पड़े चावल, दाल के नाम पर सिर्फ पीला पानी, अन्य दैनिक उपयोगी सामान जैसे तेल, साबून, पेस्ट आदि को जेल मैनुअल के कोटे से काफी कम या नाम मात्र का दिया जाता है। पेपर, पत्रिका, किताब, टीवी समाचार आदि नसीब नहीं होते हैं।

दूसरी ओर कुछ जेलों में केंटीन चलाये जाते हैं जहां अच्छा भोजन व अन्य सामग्री उन बंदियों को उपलब्ध होती है जो मुहमांगी दाम दे सकते हैं। जहां केंटीन नहीं हैं, वहां भी खाना सहित सभी सामान खरीदने से मिल सकते हैं बशर्ते जेल वार्डरों, नंबरदारों को उनका सेवा शुल्क अदा किया जाए।

सुविधाओं की मांग करने वालों को काल कोठरी (सिंगल सेल) में बंद किया जाता है। दुसरों से मिलने नहीं दिया जाता है। जेल अधिकारियों के इन कारनामों को उजागर करने की हर कोशिश को दबाने के लिए पगली घंटी बजाया जाता है और सभी बंदियों को लॉकअप करके बाद में बैरकें से एक–एक को निकालकर बेदम पिटाई की जाती है। इस तरह बंदियों में दहशत फैलाया जाता है और जेल प्रशासन के खिलाफ उठने वाली हर आवज को दबाने की कोशिश की जाती है।

जेल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं नाम मात्र की हैं। जेल के बाहर के अस्पतालों में बंदी मरीजों को नहीं ले जाया जाता है। इलाज के अभाव में जेलों में बंदियों की अकाल व जबरन मौतें आम बात हो गयी हैं। कोण्डागांव जिलें के पदेली निवासी आदिवासी किसान बलिराम कश्यप जिन्हें 2012 में तीसरी बार माओवादी होने के झूठे आरोप में जगदलपुर जेल में बंद किया गया था, की 2013 में मौत हो गयी। हमारे कार्यकर्ता रामलाल की 12 जुलाई, 2013 को जगदलपुर जेल में मौत हो गयी। महिला बंदियों की भूख हड़ताल के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां एक दिन बाद ही उनकी शहादत हुई।

सभी जेलों खासकर केन्द्रीय कारागारों में लघु उद्योग धंधे चालू हैं जहां सजायाफ्ता बंदियों के अलावा विचाराधीन बंदियों से भी जबरन काम कराया जाता है और रोजी के नाम पर 10 रु. प्रति दिन दिया जाता है। कुछ जेलों में उससे भी कम। जेलों की साफ–सफाई, एवं अन्य तमाम काम तो मुफ्त में ही कराया जाता है।

जेलों में बंद अत्यधिक लोग आदिवासी हैं और अंदरूनी इलाकों के हैं इसलिए उनके परिजनों के लिए मुलाकात के लिए जाना मुश्किल है। विधिक सहायता पहुंचाना भी कठिन है। मुलाकात के लिए जाने वालों से जेल में पैसे एंठ लिया जाता है। मुलाक़ात में सीधी बात नहीं करने देते हैं। गुप्तचर विभाग के पुलिस अधिकारियों के सामने ही जेल बंदियों को मुलाक़ातियों के साथ बात करना पड़ता है।

जेलों में जेल अधिकारियों के इशारे पर नंबरदारों की गुण्डागर्दी बेरोकटोक जारी है। क्रान्तिकारी आन्दोलन से भागकर आत्मसमर्पण करके प्रतिक्रान्तिकारी बनने वाले लोगों को जेलों में भेजकर उनके द्वारा जेल बंदियों को मुखबिरतंत्र में जबरन शामिल कराने के गैर–कानूनी प्रयास जारी हैं।

फर्जी लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान

(3 अप्रैल, 2014 को प्रवक्ता के द्वारा प्रेस को जारी बयान)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत देश की तमाम जनता का आह्वान करती है कि वह आगामी 16वें लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करें क्योंकि वर्तमान में जो लोकतंत्र अमल में है, वह फर्जी है। दरअसल वह देश के शोषक–शासक वर्गों का लूट तंत्र और दमन तंत्र है। हमारी पार्टी संघर्ष इलाकों की जनता का आह्वान करती है कि वह जन विरोधी, दमनकारी, देशद्रोही व फासीवादी कांग्रेस और भाजापा को मार भगायें और गांवों में घुसने मत दें। वोट मांगने आने वाली अन्य तमाम पार्टियों को जन अदालत के कटघरे में खड़ा करें। गांवों पर हमलों, अवैध गिरफ्तारियों, फर्जी मुठभेड़ों, नरसंहारों आदि राज्य दमन, विस्थापन एवं जन हित के अन्य मुद्दों पर उनके रूख के बारे में सवाल करें व जवाब मांगे। चुनावी राजनीति को छोड़कर जन संघर्षों की मदद में ही गांवों में घुसने की समझाइश देकर भेज दें।

देश के लुटेरे शासक वर्गों–सामंती, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग व उनके साम्राज्यवादी आकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र–राज्य सरकारों के द्वारा लोकतंत्र के नाम पर देश के चार उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर, किसान, निम्न पूंजीपति व देशी पूंजीपति की बहुसंख्यक जनता की लूट, दमन, शोषण व शासन जारी है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में शोषक–शासक वर्गों की राजसत्ता को उखाड़ फेंककर शोषित–शासित जनता की असली जनवादी राजसत्ता की स्थापना के लिए क्रांतिकारी जनयुद्ध जारी है। दण्डकारण्य सहित देश के विभिन्न इलाकों में असली आजादी, असली लोकतंत्र एवं स्वावलंबन पर आधारित असली विकास के रास्ते में क्रांतिकारी जनताना सरकारों का गठन किया जा रहा है। दंडकारण्य में गांव, एरिया, डिविजन स्तरों पर ये सरकारें काम कर रही हैं। शोषक–शासक वर्गों के झूठे लोकतंत्र का सही व एकमात्र विकल्प ये ही हैं। ये जन राजसत्ता के अंग ही सही मायने में–रूप व सार में जनता के जनवाद को अमल करेंगे। दण्डकारण्य की जनता को चाहिए कि वह इन्हें मजबूत करें व फैला दें। देश की जनता से हम अपील करते हैं कि वह इन नई जन राजसत्ता के अंगों के बारे में जाने व समझें। देशव्यापी क्रांतिकारी जनयुद्ध में शामिल होवें और इस नये विकल्प को अमल में लाने के काम में आगे बढ़े।

दरअसल 1947 में जो आजादी मिली थी, वह झूठी व नाममात्र की है। अंग्रेजों से मिलीभगत करके देश की आजादी के साथ गद्दारी करने वाले भारत के दलाल बड़े पूंजीपति व सामंतियों को सत्ता हस्तांतरण हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्यवादियों को मार भगाने की लड़ाई की बजाय उनके साथ सांठगांठ करके भारत सरकार कानून, 1935 के अमल में आने से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ते तक शासन में हिस्सेदार बनते रहे। इसीलिए हमारी पार्टी यह मानती है कि 1952 से जारी संसदीय प्रणाली असल में संसदीय लोकतंत्र या बुर्जुआ लोकतंत्र ही नहीं है, यह फर्जी संसदीय

जेलों में मौजूद अव्यवस्था, समस्याओं व जेल अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ जेल बंदी कॉमरेड्स हिम्मत व साहस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इनके संघर्षों को जेल अधिकारी दमन, दबाव, धौंस के जरिए कुचलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 2013 में 18 से 28 फरवरी के बीच जगदलपुर की महिला जेल बंदियों ने अभुतपुर्व भूख हड़ताल की थी। नागपुर केंद्रीय कारागार की महिला बंदियों ने 2013 में जेल अधिकारियों के अत्याचारों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन किया था।

मीडिया कर्मियों से हम अपील करते हैं कि वे राजनीतिक जेल बंदियों की मांगों व उनके संघर्षों को जनता के सामने लावें।

चूंकि माओवाद उत्पीड़ित जनता का राजनीतिक सिद्धांत है और हमारी पार्टी चार उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर, किसान, छोटे पूंजिपति व देशी पूंजिपति की नवजनवादी राजसत्ता के लिए लड़ रही हैं, इसलिए माओवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों व साथ ही जनवादी, प्रगतिशील आन्दोलनों एवं जल–जंगल–जमीन पर अधिकार के लिये जारी संघर्षों के दौरान राज्य दमन के तहत जेलों में बंद तमाम लोगों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने व जेलों में बंद तमाम आदिवासियों को निशर्त रिहा करने की मांग करने हमारी पार्टी जनता, जनवादी–प्रगतिशील ताकतों, मानवाधिकार संगठनों व कार्यकर्ताओं से अपील करती है।

जेल बंदियों पर अत्याचार करने वाले भ्रष्ट जेल अधिकारियों व उनके दलाल नंबरदारों को हम चेतावनी देते हैं कि वे अपने व्यवहार को सुधारें वरना जन अदालत में गंभीर सजा भुगतने तैयार रहे।

हमारी पार्टी जनता का आह्वान करती है कि वह राजनीतिक जेल बंदियों के अधिकारों के समर्थन में मार्च 23 से 29 तक संघर्ष सप्ताह मनावें, 29 मार्च को दण्डकारण्य बंद सफल बनावें। प्रगतिशील वकीलों से अपील करती है कि वे राज्य यंत्र के दमन के शिकार होकर जेलों में बंद लोगों को विधिक सहायता पहुंचाने आगे आवें। ★

लोकतंत्र है। आज की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था अर्ध–सामंती और अर्ध–औपनिवेशिक है। सामंती वर्ग, दलाल नौकरशाही पूंजीपति वर्ग ही सही मायने में हमारे देश के शोषक–शासक वर्ग हैं। ये ही भारत की जनता के असली दुश्मन हैं। 1950 में भारत के संविधान के नाम पर जिसे अमल में लाया गया वह ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि कई युरोपीय देशों के संविधानों से लिये गये धाराओं का मिश्रण मात्र है। स्वयं संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के अनुसार संविधान सभा के बहुमत के दबाव में संविधान लिखा गया था। वास्तव में भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों व आदिवासियों व पिछडी जातियों के लिए बाबासाहेब की जिद में जोडे गये आरक्षण की सुविधा के सिवाय, उत्पीड़ित जनता के लिए कुछ भी नहीं है।

1952 से लेकर अब तक यानी 15वी लोकसभा तक इन चुनावों के जरिए इस देश पर शासन करने वाली पार्टियां चाहे कोई भी हो–सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही कांग्रेस या उसके गठबंधन वाली यूपीए की पार्टियां हो या फिर भाजपा या उसके गठबंधन वाली एनडीए की पार्टियां हो सभी ने हमेशा जन विरोधी, देशद्रोही, दमनकारी, फासीवादी नीतियों पर ही अमल करती आयीं। जन भावनाओं, जन आन्दोलनों, किसान सशस्त्र संघर्षों के दबाव में संविधान की पीठिका में लिखी गयी बातों– संप्रभुता, धर्म निरपेक्षता, सामाजवादी गणतंत्र के ठीक विपरीत, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए काम करती आयीं।

देश के शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों ने देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। धर्म निरपेक्षता की रट लगाते हुए हमेशा हिन्दू धार्मिक कट्टरता को ही हवा देती रहीं। धार्मिक अल्प संख्यकों– सिख, मुसलमान, ईसाइयों पर देश की कई जगहों में हमलों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि 1984 में सिखों के नरसंहार का कांग्रेस ने एवं 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का भाजपा ने प्रत्यक्ष नेतृत्व किया था।

भारतीय अर्थ व्यवस्था को साम्राज्यवादी अर्थ व्यवस्था की जंजीर की कड़ी के रूप में जोड़कर साम्राज्यवादी ताकतों के आर्थिक हितों के अनुरूप उसे ढ़ालने के लिए देश में जन विरोधी वैश्वीकरण–निजीकरण–उदारीकरण की नीतियों पर जोर–शोर से अमल करती आ रही हैं। साम्राज्यवादी लूट व विदेशी पूंजी निवेश के लिए देश के उद्योग–धंधों, खेती–बाड़ी व सेवा क्षेत्र के दरवाजों को खुला किया गया। इतना ही नहीं, हाल के वर्षों में खुदरा व्यापार को भी कारपोरेट घरानों के हवाले किया गया है।

केंद्र–राज्य सरकारों की आर्थिक, औद्योगिक, खनन, कृषि नीतियां साफ तौर पर सामंती, बड़े औद्योगिक घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं। विगत 5 सालों में उद्योगपतियों को करों में लाखों करोड़ रुपयों की छूट दी गयी। जबकि किसानों व मध्यम वर्ग के लोगों को दी जाने वाली सब्सिडियों में भारी कटौती की गयी। जनता के पैसो से पूंजीपतियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर – एक्सप्रेस हाईवेज, फोरलेन सड़कें, पुल–पुलिया, मोबाइल टावरें, बड़े बांध, बैंक, थानें आदि का निर्माण जोरों पर है। विनिवेशीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। बड़ी खनन परियोजनाओं को जनधन से लेकर कच्चा माल तक सौंपते आये। अब तो खदानों को ही उन्हें सौंपा जा रहा है। बाल्को की माइनपाट खदान सहित दसियों हजार करोड़ की संपत्ति को महज 550 करोड़ में– कौड़ियों के भाव पूंजीपति अनिल अग्रवाल को सौंपा गया था। बड़े पूंजीपतियों के बड़े कारखानों, बड़े खदानों व उनके लिए जरूरी बिजली व पानी की आपूर्ति हेतु बड़े बांधों के निर्माण के लिए आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता के लाखों एकड़ की जमीन को छीना जा रहा है। सार्वजनिक हित के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों–5वीं अनुसूची, पेसा कानून आदि का खुला उल्लंघन करते हुए फर्जी व पुलिसिया ग्रामसभाओं का संचालन करते हुए ये सारे जन विरोधी कार्य किये जा रहे हैं।

देशी, विदेशी पूंजीपतियों के लिए जमीन से लेकर तमाम ढ़ांचागत सुविधाओं के साथ 400 विशेष आर्थिक जोनों को मंजूरी दी गयी। हजारों एमओयू किये गये। इनकी शर्तें देश की जनता के लिए गोपनीय क्यों रखी गयी हैं? असल में ये शर्तें जन विरोधी हैं। देश के बड़े पूंजीपति व विदेशी पूंजीपति देश की संपदाओं को बेरोकटोक लूट रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम मंत्रालयों के घोटालों–आदर्श हाउसिंग एवं अन्य रक्षा घोटालों, 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला आदि में लाखों करोड जन धन को लूटा गया। यह लूट बरोकटोक जारी है। राजनेताओं, नौकरशाहों के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसके खिलाफ लोगों में व्याप्त आक्रोश व इससे उपजे आन्दोलन का फायदा उठाकर बनी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही, चाहे कुछ ही दिनों के लिए क्यों न हो। वह भ्रष्टाचार मुक्त देश का भ्रामक प्रचार करते हुए देश में सत्तारूढ़ होने का सपना देख रही है।

सरकारों की जन विरोधी नीतियों के चलते इस देश के शोषित–शासित व उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ एवं देशी पूंजीपति की जनता जो कि देश की बहुसंख्यक जनता है, का जीवन दिन ब दिन दूभर होता जा रहा है। काम के घंटों में बढ़ोत्तरी, वेतन भत्तों व रोजी–मजदूरी में कटौती, सरकारों की पूंजीपति परस्त व मजदूर विरोधी नीतियों, औद्योगिक सुरक्षा उपायों में जानबूझकर बरती जाने वाली अपराधिक लापरवाही, छंटनी, ले ऑफ, तालाबंदी, ठेकेदारी प्रथा, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों के

चलते मजदूरों खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत दयनीय बनी हुई है।

देश की कृषि को कारपोरेट संस्थाओं के लाभ के अनुकूल बदलने, खाद,बीज आदि के मामले में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों में कटौती या बंद करने, सूदखोरों–बैंकों के कर्ज व ब्याज का बोझ, लागत खर्च में बढ़ोत्तरी, सिंचाई का अभाव, अकाल व बाढ़, फसलों का उचित समर्थन मूल्य न मिलने के चलते लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आत्महत्या की दर में छत्तीसगढ़ अव्वल है। कृषि प्रधान देश में अन्नदाताओं की आत्महत्याएं शासकों के किसान विरोधी व अपराधिक चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। जोतने वाले को जमीन न मिलने, साल भर काम न मिलने की वजह से ग्रामीण इलाकों से भूमि हीन व गरीब किसान बड़ी तादाद में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। छग के गांवों से हर साल दिसंबर से जून के बीच 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण घर बार, बूढ़ों–बच्चों को छोड़कर काम की तलाश में जाते हैं जहां शोषण, लूट व अत्याचारों के शिकार होते हैं। केंद्र सरकार की बहुप्रचारित मनरेगा एवं अन्य योजनाओं, छत्तीसगढ़ सरकार की ढेरों झूठी सुधार योजनाओं की बस की बात नहीं है– पलायन को रोकना, गरीबी को दूर करना, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। क्यों कि ये सारी योजनाएं सिर्फ जनता को भरमाने के लिए हैं। एक तरफ मुठ्ठीभर लोगों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति व संसाधनों की बेइंतहा लूट तो दूसरी ओर बहुसंख्यक गरीब जनता को इनसे वंचित रखा जाना जब तक जारी रहेगा, तब तक अमीर धरती के गरीब लोगों की विडंबना खत्म नहीं होगी। संसाधनों का इस्तेमाल समस्त जनता के हित में हो तभी यह विडंबना खत्म होगी। यह तभी संभव है जब उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर, किसान, पेट्टी बुर्जुआ व देशी बुर्जुआ के संयुक्त मोर्चे की सरकार बनती हो और उसका तानाशाही कायम होती हो।

सरकारों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े औद्योगिक घरानों के अनुकूल आर्थिक नीतियों के चलते महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल की दरें लगातार बढ़ायी जा रही हैं जिससे तमाम अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे मजदूर–किसान व मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक की शर्तों के तहत व्यवस्थापन खर्च को कम करने के नाम पर शिक्षकों व तमाम सरकारी विभागों के कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति पर देश भर की सरकारों ने पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिये। शिक्षाकर्मी, शिक्षा गारंटी, जन भागीदारी, संविदा नियुक्ति, कैजूअल कर्मचारी, दैनिक वेतन भेगी कर्मचारी आदि के नाम पर न्यूनतम वेतन व रोजी पर काम लिया जा रहा है। इससे शिक्षक व कर्मचारियों में न सिर्फ रोश है बल्कि हर साल अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकारों की ये कर्मचारी विरोधी नीतियां दरअसल अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही है।

देश के सौ बड़े दलाल पूंजीपति घरानों की संपत्ति कुल जीडीपी का एक चौथाई है। सुनिल मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, आदि गोदरेज, शिव नाडार, पल्लोनजी मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, दिलीप सांघवी, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी– इन नौ बड़े उद्योगपतियों की कुल संपत्ति 672 हजार करोड़ रुपये हैं। देश के अरबपतियों की संपत्ति पिछले 15 सालों में 12 गुना बढ़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारों की नीतियां किसके अनुकूल हैं। गरीबों के इंदिरा आवास के लिए 40 हजार रुपये जबकि मुकेश अंबानी निवासरत है, करीबन एक हजार करोड़ के कीमती अंटेल्ला में।

देश के छोटे व मध्यम पूंजीपति भी सरकारों की बड़े पूंजीपति व बहुराष्ट्रीय कंपनी परस्त नीतियों के चलते दम घोंटू स्थिति में हैं। देश के करीबन 2 लाख से ज्यादा छोटे व मध्यम उद्योग बिजली, कच्चा माल की आपूर्ति के अभाव में बंद पड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 सालों में पंजाब में 18,770 उद्योग बंद हो गये हैं। छत्तीसगढ़ के सौ से ज्यादा स्पंज आयरन एवं अन्य उद्योग सिर्फ लौह अयस्क व बिजली की आपूर्ति न होने के कारण बंद पड़े हैं। 5 से 6 हजार रुपये प्रति टन बाजार दर वाले लौह अयस्क को 500 रुपए प्रति टन के हिसाब से जापान व चीन को प्रति दिन दसियों हजार टन माल निर्यात करने वाली सरकार (एनएमडीसी) छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों की इस मांग को नकार रही है कि उन्हें बैलाडीला से सिर्फ 10 फीसदी लौह अयस्क की आपूर्ति की जाए। बड़े उद्योगों में मशीनीकरण, कंम्यूटरीकरण के चलते मजदूरों की छंटनी व बरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पूंजी निवेश के विलोम अनुपात में रोजगार की उपलब्धता है।

महिलाओं पर अत्याचार बेरोकटोक जारी हैं। इसमें राज्य हिंसा सबसे आगे है। संघर्ष इलाकों में महिलाओं पर अत्याचार को जन दमन के औजार के रूप में सरकारी सशस्त्र बल इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर, शाला–आश्रम– छात्रावासों में बालिकाओं–युवतियों पर होने वाले अत्याचार कुल मिलाकर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के लिए शोषक–शासक वर्ग व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें ही जिम्मेदार हैं। आर्थिक क्षेत्र में अपने शोषण व लूट को जारी रखने व विरोध की मानसिकता को भटकाने के लिए सामंती कुसंस्कृति व साम्राज्यावादी विषैली संस्कृति को पलने–फूलने व बढावा देने वाली सरकारें जनाक्रोश को ठंडा करने, आन्दोलनों को भटकाने के लिए ही निर्भया जैसे कानून बनाती हैं।

दरअसल, ये सरकारें उत्पीडित जनता की मूलभूत

समस्याओं को हल नहीं कर सकती। बुनियादी जरूरतों–खाना, कपड़ा, मकान, पेयजल, इलाज, शिक्षा, रोजगार, इज्जत से जीने के अवसर आदि को पूरा नहीं कर सकती हैं। इस शोषण मूलक अर्ध सामंती, अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था में कुछ सुधारों से यह संभव नहीं है। इस शोषण मूलक व्यवस्था का अमूलचूल परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता है जो सिर्फ क्रांतिकारी जनयुद्ध के जरिए ही संभव है।

ढोंगी लोकसभा दरअसल जन प्रतिनिधियों की सभा नहीं, यह बलवाई, गुण्डों का अड्डा है। यह चुनाव एक नौटंकी है, धोखा है। उसल में यह हर पांच साल या कम–ज्यादा समय में शासक वर्गों का कौन सदस्य जनता को लूटने व उनका दमन करने के बारे में लोकसभा में बैठकर निर्णय लेगा, इसका फैसला करने के लिए ही होता है। यानी वोट डालने या चुनाव में भाग लेने का मतलब है, आगामी पांच साल तक अपने शोषण, व दमन करने वाले को चुनना।

लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभाओं में बैठकर ये बलवाई, गुण्डे, अत्याचारी व भ्रष्ट लोग कानून बनाकर जन धन को लूटाते हैं, लूटते हैं, घपले–घोटाले करते हैं, काली कमाई को स्विस बैंकों में जमा करते हैं। और विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने कानून बनाते हैं जैसे यूएपीए, मकोका, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून आदि। यही सब करने इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किये जाते हैं। 15वीं लोकसभा के 543 सदस्यों में से भाजपा के 44 एवं कांग्रेस के 44, शिवसेना के 9 सहित कुल 162 आपराधिक चरित्र के हैं। राज्य सभा के 232 सदस्यों में से 40 दागी हैं। इनमें से 100 से ज्यादा सदस्यों पर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलें दर्ज हैं। 15वीं लोकसभा के संचालन के लिए कुल 10 हजार करोड़ खर्च हुए। जन समस्याओं पर वहां चर्चा एवं हल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

सत्ता की भोगविलासिता की होड़ में ये पार्टियां आपस में लड़–भिड़ती हैं लेकिन जन आन्दोलनों, क्रांतिकारी आन्दोलनों को कुचलने में, प्रगतिशील–जनवादी ताकतों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दबाने में ये सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर एक होते हैं। जनविरोधी नीतियों पर अमल करने में ये एक–दूसरे का बखूबी साथ निभाते हैं। 1967 के नक्सलबाड़ी किसान सशस्त्र संघर्ष से लेकर आज हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध को खत्म करने के शासक वर्गों की रणनीति–कार्यनीति तक तमाम संसदीय दलों में एकता है, सत्ताधारी हो या विपक्षी। हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध ही नहीं, जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर अपने हक के लिए संघर्षरत तमाम आदिवासी, गैर–आदिवासी जनता पर, हमारे संघर्ष इलाकों में ही नहीं, जन संघर्ष के तमाम इलाकों में देश के शासक वर्गों के द्वारा 2009 के बीच से अन्यायपूर्ण युद्ध – आपरेशन ग्रीनहंट थोपा गया है। यह अमेरिकी सेना, गुप्तचर विभाग–एफबीआई के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में, भारतीय सेना के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी से अमल में लायी जा रही विश्वासघाती एलआईसी (कम तीव्रता वाली युद्ध नीति) के तहत जारी फासीवादी चौतरफा सैनिक हमला है। इस हमले का हमारी पार्टी, हमारी सेना–पीएलजीए, क्रांतिकारी जनताना सरकारें, जन संगठन व जनता बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं।

650 कंपनियों यानी 72 हजार अतिरिक्त अर्ध–सैनिक बलों सहित कुल 1 लाख 50 हजार सशस्त्र बलों की संगीनों के साये में विगत 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने का चुनाव आयोग ने दावा किया था। जबकि सच्चाई यह है कि चुनाव के दो महीने पूर्व से ही अभूतपूर्व दमन अभियान चलाकर संपन्न कराये गये इन चुनावों का दण्डकारण्य के 700 से ज्यादा गांवों की जनता ने बहिष्कार किया था। दसियों मतदान केंद्रों में एक भी वोट नहीं पड़ा। झूठे लोकतंत्र का बहिष्कार करके यहां की जनता ने सही लोकतांत्रिक पक्रिया के तहत ग्राम सभाओं में चुनी गयी क्रांतिकारी जनताना सरकारों के प्रति अपना विश्वास जताया है। सरकारी सशस्त्र बलों के आतंक का डटकर मुकाबला करते हुए हमारी पीएलजीए ने जनता की सक्रिय भागीदारी से प्रतिरोध अभियान संचालित करके 17 पुलिस जवानों को मार गिराया एवं 20 को घायल किया था। 87 जवान विभिन्न प्रकार के ट्रैपों में फंसकर घायल हो गये थे।

इस बार सिर्फ एक ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हजारों अतिरिक्त बलों को लगाया गया है। जनवरी, फरवरी व मार्च महीनों में लगातार गश्त अभियानों को संचालित करते हुए गांवों पर हमले किये गये। लोगों की बेदम पिटाई, सैकड़ों की अवैध गिरफ्तारियां की गयी। कइयों को इनामी माओवादी घोषित कर फर्जी केसों में जेल भेजा गया। महाराष्ट्र के बेतकाठी, नेलनार (नारायणपुर), कांकेर, बीजापुर जिलों में फर्जी मुठभेड़ों में 15 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। आतंकी माहौल कायम करके चुनाव पूरा करवाने की कवायद जारी है।

हमारी पार्टी जनता व जनवादी ताकतों से अपील करती है कि चूंकि कांग्रेस, भाजपा, भाकपा, भाकमा, बसपा, स्वाभिमान मंच, चुनावी मैदान में उतरी नयी आम आदमी पार्टी सभी शोषक–शासक वर्गों की सेवा करने वाली पार्टियां ही है, इसलिए किसी के भ्रम में न रहकर चुनावों का बहिष्कार करें। देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस देश की दुस्थिति के लिए प्रधान जिम्मेदार है। भाजपा फासीवादी, हिन्दू धर्मोन्मादी पार्टी है जो भगवा आंतकवाद को बढ़ावा देते हुए अल्पसंख्यक

मतदान दल के कर्मचारियों की दुखद मौत पर

(3 अप्रैल 2014 को एसजेडसी प्रवक्ता के द्वारा जारी सार्वजनिक माफीनामा)

12 अप्रैल, 2014 को बीजापुर जिले के कुटरू के पास हमारी पीएलजीए के द्वारा पुलिस होने की गलत फहमी में किए गये बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में हुई मतदान दल के कर्मचारियों की दुखद मौत पर हमारी पार्टी की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मृत व घायल कर्मचारियों के परिवार जनों, बंधु–मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व सहानुभूति प्रकट करती है और इस गंभीर गलती के लिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है। साथ ही संजीवनी वाहन को उड़ाने की घटना में मृत ड्रायवर एवं टेक्नीशियन के परिजनों के प्रति भी हम संवेदना प्रकट करते हैं। घायल कर्मचारियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए हम उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वे उनके इलाज में कोई कसर न छोड़े। हमारी इस चूक की वजह से घटना में मृत सात शिक्षक–कर्मचारियों के परिवारजनों को अपूरणीय क्षति पहुंची है जिसका हम कोई भरपाई नहीं कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि गलती कहने और माफी मांगने मात्र से दिवंगत शिक्षक–कर्मचारी वापस नहीं आ सकते। हम सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मृत शिक्षक व कर्मचारी हमारी पार्टी के दुश्मन नहीं थे और न ही हमने उन्हें जानबूझकर मारा। यह असावधनी और धोखे से हुई दुर्घटना है।

प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि गलत फहमी पैदा करने के पुलिसिया दांव–पेंच जैसे गाडियां बदलना, सिविल वाहनों का इस्तेमाल आदि के चलते अनजाने में, गलत फहमी व जल्दबाजी में हमारी ओर से यह भारी चूक हुई है। यह एक चिंताजनक व अफसोसनाक घटना है। इसे हम गंभीरता से लेंगे। हालांकि चुनाव पूर्व ही हमारी स्पेशल जोनल कमेटी ने एक परिपत्र जारी करके पुलिस पर की जाने वाली सैनिक कार्रवाइयों के दौरान मतदान दलों, नागरिकों व जनता के जानमाल को नुकसान न पहुंचने देने आवश्यक व तमाम सावधानियां बरतने हमारे कैडरों को दिशा–निर्देश दिया था। बावजूद हमसे यह भारी चूक हुई है। यह चूक कैसे, क्यों, किस स्तर पर हुई है, इसकी गहराई से जांच–पड़ताल करके नतीजों पर आधारित होकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने उचित कदम उठायेंगे।

इस घटना की कड़ी निंदा करने वालों में मृतक व घायलों के परिजनों, शिक्षाकर्मी व कर्मचारी संगठनों से लेकर विभिन्न संसदीय पार्टियां, आला पुलिस अधिकारी

मुस्लिम व ईसाईयों पर हमलों के लिए मुख्य जिम्मेदार है। हिन्दू धार्मिक एजेन्डे पर कभी खुला व घोषित रूप से तो कभी उसे छुपाकर विकास की दुहाई देते हुए लोगों को भरमाने व भटकाने की कोशिश करती आ रही है।

1951 में ही तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष को तिलांजलि देकर भाकपा एक संशोधनवादी पार्टी में तब्दील हो गयी है। जनता की समस्याओं को लेकर जन संघर्षों को खुले व कानूनी दायरे में बांधकर अपनी संसदीय राजनीति को आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर यह शासक वर्गों की सेवा ही कर रही है।

एनजीओ की पृष्टभूमि के साथ–साथ गांधीवादी अहिंसा, स्वराज और जेपी के समाजवाद एवं क्रांतिकारी लफ्फाजी का सम्मिश्रण लेकर पुरानी संसदीय पार्टियों से ऊब चुकी जनता को भरमाने आम आदमी पार्टी नयी कोशिश कर रही है। देश भर में शासक वर्गों, राजनेताओं–अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्यम वर्गीय जनता में जो आक्रोश है, उसे भुनाते हुए आप पार्टी आगे आई है। लेकिन शोषण मूलक व भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के बगैर भ्रष्टाचार को खत्म करना न सिर्फ कोरी कल्पना है बल्कि जनता के साथ छल व धोखा ही है।

चुनाव आयोग व चुनावी पार्टियों के हर तरह की कवायद के बावजूद उल्लेखनीय संख्या में लोग मतदान केंद्रों से दूर ही रहते हैं। चुनाव सुधारों के जरिए चुनाव प्रक्रिया के प्रति भरोसा कायम करने व बढ़ाने के तहत इस बार नोटा बटन चालू किया गया है। लेकिन नोटा का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों में भी दसियों हजारों वोटरों ने नोटा दबाया था लेकिन इससे चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की तरह भी नहीं है, यह। इसलिए चुनावी प्रक्रिया को ही पूरी तरह नकारे व वैकल्पिक जन राज सत्ता के अंग– क्रांतिकारी जनताना सरकारों को चुनने की प्रक्रिया से जुड़े।

हमारी पार्टी चार उत्पीड़ित वर्गों–मजदूर किसान, पेट्टी बुर्जुआ, देशी बुर्जुआ (छोटे व मध्यम) के संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में भारत की जनता के नवजनवादी गणराज्यों के फेडरेशन के निर्माण के लक्ष्य से क्रांतिकारी जनयुद्ध को जारी रखी हुई है। यही आज के झूठे लोकतंत्र व वर्तमान फर्जी संसदीय प्रणाली का असली विकल्प है। इस दिशा में कदम बढ़ाने, ऑपरेशन ग्रीन हंट को हराने के लिए जारी जनयुद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाने हम आह्वान करते हैं। ★

एवं छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार तक शामिल हैं। इनमें से परिवार जनों, शिक्षक–कर्मचारी संगठनों के रोष व आक्रोश को हम समझ सकते हैं लेकिन शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली लुटेरी केंद्र–राज्य सरकारों, उनके राज्ययंत्र के कल–पुर्जे का काम करने वाली पुलिस के अधिकारियों व संसदीय पार्टियों को हमारी निंदा करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। इस दुखद घटना का फायदा उठाते हुए पुलिस अधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्रालय हमें उग्रवादी करार देने और इस कार्रवाई को जानबूझकर मतदान दल को निशाना बनाकर की गयी कार्रवाई साबित करने का नाकाम प्रयास कर रहे हैं। जनविरोधी, देशद्रोही, भ्रष्ट व फासीवादी कांग्रेस, भाजपा व संघ परिवार के सदस्य संगठनों के द्वारा हमारे खिलाफ रैलियां आयोजित की जा रही हैं। दरअसल शोषक–शासक वर्गों– दलाल बड़े पूंजीपति वर्ग, सामंती वर्ग एवं उनके साम्राज्यवादी आकाओं की सरकारें ही असली आतंकवादी व उग्रवादी हैं जो हर दिन उत्पीड़ित–शोषित जनता को आतंकित करने में लगी हैं। जल–जंगल–जमीन पर अपने अधिकार, अस्तित्व व अस्मिता के लिए संघर्षरत जनता पर नाजायज युद्ध–ऑपरेशन ग्रीनहंट थोपने वालों को हमारी गलती पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ढ़ाई साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़ों तक को मारने वाले, एड़समेट्टा, सारकेनगुडा जैसे दसियों नरसंहार करने वाले, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार व हत्या करने वाले, घरों–गांवों को जलाने वाले, ग्रामीणों की बेदम पिटाई करने वाले, अवैध गिरफ्तारियां करके फर्जी केसों में जेल भेजने वाले, बिना या फर्जी गवाही पर लंबी सजाएं देने वाले ही असली उग्रवादी हैं। देश की संपदाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने वाले ही असली देशद्रोही हैं।

हमारी ओर से शिक्षक–कर्मचारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। यह जगजाहिर है कि शिक्षक–कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार जिन्हें पेट्टी बुर्जुआ वर्ग कहते हैं हमारे नवजनवादी संयुक्त मोर्चे के चार वर्गों में से हैं। ये हमारे मित्र वर्ग के हैं। ऐसे में इन पर हमले के बारे में हमारा कोई भी कैडर सोच भी नहीं सकता है। जबकि सरकारों की शिक्षक–कर्मचारी विरोधी नीतियों से सभी वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, संघर्ष इलाकों में मतदान कराने के लिए शिक्षक–कर्मचारियों को निलंबन या बर्खास्तगी का डर दिखाकर, उनके विरोध के बावजूद एवं उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन भेजा जाता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम पर अलोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराये जाते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के नाम पर विगत नवंबर में 72 हजार अतिरिक्त फोर्स सहित कुल डेढ़ लाख सशस्त्र बलों की संगीनों के साये में जनता को आतंकित करके छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनावों को संचालित किया गया था। हमारी पार्टी के चुनाव बहिष्कार के आव्हान को विफल करने अब लोकसभा चुनावों में भी दसियों हजार सशस्त्र बलों को तैनात करके चुनाव के दो महीने पहले से ही लगातार गश्त अभियान चलाते हुए, गांवों पर हमले करते हुए जनता में खौफ फैलाया गया था। चुनाव बहिष्कार के अपने जनवादी अधिकार से जनता को वंचित रखने के तहत ही यह सब किया गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव बहिष्कार के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने जनता के सामने प्रतिरोध का रास्ता चुनने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। जनता के हक में जारी इस प्रतिरोध में हमारे निशाने पर सरकारी सशस्त्र बल थे। यहां यह बताना भी उचित व आवश्यक है कि पुलिस, अर्ध–सैनिक बल व सेना के जवान एवं छोटे अधिकारी भी वर्गीय आधार पर हमारे दुश्मन नहीं है और न ही उनके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी है। लेकिन शोषक–शासक वर्गों के राज्ययंत्र के हिस्से के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरने के कारण ही हम मजबूरन उन्हें निशाना बनाते हैं।

हम मृतक व घायलों के परिवार जनों, बंधु–मित्रों, शिक्षक–कर्मचारी संगठनों, जनता, प्रगतिशील–जनवादी ताकतों, मानवाधिकार संगठनों से अपील करते हैं कि वे हमारे इस स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश करे कि कुटरू की घटना इरादतन घटना नहीं है। इसे मानवाधिकारों के हनन के रूप में न देखें। सरकारों के द्वारा जनता पर जारी नाजायज युद्ध के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित जनता के द्वारा किये जा रहे न्यायपूर्ण जन युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के षड्यंत्रकारी दांव–पेंच को समझने में हमारी ओर से हुई खामी व कमी के चलते घटी गंभीर गलती के रूप में इसे देखना चाहिए। हम कम्युनिस्ट मनुष्य के प्राणों को मूल्यावान व सर्वोपरि समझते हैं। दुनिया के तमाम मनुष्यों की खुशहाली के लिए, शोषण व उत्पीड़न मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना के लिए शोषकों–उत्पीड़कों के खिलाफ हम जनयुद्ध में लगे हुए हैं और इस दौरानं सर्वोच्च बलिदान देने तैयार रहते हैं।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अंततः इस तरह की घटनाओं की जवाबदेही लुटेरी सरकारों पर ही होगी। जब तक चुनाव में वोट देने या न देने सहित जनता को उनके तमाम जनवादी अधिकारों से लैस नहीं किया जाता है, जनता का शोषण–दमन खत्म नहीं किया जाता है तब तक जनप्रतिरोध व जनयुद्ध जारी रहेगा। सशस्त्र बलों की भारी तैनाती के बिना, जनवादी माहौल में यदि चुनाव कराये जाते हैं तो इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी।

हम शिक्षक–कर्मचारियों व पत्रकारों से अपील करते हैं कि वे पुलिस वाहनों में, पुलिस के साथ, पुलिस के द्वारा

सी–60 बलों की फर्जी मुठभेड़ों, क्रूरता व आतंक का प्रतिशोध है, मुरमुरी एम्बुश!

(मुरमुरी एंबुश के संदर्भ में 12 मई, 2014 को डीकेएसजेडसी के प्रवक्ता के द्वारा मीडिया को जारी बयान)

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के चामुर्षि तहसील के मुरण्डा–मुरमुरी के बीच कुख्यात सी–60 कमांडों बलों पर 11 मई को बहादुराना हमला करके 7 कमांडों को मौत के घाट उतारकर, 2 को गंभीर रूप से घायल करने वाली पीएलजीए के लाल योद्धाओं का हमारी दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी क्रांतिकारी अभिनदंन के साथ जय–जयकार करती है। शोषक–शासक वर्गों की सेवा व गुलामी में अपनी वर्गीय जड़ों को भुलाकर गढ़चिरोली, गोंदिया की संघर्षरत जनता पर कहर बरपाने वाले सी–60 कमांडो बलों को इस मौके पर हम गंभीर चेतावनी देते हैं कि क्रांतिकारी आन्दोलन व जनता के खिलाफ आक्रामक ढंग से आगे आना बंद नहीं करेंगे तो इससे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ, आत्मरक्षा के लिये हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध के तहत अपनायी गयी कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान का हिस्सा है, मुरमुरी का हमला। सी–60 कमांडो बलों की कूरता एवं उनके आतंक का प्रतिशोध है।

केंद्र–राज्य सरकारों के द्वारा देश की उत्पीड़ित जनता पर थोपे गये नाजायज जंग–ऑपरेशन ग्रीनहंट के चौतरफा हमले के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंदिया जिलों में जनवरी, 2013 से फरवरी, 2014 तक के 13 महीनों में हमारे 30 से ज्यादा कामरेडों का कत्लेआम किया गया है। महाराष्ट्र के संघर्ष इलाकों में आज गांवों पर हमले, ग्रामीणों की बेदम पिटाई, अवैध गिरफ्तारियां, झूठे केसों में जेलों में सड़ाना, मुठभेड़ों व फर्जी मुठभेड़ों में क्रांतिकारियों व आम जनता की जघन्य हत्याएं करना, महिलाओं पर अत्याचार आदि आम बात हो गयी है। गढ़चिरोली के गोविंदगांव में 6, भटपर में 5, सिंदेसूर में 7, गोंदिया के बेतकाठी में 7 कामरेडों के साथ–साथ गढ़चिरोली के ही मेड्री में 6 महिला कामरेडों की जघन्य हत्या की गई। मेड्री में 6 महिला कामरेडों को पकड़ कर अत्याचार करने के बाद उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। इतना ही नहीं, सी–60 कमांडो बलों ने शहीद हुई हमारी महिला कामरेडों की लाशों के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि अश्लील वीडियो क्लिप्पिंग्स बनाकर दुकानों में बेच रहे हैं और गांवों में जबरन प्रदर्शित कर रहे हैं।

सी–60 बलों की इस नीच व शर्मनाक हरकत की तीव्र भर्त्सना करने एवं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने हम छात्रों, नौजवानों, प्रगतिशील–जनवादी ताकतों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व संगठनों, जन पक्षधर मीडिया कर्मियों का आह्वान करते हैं। हम अपील करते हैं कि वे ऑपरेशन ग्रीनहंट के विरोध में आन्दोलन को तेज करें एवं पार्टी के नेतृत्व में ऑपरेशन ग्रीनहंट के खिलाफ जारी क्रांतिकारी जनयुद्ध की हर संभव मदद करें। अपने अस्तित्व व आत्म सम्मान सहित जल–जंगल–जमीन पर अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए संघर्षरत पीड़ित–शोषित जनता, खासकर आदिवासी जनता का समर्थन करें।

★

इस्तेमाल वाहनों पर सफर न करें। साथ ही हम विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों एवं निजी वाहन मालिकों से अपील करते हैं कि वे संघर्ष इलाकों में पुलिस को लाने–ले जाने का काम न करें। अपने वाहनों में न बैठायें, अपने वाहनों को पुलिस विभाग के लिए किराये से न दें। पुलिस के द्वारा संजीवनी वाहन का जबरन इस्तेमाल के चलते ही वाहन ड्रायवर एवं तकनीशियन की अनावश्यक मौत हो गयी। निजी व सरकारी विभागों के वाहनों के जबरन अधिग्रहण के संदर्भ में वाहनों के ड्रायवरों को पुलिस के साथ ड्यूटी में न जाने हम आग्रह करते हैं।

मतदान कर्मियों या पुलिस जवानों की मौत पर सरकारें मगरमच्छ की आंसू बहाती हैं, मुआवजे के रूप में मुठ्ठी भर रुपये देती हैं, सांत्वना के दो–चार शब्द बोलती हैं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए जान देने वाले शहीद कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान लोकतंत्र झूठा है। यह शोषण मूलक अर्ध–सामंती व अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था है। शिक्षक–कर्मचारी, सशस्त्र बलों को ये शोषक–शासक वर्ग व उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारें महज अपनी सेवा करने वाले व सुरक्षा देने वाले मोहरे समझते हैं। अपने शोषण व शासन को जारी रखने के लिए ये किसी की भी बलि चढ़ाते हैं। उनकी मौत पर उन्हें कोई अफसोस नहीं होता है। जन धन के कुछ हिस्से को खर्च करके, उनकी जनविरोधी नीतियों के चलते बने बेरोजगारों की फौज से कुछ नये लोगों को अपनी सेवा में फिर से भर्ती करते हैं। हम परिवारजनों, कर्मचारी संगठनों से अपील करते हैं कि वे इस सच्चाई को समझें एवं जन आन्दोलनों व जनयुद्ध के पक्ष में खडे होवें।

★

सी–60 कमाण्डो जवानों को विज्ञप्ति

(पार्टी की पश्चिम रीजनल कमेटी के द्वारा फरवरी 26, 2014 को जारी बयान)

सी–60 कमाण्डो जवानों!

गड़चिरोली जिले में पिछले 35 सालों से क्रांतिकारी आंदोलन जारी है। क्रांतिकारी आंदोलन के विस्तार से अपने जिले के सैकड़ो गांवों के आदिवासी किसान, महिला एवं पुरुष जन संगठनों में संगठित हुए। आप लोग जानते ही हैं कि ये सभी आपके अपने ही परिवारजन हैं। अपने आदिवासी बंधुओं ने पीढ़ियों से जारी शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष छेड़े थे। ग्रामीण कबीलाई मुखियाओं के खिलाफ संघर्ष छेड़े। जन विरोधी अहेरी राज परिवार द्वारा जारी परंपरागत शोषण के खिलाफ संघर्ष किये। जोत जमीन के लिए संघर्ष किये। मजदूरी बढ़ाने के लिए संघर्ष किये। इस तरह जनता ने संघर्षों के द्वारा ही अनेक सुविधाओं को हासिल किया। पार्टी के आने के पहले अपने गांवों व जनता की जिंदगी कैसी थी? इसके बारे में जरा सोचिये। अपने संघर्ष के जरिये उनकी जिंदगी में आये बदलावों के बारे में सोचिये। एक जून पेट भर खाना नहीं मिलने वाले परिवारों को याद कीजिये। शरीर ढांकने कपड़े न मिलने के कारण अधनंगी जिंदगी बिताई अपनी मां–बहनों की हालात को याद कीजिये। फारेस्ट अधिकारियों द्वारा तंग की दास्तानों के बारे में अपने बुजुर्गों से पूछिये। लुटेरे साहुकारो की लूट के बारे में पूछ लीजिये। इन 35 सालों में अपनी जिंदगियों में आये बदलावों के बारे में सोचिये। 1947 में आजादी के ढोंग रचने वाले राजनीतिक पार्टियों व नेताओं से सवाल पूछिये कि इतने सालों से अपनी आदिवासी जनता के विकास के लिए उन्होंने क्या किया? केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और वित्त मंत्री चिदंबरम बेशर्मी से कबूल रहे हैं कि आजादी के 60 सालों में आदिवासियों की अनदेखी हुई है। यह बात आपके आला अधिकारी बखूबी जानते हैं। लेकिन इन तमाम सच्चाइयों पर परदा डालते हुए हमें विकास विरोधी तथा खुद के देशभक्त होने का दंभ भर रहे हैं। देश के लिए लड़–मरने आपको उकसा रहे हैं। इनकी बातों में जरा सा भी सच्चाई नहीं है। आप गांवों में आकर जनता से सच्चाई का पता कीजिये। आखिरकार आपको सी–60 कमाण्डों बनाये क्यों है? अत्यंत नवीनतम हथियार आपके हाथों में थमाये क्यों हैं? आपको अपनी ही आदिवासी जनता के खिलाफ क्यों उकसा रहे हैं? किनके आदेशों पर आप अपने ही भाई–बंधुओं को गिरफ्तार कर रहे हो? मारपीट कर रहे हो? असहनीय यातनाएं देते हुए जेल में बंदी बना रहे हो? आदिवासी जनता का फर्जी मुठभेड़ों में कत्ल कर रहे हो? आदिवासी महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार करने वालों को नागरिक समाज में कौन सा दर्जा मिलता है– इसके बारे में कभी सोचे हो? सी–60 कमाण्डों के नाम से ही जनता नफरत क्यों कर रही है? मोतीरात, गंगाराम सिडाम, रामा कुडमेथे, सुक्कू विडिपि, विनोद हिचामी कोको नरोटे, मुन्ना ठाकुर के नाम से ही जनता घृणा क्यों करती है? आपको ऐसा तैयार करने वाले कौन है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या? क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से ही आपको पढ़ाई करने का मौका मिला। नौकरियां मिली। आपकी जिंदगियों में बदलाव आया। ये बात आप जानते ही है कि क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए ही गड़चिरोली जिले में कई सारे बदलाव आये हैं। जनता जी–जान से लड़कर ही अपनी जिंदगियों को बदल रही है। अपने विकास के लिए वो लड़ रही है। जल–जंगल–जमीन पर अधिकार तथा इज्जत से जीने के अधिकार के लिए वो लड़ रही है। जनता के इन आंदोलनों को दबाने के लिए या कुचलने के लिए आप कमाण्डों में भर्ती हए। धन कुबेरों व लुटेरे शासक वर्गों के हितों के लिए आप क्यों हथियार उठाये हो? सूर्जागढ़, दमकोडी इत्यादि जगहों की जनता की जमीनों व संपत्तियों को कब्जा करने के लिए आप क्यों खाकी वर्दी पहने हो? इस सच्चाई को आप मानेंगे कि आपके हर काम जनता के खिलाफ है और लुटेरे शासक वर्गों के लिए फायदेमंद है। आपके आला अधिकारी रवींद्र कदम हो या सुवेज हक इन सच्चइयों के बारे आपको कभी नहीं बतायेंगे। आपके आला अधिकारी सत्यपाल सिंह इस बार रंग बदलकर भाजपा का उम्मीदवार बनने की बात पर गौर करने से पता चलेगा कि ये तमाम अधिकारी किस वर्ग में जन्में हैं या किस वर्ग के हितों के लिए काम करते हैं। उनके लिए आप अपनी जनता, जनता के लिए लड़ने वाले जन छापामारों व जन युद्ध से टक्कर ले रहे हो। आपकी जान दांव पर लगाकर लुटेरे शासक वर्गों को बचा रहे हो। आप लोगों के मारे जाने से आपके परिवारजनों के हाथ में थोड़ा बहुत रकम थमाकर अपना हाथ झाड़ लेते हैं। आपके परिवार को जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई क्या पैसों से होगा? आप किस के लिए जान दोगे? अपनी जान क्यों गंवाओगे? आपकी मृत्यु पंख से भी हल्का है। आपकी मृत्यु की खबर सुनकर जनता खुश क्यों हो रही है? जनता यह क्यों सोच रही है कि मुन्ना ठाकुर, मोतीराम, रामा कुडमेथे, कोको नरोटे, विनोद हिचामी जैसे क्रूर कमाण्डो अधिकारियों के मर जाने से अच्छा है। आपकी जिंदगी के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। आपके बलिदान व्यर्थ हैं। आपकी

(शेष पेज 29 में...)

8 मार्च 2014

अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला संघर्ष दिवस जिंदाबाद!

महिलाओं पर राज्य हिंसा के विरोध में संघर्ष करो!

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का आह्वान!

दिल्ली बलात्कार कांड को लेकर उभरे जन आक्रोश के बाद भारत सरकार ने अपनी इज्जत बचाने महिला विषयक कानूनों में बदलाव और निर्भया फंड जैसी घोषणाएं करके यह जताने की कोशिश की कि मानो वह वाकई महिलाओं की समानता, उत्थान और सशक्तीकरण की पक्षधर हो। किन्तु यह मात्र उसकी ढोंग है। बच्चों सहित महिलाओं पर बेरोकटोक जारी अत्याचार सरकारों की खोखले वादों का भण्डाफोड़ कर रही हैं। दरअसल जनाक्रोश के सामने झुककर सरकार ने अत्याचार विरोधी कानून बनाने का दिखावट किया। लेकिन इन सरकारों का चरित्र ही पितृसत्तात्मक, शोषणमूलक व अत्याचारी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलनेवाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार हो या अन्य किसी संसदीय पार्टी के नेतृत्व में चलनेवाली सरकार हो इनका असली चेहरा अत्यंत क्रूर, घृणास्पद और महिलाओं पर बर्बर हिंसा करनेवाली समाज व्यवस्था को संरक्षण देने का है। गुजरात नरसंहार में सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार व हत्या करने वालों, गर्भवती की कोख को त्रिशूल से फाड़कर मौत के घाट उतारने वालों का खुला संरक्षण देने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनता है। तो सरकारी नीतियों का शिकार होकर आत्महत्या करने वाले किसानों की, कलावती जैसी किसानों की जीवन संगिनियों की भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीतिक फायदा उठाने वाला राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। गेरुआधारी भारतीय जनता पार्टी हो या तिरंगी कांग्रेस – दोनों गिरोह घोर महिला विरोधी है।

इन पार्टियों की सोच अत्यंत पिछड़ी एवं बाजारू है। एक ओर महिलाओं को पैरों की जूती समझती हैं तो दूसरी ओर बाजार में उसके जिस्म का प्रदर्शन करवाती हैं। ये सरकारें एक तरफ सड़ी–गली सामंती व्यवस्था जो महिलाओं को घूंघट, लज्जा, रीति–रिवाज, परंपरा, धर्म, सामाजिक बंधनों और घर की चौखट के अंदर कैद करके रखती हैं, उसे बनाए रखती हैं तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए महिलाओं के जिस्म का प्रदर्शन करते हुए उसे बाजार में बिकनेवाला माल बना देती है। महिलाएं सामंती और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाओं में अमानवीय अत्याचार और शोषण की शिकार हैं। गांव, कारखाना, ऑफिस या संसद कहीं भी हो महिलाएं हर जगह अपमान व हिंसा का शिकार हो रही हैं। 66 साल से दलालों की सत्ता भारत में चली आ रही है पर झूठी प्रतिष्ठा के नाम पर हत्याएं, बलात्कार, महिला भ्रूण हत्या रोक पाने में यह व्यवस्था नाकाम हुई है, उल्टा इसमें वृद्धि हुई है। यह संपत्ति के केन्द्रीकरण, मुनाफाखोरी व उपभोक्तावादी संस्कृति परस्त सरकारी नीतियों के कारण ही हुआ है।

महिलाओं पर जारी यह सारी हिंसा राजसत्ता द्वारा पोषित एवं संरक्षित है। जातिवाद, धर्मांधता, परंपराओं जैसे पिछड़े विचारों को राजसत्ता बढ़ावा देती है। इसके खिलाफ जब महिलाएं संगठित होकर आवाज उठाती हैं तो उनका कत्ल किया जाता है। महिलाओं ने जब इस व्यवस्था को ही बदलने के इरादे से क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होकर हथियार उठाई हैं तो ये सरकारें जन संहारों, मुठभेड़ों व फर्जी मुठभेड़ों के द्वारा महिलाओं की हत्याएं करवा रही हैं।

वर्गीय समाज के अस्तित्व के साथ ही महिलाओं पर पितृसत्ता शुरू हो गई है। उसके खिलाफ संघर्ष करते–करते अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर महिला मुक्ति की आवाज 8 मार्च 1910 को बुलंद हुई। कॉमरेड क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए शुरू किया गया यह संघर्ष आज भी जारी है। भारत में यह संघर्ष जनयुद्ध का रूप धारण कर चुका है। इसमें महिला जनयोद्धाओं का अभूतपूर्व योगदान है। अनमोल त्याग व बलिदानों के साथ महिला मुक्ति की दिशा में अग्रसर नवजनवादी क्रांति को अपने खून से सींचकर महिला जनयोद्धाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापक बनाया है। पुरुषों के बराबरी में जंग–ए–मैदान में अपना लड़ाकू जौहर दिखाया है।

महिलाओं की जनयुद्ध में इस बढ़ती भागीदारी से घबराकर शोषक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों ने महिलाओं पर अभूतपूर्व रूप से हमलों को तेज किया है। अभी तक सैकड़ों संघर्षरत महिलाओं को, जन योध्दाओं को मार डाला है। सैकड़ों को झूठे मुकद्दमों में जेलों में कैद किया हैं। जेलों में भी महिलाओं पर हमलें हो रहे हैं। जगदलपुर, रायपुर, नागपुर, मुम्बई एवं देश के अन्य जेलों में महिलाओं पर राज्यहिंसा जारी है। वहीं जेलों में भी

क्रांतिकारी महिलाएं अपने हक और अधिकारों के लिए जबरदस्त संघर्ष करते हुए महिला मुक्ति का परचम ऊंचा लहरा रही हैं।

ये सरकारें बलात्कार को दमन के एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। बस्तर की शिक्षिका सोनी सोड़ी पर हुए सरकारी अत्याचार किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करनेवाले हैं।

विगत एक साल में देशभर में 31 क्रांतिकारी महिलाओं की झूठी मुठभेड़ों में राज्य सत्ता द्वारा सीधे हमले कर हत्या की गई है। अकेले गड़चिरोली जिले में पिछले एक साल में 17 महिला क्रांतिकारियों की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है। सार्केनगूडा, एडसमेट्टा जैसे नरसंहारों, झूठी मुठभेड़ों में सैकड़ों जनता को मौत के घाट उतारा गया जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सामूहिक अत्याचार व हत्याएं, काले कानूनों की जंजीरों में जकड़ कर रखना, उपभोक्तावादी–बाजारू संस्कृति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों का शिकार बनाना व पुरोगामी दिखावे की आड़ में पिछड़े विचारों को बनाये रखना आदि रूपों में राज्य सत्ता की ओर से महिलाओं पर हिंसा जारी है। जब तक यह पितृसत्तात्मक अर्द्ध–सामंती व अर्द्ध–उपनिवेशी शोषणकारी व्यवस्था जारी रहेगी तब तक महिलाओं पर अत्याचारों का रोकथाम नहीं होगा व महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं। भारत में नव जनवादी क्रांति के लिए जारी जनयुद्ध महिला मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता हुआ संघर्ष है। सरकार द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीनहंट' के नाम से जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध जुल्मी और महिलाओं को गुलाम बनाकर रखनेवाली व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए है। इसलिए तमाम महिला–पुरुषों को महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह आह्वान है कि वे पीड़ित जनता की मुक्ति के साथ–साथ महिला मुक्ति की दिशा में जारी जन युध्द में बड़े पैमाने पर भागीदारी ले। सरकारों के द्वारा जनता पर जारी नाजायज युद्ध के विरोध में क्रांतिकांरी जन युद्ध को तेज करे। 8 मार्च, 2014 के महिला दिवस को देशभर में महिलाओं पर राज्यसत्ता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जारी राज्यहिंसा के विरोधी संघर्ष दिवस के रूप में मनाए। गांवों तथा शहरों में भी जगह–जगह पर सभा, सम्मेलन आयोजित करके, रैलियां निकालकर बड़े पैमाने पर जन गोलबंदी करें, खासकर महिलाओं की व्यापक गोलबंदी करें और महिलाओं पर सरकारी हिंसा का विरोध करते हुए महिला मुक्ति के झंडे को ऊंचा उठाये और आवाज बुलंद करें।

☆ शोषक–शासक वर्गों की राजसत्ता के द्वारा महिलाओं पर जारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद करो।

☆ जनसंहारों, फर्जी मुठभेड़ों में जनता खासकर महिलाओं व बच्चों के कत्लेआम के विरोध में व्यापक, संगठित व जुझारू जन आंदोलनों व महिला आंदोलनों का निर्माण करो!

☆ क्रांतिकारी जन युध्द को तेज करके केन्द्र–राज्य सरकारों के द्वारा देश की पीड़ित जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युध्द – ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त करो!

☆ आधे संसार पर अधिकार को सुनिश्चित करने वाली जन राज सत्ता के अंग – क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत करेंगे व विस्तार करेंगे!

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन

दंडकारण्य

पंचायत सचिव की पुलिस हिरासत में हत्या के खिलाफ शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व जनता आवाज बुंलद करे।

विगत 18 मार्च, 2014 को ग्राम सिकसोड़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर निवासी एवं ग्राम पंचायत सुलंगी के सचिव जागेश्वर प्रसाद यादव पिता रामभरोस यादव की पुलिस हिरासत में जहर देकर हत्या की गयी थी। पुलिस ने यह बयान जारी किया कि पूछताछ के लिए ले जाते समय जागेश्वर ने जहर खा लिया था। जबकि जागेश्वर के पिता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह खुलासा किया कि जागेश्वर को घर से उठाकर ले जाया गया था और थाने में जहर देकर मार डाला गया। दण्डकारण्य के संघर्ष इलाकों में पुलिस, अर्ध–सैनिक बलों के द्वारा आये दिन फर्जी मुठभेड़ें, नरसंहार, अवैध गिरफ्तारियां आम बात है। पूछताछ के नाम पर घर से ले जाकर थाने में जहर देकर मार डालने की यह पुलिसिया हत्या अपने तरह की विशेष घटना है। पंचायत सचिव की नौकरी कर रहे जागेश पर वारण्टी नक्सली का झूठा आरोप लगाकर, किस तरह हिरासत में उसकी क्रूर हत्या की गयी, इसे समझने हम जागेश के पिता रामभरोस यादव के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं सिकसोड थाना प्रभारी को सौंपे गये ज्ञापन में दी गयी जानकारियों को नीचे दे रहे हैं।

थाना प्रभारी, थाना सिकसोड़ को मृतक के पिता के द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में दी गयी जानकारियां कंडिकावार इस प्रकार है।

1. दिनांक 18/03/2014 दिन मंगलवार, समय दोपहर 1.00 बजे पुलिस विभाग के आरक्षक नरेश कुमार साहू, कंश सिन्हा, सोपसिंह कुलदीप एवं एक अन्य व्यक्ति ग्राम सिकसोड़ में मेरे घर आये एवं उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कांकेर एस.पी. ने भेजा है। जागेश्वर को ले जाना है। उन्होंने यह कहा कि हम लोग खाना खाकर जाएंगे, उसके बाद उन्होंने मेरे पुत्र जागेश्वर प्रसाद यादव से कहा कि खाना बनते तक सामने नाला तक ठहल कर आते हैं, यह कहकर जागेश्वर प्रसाद को साथ में ले गये। जाने से पहले टाबेल पहना हुआ था, उसने अपने छोटे भाई ललित यादव से जिंस पेंट मंगाया एवं अपने सामने ही जिंस पहन कर निकल गया था। उस समय जिंस में किसी प्रकार का जहर नहीं था। जागेश्वर प्रसाद यादव को घर से ले जाने के बाद करीब 4.15 बजे घर में सिकसोड़ थाने से दो सिपाही आये एवं उनके द्वारा बताया गया कि जागेश्वर प्रसाद यादव को ले जाते समय जहर का सेवन कर लिया एवं गंभीर अवस्था में अंतागढ़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। तब मैं और मेरे छोटे पुत्र ललित यादव अंतागढ़ अस्पताल गये, पहुंचने पर डॉक्टर रामटेके ने बताया कि जिला अस्पताल कांकेर रिफर किया गया है। कांकेर जाने पर बताया गया कि उन्हें रायपुर रिफर कर दिया गया है। अंत में यह पता चला कि उन्हें धमतरी जिला अस्पताल में रखा गया है जिसको मृत घोषित कर चुके हैं। मृत्यु का कारण जहर सेवन बताया गया।

2. दिनांक 17/02/2014 की रात में उपरोक्त कंडिका नं 1 में वर्णित आरक्षक के साथ 7–8 लोग नकाब लगाकर आये थे। उस वक्त हम सोये हुये थे। हमें उठाकर पूरे परिवार को बाहर निकालकर बोले, 'तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे'। उसके बाद अंदर घुसकर आलमारी, पेटी की तलाशी लेकर निकल गये। 'पुनः कुछ दिन बाद आयेंगे', कहकर (धमकी देकर) चले गये। सुबह होने के पश्चात सिकसोड़ थाने में रात की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने गये। परंतु हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

3. दिनांक 03/03/2014 को इन्हीं आरक्षकों के साथ 10,12 लोग रात 10,30 बजे नशे की हालत में आये। तब तक हम लोग सो चुके थे, हमें जगाकर बाहर निकाला गया और मेरी पत्नी श्रीमती यशोदा यादव एवं पुत्रवधु श्रीमती स्वाती यादव एवं पुत्रवधु की मां श्रीमती पुष्पा यादव की बांह पकड़कर, धक्का मारते हुए उन्हें जमीन पर बैठाला गया और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार को मार देने, मकान को जला देने की धमकी दे रहे थे। मकान के अंदर घुसकर तलाशी लिये और घर में रखे सामानों को तहस नहस किया गया। उसके बाद धमकी देकर चले गये। तो हम उसके पश्चात ड़र की वजह से रात में ही पुलिस थाना सिकसोड़ में इस घटना को दर्ज कराने गये। थाने के पास पहले संतरी से संपर्क किये। उसने थाना प्रभारी से पूछकर सुबह आने को कहा। सुबह जाने पर भी एसपी का आदेश है, कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया।

नोटः विदित हो कि 18/3/2014 को जब जागेश्वर प्रसाद को कांडिका क्रमांक 01 में वर्णित आरक्षकों के द्वारा ले जाया गया था, उसके प्रत्यक्षदर्शी निम्नानुसार हैंः

1. पिंकी प्रधान
2. मीना देहारी
3. लक्ष्मण कोमरा
4. संतोष कुमेटी
5. रमेश नाग

जागेश यादव की पुलिस हिरासत में मृत्यु पर उनके पिता रामभरोस यादव के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति!

मैं इस विज्ञप्ति के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को यह बताना चाहुंगा कि पुलिस के द्वारा मेरे पुत्र जागेश्वर प्रसाद यादव उर्फ जागेश यादव को ग्राम सिकसोड़ के पास से हिरासत में लेना बताया गया है। इतने बड़े भारतीय कानून के रखवाले होकर सरासर झूठ बोल रहे हैं, जबकि सिकसोड़ स्थित हमारे घर से उठा लिया गया है जिसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। आवश्यकता पड़ी तो न्यायलय में पेश किया जावेगा। हम जानते हैं कि हमारा पुत्र ग्राम पंचायत सचिव के पद पर रहकर शासन के पंचायत स्तरीय कार्यों का निष्पादन करता था, परन्तु पुलिस प्रशासन इन्हें वारण्टी नक्सली बता रही है। क्या शासकीय कर्मचारी नक्सली कहलाते हैं? अगर जागेश नक्सली था तो पुलिस प्रशासन साबित कर बताएं ताकि हमें भी राहत महसुस हो या फिर हम यही सोचें कि प्रमोशन पाने पुलिस ने जागेश को नक्सली बनाकर मारा। अगर वारण्टी नक्सली आरोप रहा भी होगा तो कम से कम वारण्ट लिखित देकर मेरे पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश करते। क्या ऐसे वारण्टी नक्सली को छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था में पुलिस आरक्षकों द्वारा उच्च अधिकारी बुलाए हैं कहकर ले जाना और उसे मार डालना है? अगर वारण्ट था तो कानून के नियमानुसार गिरफ्तार कर लेते और सजा मुकद्दर करते। जहर स्वयं द्वारा खाया गया बताया जा रहा है, तो पुलिस हिरासत में रहते हुए स्वयं जहर कैसे खा सकता है? क्या मशहुर नक्सली को बिना तलाशी लिये गिरफ्तार किये? क्या यह सही है? जबकि बहुत बड़ा वारण्टी नक्सली बताया जा रहा है तो हमारे पुलिस जवानों पर अचानक हमला कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होते? व्यंग्यात्मक तथ्य यह है कि बिना हथकड़ी लगाये, चार ही आरक्षक बिना रायफल के मशहूर नक्सली को हिरासत में लेते हैं, तो बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित राज्यों में इतनी फौज क्यों तैनात की गयी है?

इन चारों सहायक आरक्षक पहले से घर में आकर खाना–पीना करते थे, और घटना के दिन भी घर में बाकायदा खाना बनाने को कहा गया था और खाना बनते तक टहलने के नाम से ले गये थे न कि गिरफ्तार कर जेल भेजने। इस संदिग्ध पुलिस कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि बेकसूर ग्रामीणों को नक्सली बताकर मारते हैं या फिर नक्सलियों के साथ पुलिस मिली–जुली है। तभी तो जागेश के साथ घर में खाना खाते थे और घटना के एक दिन पूर्व तो उनकी कार को भी इन्हीं आरक्षकों ने मांगा था। परंतु देने से इन्कार किये।

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी लोग ऐसे निराधार आरोपों से त्रस्त हैं। कई लोग बेकसूर होते हुए भी कानून में कसूरवार ठहराये जाते है। उन्हें जबरदस्ती आरोपी बनाकर जेलों में ठुंसा जाता है। इसी ड़र से कई लोग आत्माहत्या तक कर डालते हैं या गलत राह अपनाते हैं। क्योंकि उनकी मजबुरी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे क्षेत्र में मानव अधिकार का हनन हो रहा है। न हमें पूरी सुरक्षा मिलती न पूरे अधिकार मिलते हैं।

हमें आशा है कि जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच कर हमें न्याय पहुंचायेंगे। और मैं इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मानव अधिकार आयोग एवं तमाम स्वयं सेवी संगठनों से अपील करता हूं कि वे जांच में हमें सहयोग प्रदान करें और पत्रकार बन्धुओं से गुजारिश करता हूं कि प्रत्येक जांच कड़ी को कवर करें और जनता के समक्ष लायें ताकि भविष्य में ऐसी घटना को नासमझ लोग अंजाम न दे सकें।

धन्यवाद,

प्रार्थी

राम भरोस यादव

उपरोक्त तथ्यों से यह साफ है कि जागेश को वारण्टी नक्सली होने के झूठे आरोप में उनके घर से उठा लिया गया था। थाने में यातनाएं देने के बाद जहर देकर उसकी हत्या की गयी। नक्सली मददगार या वारण्टी नक्सली बनाकर जागेश से पैसे एंठना, प्रताड़ित करना आदि के साथ–साथ इसी क्रम में पुलिस का जागेश के घर आना–जाना, उठना–बैठना भी जारी था। वसूली के उजागर होने से बचने या जागेश के द्वारा पुलिस के इच्छानुसार काम करने तैयार न होने की वजह से उन्हें रास्ते से हटाने सिकसोड पुलिस ने हिरासत में जागेश को जहर देकर मारने का तरीका अपनाया और उसे आत्महत्या साबित करके मामले को रफा–दफा करने का प्रयास कर रही है।

जागेश की हिरासती हत्या के मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए रामभरोस यादव ने मुख्यमंत्री सहित गृहमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एसपी कांकेर, पुलिस महानिरीक्षक, कांकेर एवं पुलिस मुख्यालय, रायपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ ग्रामवासियों एवं पंचों का हस्ताक्षर सूची भी संलग्न की गयी थी। लेकिन जनता व जनसंघर्षों पर पाशविक दमन जारी रखी हुई छत्तीसगढ़ सरकार, पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों में सहज ही चुप्पी साधे बैठती हैं। जागेश के साथ जो घटी है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तमाम शासकीय कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रगतिशील–जनवादी ताकतों व संघर्षरत जनता को अपनी आवाज बुंलद करनी होगी।

★

(...आखरी पेज से)

आन्ध्रप्रदेश में किसान सशस्त्र संघर्षों के निर्माण के कई प्रयास किये लेकिन जनाधार नहीं बढ़ाने के कारण वह उसमें सफल नहीं हो सकी। जनता के बीच जाने में विफल होने के कारण पार्टी का विस्तार नहीं हो सका और आन्दोलन को धक्का लगा। 1983 में कॉमरेड रऊफ गिरफतार हुए थे। उसी समय सीआरसी, सीपीआई (एमएल) के तत्कालीन महासचिव वेणु के दक्षिणपंथी अवसरवादी व संशोधनवादी लाइन का विरोध करके कॉमरेड रऊफ ने उससे अलग होकर क्रांतिकारी लाइन अपनायी। 1989 में कॉमरेड रऊफ अपनी पार्टी का सीपीआई (एमएल) रेड फ्लैग जिसने यह घोषणा की थी कि वह 1970 के पार्टी कार्यक्रम का अनुमोदन करती है, के साथ विलय किया। 1998 तक उसके सीसी सदस्य रहे। जब रेड फ्लैग के महासचिव के द्वारा पार्टी में दक्षिणपंथी अवसरवादी, संशोधनवादी लाइन सामने लायी गयी थी, कॉमरेड रऊफ ने उसके खिलाफ संघर्ष करके सही क्रांतिकारी लाइन के साथ पार्टी में मौजूद क्रांतिकारियों को संगठित करने में एवं सीपीआई (एमएल) नक्सलबाड़ी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। बाद में 1999 में सीपीआई (एमएल), माओवादी एकता केंद्र (एमयूसी) का सीपीआई (एमएल) नक्सलबाड़ी में विलय हो गया था।

कॉमरेड रऊफ 2006 तक इस एकीकृत पार्टी का महासचिव रहे। उन्होंने इस पार्टी को एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया। यह पार्टी सिकाम्पोसा (को–ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड ऑर्गनाइजेशन्स ऑफ साउथ एशिया) की संस्थापक सदस्या है। क्रांतिकारी प्रचार के कामकाज में इसने अच्छी भूमिका अदा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरसीपी (अमेरिका) के नेता बाबा अवेकिन व नेपाल की यूसीपीएन (माओवादी) के प्रचण्ड व बाबूराम भट्टाराई के द्वारा सामने लाई गयी संशोधनवादी लाइन का पर्दाफाश करने में रिम व सिकांपोसा में इसने मुख्य भूमिका निभायी। 2008 के बाद कॉमरेड रऊफ गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गय थे।

वे कॉमरेड चारु मजुमदार के स्थायी अनुयायी थे। मा–ले–मा के प्रति अचंचल व दृढ़ विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी व्यवहार में उत्पन्न होने वाली कमियों व खामियों को वे चिन्हित करते थे। उन्होंने पार्टी के धक्का खाने के बारे में अपनी रपट में बेबाकी से इस तरह समीक्षा की–'इलाकावार राजसत्ता को हासिल करने की रणनीति को सही ढ़ंग से व्यवहार में लागू करने में विफल हुए। .. .. वर्ग दुश्मन के सफाये को राजसत्ता के साथ नहीं जोड़ने के चलते वह सिर्फ जुझारु अर्थवाद बनकर समूचा क्रांतिकारी व्यवहार घुमंतू छापामार कार्रवाइयों तक सीमित हो गया है।' पार्टी के सेट बैक में अपनी भूमिका को उन्होंने चिन्हित किया और कुछ इस तरह आत्मालोचना की–'आन्दोलन का विस्तार करने में कैडरों को सैद्धांतिक व सांगठनिक तौर पर तैयार किये बगैर तात्कालिक कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया।'

जब भी उन्हें लगा कि नेतृत्व गलत लाइन अपना रही है, वे विद्रोह का परचम लहराते गये। जबकि सच्चाई यह है कि वे गुटबाजी करने की संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं थे। दरअसल वे अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी के निर्माण के लक्ष्य से विभिन्न पार्टियों के बीच एकता के लिए कोशिश करते रहे। मतभेदों के बावजूद वे दीगर माओवादी पार्टियों के अनुभवों का पैनी नजर से अवलोकन करते थे और उनसे सीखने में रुचि रखते थे। सीपीआई (एमएल) रेड फ्लैग के नेतृत्व को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा– 'विभिन्न एमएल संगठनों की अगुवाई में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन के बारे में, खासकर सशस्त्र संघर्ष में लिप्त पीपुल्सवार, एमसीसी एवं पार्टी यूनिटी के आन्दोलनों के बारे में सीआरसी ने कभी चर्चा नहीं की। दुर्भाग्य से पीपुल्सवार के प्रति सीआरसी का रवैया काफी नकारात्मक है। वह पार्टी राज्य दमन का प्रधान लक्ष्य बन गया है। क्या हमें उसके व्यवहार से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक विषयों से सीखने की जरूरत नहीं है?', इस तरह का व्यापक दृष्टिकोण एवं भिन्नमत वालों से भी सीखने का सही माओवादी रवैया नई पीढ़ी के कम्युनिस्टों के लिए बढ़िया उदाहरण बना रहेगा।

कॉमरेड रऊफ ने इस विश्वास व आकांक्षा के साथ काम किया था कि भारत देश में कभी न कभी एक सही माओवादी लाइन के इर्द–गिर्द सभी क्रांतिकारी एकताबद्ध होंगे। आन्दोलन के कई उतार–चढ़ावों, शोषक–शासक वर्गों के सरकारी दमन की परवाह किये बगैर क्रांति के प्रति अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय व संकल्प के साथ कॉमरेड रऊफ आखिरी सांस तक एक क्रांतिकारी नेता के रूप में डटे रहे। दीर्घकालीन लोक युद्ध के जरिए भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने वे अनवरत प्रयास करते रहे। अपने द्वारा निर्मित पार्टी को माओवादी क्रांतिकारी लाइन के साथ एकताबद्ध करके देश में कार्यरत सही क्रांतिकारियों की एकता को साकार करने के प्रयास में ही वे शहीद हुए। 'नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता' नारे को उन्होंने सार्थक बनाया।

कॉमरेड रऊफ पांच दशक से भी ज्यादा के अपने क्रांतिकारी जीवन में 12 साल जेलों में बिताये। कॉमरेड रऊफ की जीवनशैली, 'सादा जीवन कठोर श्रम' वाली थी। वे जनता के साथ घुलमिल जाते थे। युवाओं के साथ वे इस तरह एकताबद्ध हो जाते थे कि उम्र का फर्क आड़े नहीं आती थी। वे आजीवन अविवाहित रहे।

कॉमरेड रऊफ की शहादत को ऊंचा उठाते हुए, 'प्रभात' उनकी मौत के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। उनके परिवारजनों के दुख में शामिल होता है। नवजनवादी समाज, समाजवाद–साम्यवाद की स्थापना के लक्ष्य के उनके सपने को साकार करने आखिरी तक संघर्ष करते रहने का इस मौके पर एक बार और शपथ लेता है। ★

नक्सलबाड़ी के लाल पताके को आखिरी सांस तक ऊंचा उठाये रखने वाले भारत की क्रांति के नेता कॉमरेड एसए रऊफ को लाल–लाल सलाम!

भारत की क्रांति के नेता कॉमरेड शेख अब्दुल रऊफ उर्फ विश्वम् की 9 फरवरी, 2014 को 89 वर्ष की उम्र में तीव्र अस्वस्थता के चलते मृत्यु हुई। वे भाकपा (मा–ले) (नक्सलबाड़ी) जिसका हाला ही में भाकपा (माओवादी) के साथ विलय हुआ है, के संस्थापक नेता थे। भाकपा के संशोधनवाद, माकपा के नव संशोधनवाद के खिलाफ सैद्धांतिक संघर्ष करने वालों में कॉमरेड रऊफ भी एक थे।

आन्ध्रप्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के कदिरि तहसील का कूटागुल्ला गांव उनका जन्म स्थल है। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। अपने छात्र जीवन से ही–1950 के दशक से वे भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन का हिस्सा बन गये थे। अंग्रेज साम्राज्यवादी विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष खासकर महान तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का दौर था, वह। तब कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने वाले कॉमरेड रऊफ आजीवन कम्युनिस्ट बने रहे। 'प्रभात' अपने तमाम पाठकों की ओर से उन्हें शीश झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

भाकपा के चुनावी दलदल में उतरने को लेकर हालांकि कॉमरेड रऊफ व्यक्तिगत रूप से मतभेद रखते थे लेकिन पार्टी अनुशासन के तहत वे स्थानीय चुनावों में भाग लिये। इस तरह वे कदिरि शहर का पहला कम्युनिस्ट म्युनिसिपल चेयरमन बने थे। फिर भी ताम–झाम वाले सरकारी कार्यालयों में बैठकर जनता से अलग–थलग होना उन्हें स्वीकार नहीं था। सरकारों की जनविरोधी नीतियों को अमल में लाने वाले राज्य यंत्र के अंग–स्थानीय संस्थाओं में उन्हें एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने के तमाम प्रयासों का उन्होंने दृढ़ता से सामना किया।

भाकपा के नेतृत्व के संशोधनवाद के खिलाफ आंतरिक संघर्ष में कॉमरेड रऊफ ने सक्रिय भागीदारी निभायी। इस आंतरिक संघर्ष के फलस्वरूप जब माकपा का गठन हुआ, तब वे तुरंत उसमें शामिल हो गये थे। लेकिन वे बहुत जल्द ही माकपा के नव संशोधनवाद से अवगत हो गये थे। माकपा के इस नव संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करके, नक्सलबाड़ी के उभार का मजबूती से समर्थन करके, यह कहते हुए कि नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता, आन्ध्रप्रदेश में क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों में से कॉमरेड रऊफ एक थे। तब तक वकालत करते हुए खुली क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त कॉमरेड रऊफ अपना पेशा छोड़कर भूमिगत हो गये थे। पहले वे कामरेड चारू मजुमदार के नेतृत्व में 1968 में गठित एआईसीसीसीआर में शामिल होकर आन्ध्रप्रदेश राज्य समन्वय इकाई के राज्य कमेटी सदस्य बने थे। कॉमरेड सीएम के नेतृत्व में गुत्तिकोंडाबिलम में आयोजित आन्ध्रप्रदेश के नेतृत्वकारी प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होकर आन्ध्रप्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी का सदस्य चुने गये थे। बाद में 22 अप्रैल, 1969 को स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) में शुरू से ही रहे। नागिरेड्डी, देवुलापल्ली, पुल्ला रेड्डी की दक्षिण पंथी अवसरवादी व संशोधनवादी लाइनों के खिलाफ सैद्धांतिक व राजनीतिक संघर्ष को संचालित करने वाले प्रमुखों में कॉमरेड रऊफ भी एक थे। मई, 1970 में आन्ध्रप्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न भाकपा (मा–ले) के पहले राज्य अधिवेशन में वे राज्य कमेटी सदस्य चुने गये थे। 1972 में जब पार्टी में विभाजन हुआ था, तब सीओसी, सीपीआई (एमएल) के पक्ष में रहकर वे आन्ध्रप्रदेश प्रोविन्शियल कमेटी (राज्य कमेटी) सदस्य बने रहे। वे 1973 में बंगाल में गिरफ्तार हुए थे। 1977 में आन्ध्रप्रदेश प्रोविन्शियल कमेटी ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप कार्यनीति तय करते हुए अगस्त प्रस्ताव पारित किया था। कॉमरेड रऊफ उस प्रस्ताव का विरोध करके पार्टी से बाहर चले गये थे। आन्ध्रप्रदेश प्रोविन्शियल कमेटी विशेषकर रायल सीमा के कॉमरेडों ने कॉमरेड रऊफ से अपील की थी कि वे पार्टी में कार्यनीति संबंधित अपने राय को बहस के लिए रखें और दो लाइनों के बीच आंतरिक संघर्ष चलावें। वे नहीं माने और पार्टी छोड़कर चले गये। आन्ध्रप्रदेश राज्य में अलग से एक और क्रांतिकारी पार्टी–भाकपा (मा–ले) आंध्रप्रदेश री–ऑर्गानाइजिंग कमेटी (एपीआरओसी) का उन्होंने गठन किया। इससे पार्टी में विभाजन हुआ। 1979 में वे सीपीआई (एमएल) की केरल राज्य कमेटी के साथ मिलकर सीपीआई (एमएल) री–ऑर्गनाइजिंग कमेटी (सीआरसी) की स्थापना में भागीदार बने थे। 1981 में आयोजित कांग्रेस में वह अपना नाम (सीपीआई) सेंट्रल री–ऑर्गनाइजिंग कमेटी में तब्दील किया। वे उसमें सीआरसी सदस्य थे। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन (रिम) की तीन संस्थापक सदस्य पार्टियों में से सीआरसी एक थी। बाकी दो संस्थापक पार्टियां हैं–पेरू कम्युनिस्ट पार्टी एवं रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी (अमेरिका)। हालांकि सीआरसी ने 1980 के दशक में

(शेष पेज 51 में...)